



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222144  
CG-DL-E-30092020-222144

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]  
No. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं. एडीडी-एसएसआर 03/2019

**विषय :** कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एसीटोन” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

**फा.सं.07/09/2019-डीजीटीआर.**—डीजीटीआर: समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और उसका समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (इसके पश्चात ‘पाटनरोधी नियमावली’ के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में;

## मामले की पृष्ठभूमि

1. एसीटोन के संबंध में मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा रूस और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एसीटोन” के आयातों के संबंध में पाटन की प्रकृति और सीमा तथा घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक

मानदंडों के कार्य-निष्पादन पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए की गई थी। जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद “एसीटोन” (इसके पश्चात् “संबद्ध वस्तु” अथवा पीयूसी के रूप में भी संदर्भित) थी। प्राधिकारी ने रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में इस जांच को दिनांक 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 14/13/2006 के माध्यम से समाप्त कर दिया। उसके बाद, प्राधिकारी द्वारा कोरिया गणराज्य से आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 14/13/2006-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 10 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 75/2008-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था। एक समीक्षा जांच की गई थी और प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से आयातों पर शुल्क को लगातार लगाए रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 18 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 05/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार किया और उसमें दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 07/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था, मौजूदा शुल्क 14 अक्तूबर, 2020 तक वैध है।

2. ताईवान और सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जिसे दिनांक 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 13/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था और उसमें दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 07/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था, को लगाए रखने की सिफारिश करते हुए दिनांक 22 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 14/16/2012-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, मौजूदा शुल्क 14 अक्तूबर, 2020 तक वैध है।
3. इस अधिनियम की धारा 9क(5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के लगाए जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
4. उक्त शुल्कों के समाप्त होने के पूर्व, एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्गेनिक्स लि. और दीपक फेनोलिक्स लि., जो घरेलू उद्योग हैं (इसके पश्चात् “आवेदक” के रूप में संदर्भित) ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “एसीटोन” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत् प्रमाणित आवेदन दायर किया है।
5. प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताईवान से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच करने के लिए आवेदन पर विचार किया और इस तथ्य की जांच करने के लिए कि कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताईवान (इसके पश्चात् “संबद्ध देश” के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर उक्त शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, दिनांक 7.8.2019 की सार्वजनिक नोटिस सं. 7/09/2019-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।

6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में दिनांक 9 मई, 2008 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/13/2006-डीजीएडी और दिनांक 22 जनवरी, 2015 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/16/2012-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

#### क. प्रक्रिया

7. यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन जांच के संबंध में किया गया है:
- i. प्राधिकारी ने संबद्ध निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 7.8.2019 को अधिसूचना सूचना जारी की।
  - ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। इस आवेदन की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां भी अनुरोध किया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
  - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार नोटिस की एक प्रति भी अग्रेषित की और उनसे यह अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के जारी होने के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:
    - क) कुम्हो पी एंड बी केमिकल इंक
    - ख) एलजी केम., लि.
    - ग) कोविन ग्लोबल कं. लि.
    - घ) हुमादे कार्पोरेशन
    - ङ) जिसान केमिकल कं. लि.
    - च) ओसीआई कार्पोरेशन
    - छ) सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल कंपनी
    - ज) रबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी
    - झ) चांग चुन प्लास्टिक कं., लि.
    - ञ) ताइवान प्रोसपेरिटी केमिकल कार्पोरेशन
    - ट) ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कार्पोरेशन
    - ठ) फॉर्मोसा केमिकल्स एंड फाइबर कार्पोरेशन
  - iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबंधित देश के उत्पादकों/निर्यातकों के साथ प्रश्नावली की एक प्रति उत्पादकों के नाम और पते के साथ संबंधित दूतावास को भेजी गई थी।
  - v. इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि 14.10.2019 तक बढ़ाया।

- vi. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर प्रत्युत्तर दिया है:
- क) हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर प्रा. लि.
  - ख) फॉर्मोसा केमिकल्स एंड फाइबर कार्पोरेशन (एफसीएफसी)
  - ग) ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कार्पोरेशन (टीपीसीसी)
  - घ) एलजी केम लि.
  - ङ) सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि.
  - च) विनमार इंटरनेशनल लिमिटेड
  - छ) कुमहो पी एंड बी केमिकल्स
  - ज) हुमादे कार्पोरेशन
  - झ) यूनिड ग्लोबल कार्पोरेशन
  - ञ) सैमसंग सी एंड सीएंडटी कार्पोरेशन
  - ट) आईएमएस कार्पोरेशन
  - ठ) कैनको मार्केटिंग इंडिया.
  - ड) सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (एसएबीआईसी)
  - ढ) सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी (सऊदी कायन)
  - ण) सऊदी एशिया पैसिफिक लि.
  - त) रबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (पैट्रो रबिघ)
- vii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावली भेजी:
- क) मै. सी.जे.शाह एंड कंपनी
  - ख) मै. पीसीएल ऑयल इंडस्ट्रीज
  - ग) मै. कांतिलाल मनिलाल एंड कं. प्रा. लि.
  - घ) मै. सोनकमल इंटरप्राइजेज
  - ङ) मै. खेतान ब्रादर्स
  - च) मै. शुभम डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड
  - छ) मै. एक्रान इंटरप्राइजेज
  - ज) मै. नाइकनवारे केमिकल्स लिमिटेड
  - झ) मै. पारस डाइज एंड केमिकल्स
  - ञ) मै. टोरेट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
  - ट) मै. यूनाइटेड फास्फोरस लि.
  - ठ) मै. रेजिन एंड प्लास्टिक लि.

- ड) मै. कैलाश पोलिमर्स
  - ढ) मै. सेन्ट्रम मेटालिक्स प्रा. लि.
  - ण) मै. वंडर लेमिनेट्स प्रा. लि.
  - त) मै. मेघदेव इंटरप्राइजेज
  - थ) मै. हाई पोलिमर्स लैब्स लि.
  - द) मै. रेनबो कलर्स ऐंड केमिकल्स
  - ध) मै. हर्देश कुमार ऐंड कं.
  - न) मै. ब्लीच मार्केटिंग प्रा. लि.
  - त) मै. कारमेन इंटरनेशनल (प्रा.) लि.
  - प) मै. कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लि.
  - फ) मै. एनजीपी इंडस्ट्रीज लि.
  - ब) मै. फार्मसन फार्मास्युटिकल गुजरात लि.
  - भ) मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लि.
  - म) मै. सिंह प्लास्टिसीजर्स ऐंड रेजिन (इंडिया) प्रा.
  - य) मै. नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लि.
  - र) मै. कुंदन राइस मिल्स लि.
- viii. आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं में से किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ix. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) आवश्यक सूचना की मांग करते हुए तथा परिचालन के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को आयातक की प्रश्नावली भेजी:
- क) एसोचेम
  - ख) एफआईआईओ
  - ग) सीआईआई
  - घ) फिक्की
- x. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- xi. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से (डीजीसीआईएंडएस) क्षति की अवधि तथा इसके पूर्व की अवधि और उसके साथ ही जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेनवार ब्यौरा उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना तथा लेन-देन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण की जांच के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी ने प्रस्तुत किए गए उत्तरों को संभव सीमा तक विधि मान्य बनाने के लिए उल्लिखित निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा के परस्पर संबंध होने के लिए जांच की अवधि के वास्ते डीजी-प्रणाली से आंकड़े भी प्राप्त किए।

- xii. इसके अतिरिक्त, पी ओ आई पश्चात की अवधि, विशेष रूप से महामारी की अवधि, के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और कीमत के संबंध में किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने बाद में डीजीसीआई एंड एस से आंकड़े प्राप्त किए हैं।
- xiii. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा इस नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आदर्शतम लागत और उसका निर्माण करने और बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiv. इस नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 29-10-2019 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया। उसके उपरान्त, नई मौखिक सुनवाई निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण दिनांक 6-12-2019 और 3-7-2020 को आयोजित की गई थी जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध को प्राप्त करें और उसके बाद उन्हें लिखित प्रति उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया था।
- xv. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का मौके पर सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उसे संगत माना गया था।
- xvi. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 .4.2018 से 31-3-2019 ( 12महीने) है। क्षति और संभावना के विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2015- मार्च 2016, अप्रैल 2016-मार्च-2017, अप्रैल 2017-मार्च, 2018 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल की गई थी। पी ओ आई और पी ओ आई - पश्चात (6 महीने) की अवधि शामिल है। पी ओ आई - पश्चात की उक्त अवधि के बाद भी संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत प्रवृत्तियों की, कोविड महामारी के कारण उभरती हुई परिस्थितियों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए जांच की गई है।
- xvii. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों को जहां कहीं भी संगत पाया गया, इस प्रकट न विवरण में प्राधिकारी द्वारा समाधान किया गया है।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई गई या इस जांच में काफी सीमा तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया है।

- xx. एक प्रकटन विवरण दिनांक 24.7.2020 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य, प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 28.7.2020 तक समय देना निहित था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन प्रस्ताव टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- xxi. इस अंतिम जांच परिणाम में “\*\*\*\*” गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से मांगी गई सूचना का द्योतक है।
- xxii जांच की अवधि (1.4.2018 से 31.3.2019 तक) के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा  $70.82 = 1$  यूएस डॉलर के रूप में लिया गया है और जांच की अवधि की बाद की अवधि (1.4.2019 से 30.9.2019 तक) के लिए 69.15 प्रति यूएस डॉलर के रूप में लिया गया है।

## ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

### ख.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

8. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद वही जो पूर्व की जांचों में था।
  - विचाराधीन उत्पाद एक आर्गेनिक रसायन उत्पाद है जिसे डिमिथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है और जिसका उपयोग भारी मात्रा में दवा, कृषि संबंधी रसायन पदार्थ, डाई स्टाफ, कुछ विस्फोटक सामग्री तथा डाउनस्ट्रीम रासायनिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
  - चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वहीं रहता है जिसे पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया है। कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस अवधि के दौरान नहीं हुई है। इस कारण से घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व की जांच और संदर्भ लेता है और उस पर विश्वास करता है।

### ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

9. किसी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

### ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “एसीटोन” (इसके पश्चात “संबद्ध वस्तु” के रूप में भी संदर्भित) है। संबद्ध उत्पाद एक आर्गेनिक रासायनिक पदार्थ है जिसे डिमिथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग भारी मात्रा में दवाओं, कृषि संबंधी रासायनिक पदार्थों, डाई स्टाफ, कुछ विस्फोटक पदार्थों और डाउनस्ट्रीम रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है।
11. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 29 और आगे 29141100 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि यह वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जबकि अलग-अलग आईटीसीएचएस उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बताया जा सकता है, उत्पाद वर्णन का आईटीसीएचएस पर प्राथमिकता रहती है क्योंकि वह सांकेतिक है।
12. वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के कारण, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल और बाद की समीक्षा जांच में था। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने समीक्षा के क्षेत्र में संशोधन (कटौती सहित) का अनुरोध करते हुए कोई परिमाण संबंधी अनुरोध नहीं किया है।

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश्य हैं। पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादन की गई वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्माण किए गए विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम उपयोगों कोई अंतर नहीं है। इन दोनों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किया जा सकता है और इस कारण से उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए।
14. समान वस्तु के संबंध में, इस नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है:  
*“समान वस्तु” का आशय उस वस्तु से है जो भारत में आयात किए जाने के लिए जांच के अधीन वस्तु के सभी अर्थों में सदृश्य अथवा एक जैसे हों अथवा इस प्रकार की वस्तु के न होने पर, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी अर्थों में समान नहीं हो, में जांच के अधीन वस्तुओं के बिल्कुल एक जैसी विशेषताएं हों*
15. रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार से, प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक/घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु विचाराधीन उत्पाद जिसका आयात संबद्ध देश से इस नियमावली के अनुसार किया जाता है, की समान वस्तु है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।
16. यह एकल श्रेणी में उत्पादन किया गया मौलिक आर्गेनिक रासायनिक पदार्थ है। यह एक रंग रहित तरल पदार्थ है जिसमें सहमत होने योग्य इथर जैसी दुर्गंध होती है। इसका उपयोग या तो साल्वेंट के रूप में अथवा एक मध्यवर्ती के रूप में अनेक आर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है। इसका उपयोग भारी मात्रा में दवाओं, कृषि संबंधी रासायनिक पदार्थों, डाइ स्टफ, कुछ विस्फोटक पदार्थों और डाउनस्ट्रीम रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। एसीटोन का विशिष्ट रूप से उपयोग आइसोफोरोन, डाइसीटोन, एल्कोहल, मिथाइल मेथाक्राइलेट और बिसफिनोल ए के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग रबड़ रासायनिक पदार्थों अथवा ओक्सी एसीथीलीन सेलुलोज एसीटेट के निर्माण में किया जाता है।
17. इसलिए, प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान पुनरीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र वही बना हुआ है जैसाकि मूल जांच में था।

## ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

### ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा का दृष्टिकोण

18. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- निर्णायक समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमिटेड (एसआईजी), मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एसओसीएल) और मै. दीपक फिनोलिक्स लि.(डीपीएल) द्वारा किया गया है जो भारतीय उत्पादन का सौ प्रतिशत है।
  - रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है यद्यपि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है।
  - कानून में ऐसी कोई कानूनी रोक नहीं है कि कंपनी जिसमें केवल छह महीने के लिए अपना उत्पादन शुरू किया है, इस तथ्य के बावजूद कि इसे क्षति हो रही है, पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता है।



- iv. एसआईजी द्वारा किए गए आयातों की मात्रा बहुत कम हुई थी और वह अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत था।
- v. निर्दिष्ट प्राधिकारी के एसीटोन और फिनोल के मामले में अन्तिम 22 जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में तब नहीं माना है जब उन्होंने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।
- vi. मै. दीपक फिनोलिक्स लि. ने इसके द्वारा संबंधित उत्पाद का निर्माण शुरू किए जाने के पूर्व संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की बहुत कम मात्रा में आयात किया है।
- vii. मै. दीपक फिनोलिक्स द्वारा आयात बीज की बिक्री करने के उद्देश्य से किया गया था, जैसे ही कंपनी ने इस उत्पाद का निर्माण करना शुरू किया, इस कंपनी ने आयात रोक दिया है।

## ग 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

19. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रमुख उत्पादकों में से दो उत्पादकों (अर्थात् दीपक फिनोलिक्स और एसआई ग्रुप) ने विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में उत्पाद किया है और यदि डीजीटीआर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में इन उत्पादकों को शामिल करने के लिए अपने निर्णय को लागू करता है तब उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया आयात जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों का लगभग 5-15 प्रतिशत है और उसे "बहुत कम" के रूप में नहीं माना गया है। आयातों में सऊदी अरब का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है और उसे बहुत अधिक नहीं माना जाना चाहिए।
- iii. एसआई ग्रुप इन आयातों के लिए कोई तर्कसंगत कारण दिए बिना अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात करता रहा है।
- iv. मै. दीपक फिनोलिक्स द्वारा आयातों के वास्ते तर्क अर्थहीन है क्योंकि एसीटोन एक स्थापित उत्पाद है और इसे बीज के विपणन की आवश्यकता नहीं होती है। मै. दीपक फिनोलिक्स बाजार में किसी अन्य व्यापारी की तरह कार्य करता है।
- v. मै. एसआई ग्रुप फाइनेंसिएल के अनुसार कोरिया में एक संबंधित पक्षकार है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।
- vi. एचओसीएल एक रुग्ण इकाई है और यह पुनर्गठन की प्रक्रिया के अधीन है। इसे इस जांच के उद्देश्य से अर्थक्षम घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है।
- vii. भारत में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से घरेलू उद्योग होने के लिए कोई अर्थक्षम घरेलू उत्पादक नहीं है। ऐसे आधारों पर, वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- viii. नियम 2(ख) की व्याख्या करते हुए डीजीटीआर मैनुअल के पैरा सं. 4.9.20 के अनुसार, घरेलू उत्पादक जो संबद्ध वस्तुओं का आयात करते हैं तब तक घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए "अपात्र" हैं जब तक माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे की सूचना के लिए इस जांच के समग्र हित में इसे उपयुक्त मानते हैं।
- ix. यदि प्राधिकारी इस जांच को जारी रखने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तब घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को इस जांच में विश्लेषण के उद्देश्य से कुल संबद्ध आयातों से अवश्य बाहर किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि दीपक फिनोलिक्स और एसआई ग्रुप दोनों को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में अवश्य ही नहीं माना जाना चाहिए और इस कारण से समीक्षा जांच को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

**ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

20. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. लि., मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. और मै. दीप फिनोलिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था। इन आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत उत्पादन है।
21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये आवेदक संबद्ध देशों में उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद का एक निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयातक से संबंधित (या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं हैं। आवेदक कंपनियों में से दो कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूओएम	एसआई ग्रुप	दीपक फेनोलिक्स
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	350	1,997
कंपनी के उत्पादन की तुलना में आयात	%	1.70	11.91
भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात	%	0.41	3.55
भारत को किए गए कुल आयात की तुलना में आयात	%	0.30	6.88
मांग की तुलना में आयात	%	0.18	1.25

22. दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, हालांकि वे शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत हैं और उसके साथ ही नए संयंत्र के पूर्ण रूप से चालू होने के पहले बीज की बिक्री के उद्देश्य से हैं। प्राधिकारी ने प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों की प्रतिक्रिया में बाद में इस मामले पर भी विचार किया है।
23. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी धारित करते हैं कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का “एक प्रमुख हिस्सा” है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) की शर्तों में ‘घरेलू उद्योग’ (डी आई) के रूप में स्थापित है।

**घ. गोपनीयता****घ.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

24. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता संबंधी दावे के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:
- यह याचिका व्यापार नोटिस सं. 1/2013 के अनुपालन में हैं। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने कोई उदाहरण नहीं दिया है जिसमें घरेलू उद्योग ने लागत प्रपत्र ए-एल को छोड़कर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार की लागत से संबंधित सूचना गोपनीय प्रकृति की है और यह सारांश किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
  - हितबद्ध पक्षकारों ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
  - इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के अगोपनीय पाठ में कोई सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- iv. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अत्यधिक गोपनीयता के दावों और व्यापार नोटिस का उल्लंघन किए जाने पर निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों को अस्वीकार कर दें।

## घ2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- i. उत्पादकों/निर्यातकों ने यह अनुरोध किया कि याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और एक अपूर्ण याचिका दायर की है। इस आवेदन के खण्ड-VI (लागत संबंधी सूचना) के उत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने इस याचिका के भाग VI “ए से एल” तक लागत संबंधी प्रपत्र अनुबंध 5.6 के रूप में संलग्न हैं” में उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। हालांकि अनुबंध 5.6 के संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ii. नियम 11 में सूचीबद्ध मानदंड जैसे इकाई कीमत, कुल लागत, निवेश, रोजगार और भंडार के बारे में सूचना इस याचिका में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है और न ही इन बयानों में इसका विश्लेषण किया गया है और इस प्रकार से इसमें सार्थक विश्लेषण का अभाव है।
- iii. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं कराया है कि क्यों गोपनीयता का दावा किया गया था और क्यों कुछ सूचना के लिए सारांश संभव नहीं था। याचिकाकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे अपने दावे के लिए औचित्य दर्शाएं लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने इस आवेदनक के अंतर्गत यथा अपेक्षित पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- iv. याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। मूल सूचना जैसे अलग-अलग बिक्री, क्षमता, खरीद, बिक्री और लेखांकन नीति के बारे में गोपनीय होने का दावा किया गया है। डीपीएल की पूर्ण परियोजना रिपोर्ट के संबंध में भी गोपनीयता का दावा किया गया है।
- v. खण्ड VI में लागत संबंधी सूचना अनुक्रमित के रूप में नहीं दी गई है।
- vi. वार्षिक रिपोर्टों में उत्पादन मात्राएं दी गई हैं हालांकि उसके संबंध में दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 में सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में सूचना के प्रकटन के लिए अधिदेश के विरुद्ध गोपनीयता का दावा किया गया है।
- vii. इसके अलावा, जहां तक गोपनीयता का प्रश्न है, उत्पादकों/निर्यातकों ने व्यापार नोटिसों और समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सूचना उपलब्ध कराई हैं जबकि इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने अपने आप को दायर की गई याचिका के संबंध में गोपनीयता के मानदंडों को पूरा नहीं किया है। याचिका के अगोपनीय पाठ में महानिदेशक द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुसार अगोपनीयता की अपेक्षा का उल्लंघन हुआ है।
- viii. इस याचिका के “कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताईवान से एसीटोन के आयातों के मामले में व्यापार नोटिस स्थिति-निर्णायक समीक्षा जांच” भाग में, याचिकाकर्ताओं ने व्यापार नोटिस से “दो से अधिक उत्पादक” मानक के बजाय एकल उत्पादक/दो उत्पादक मानदंड पर विचार किया है।
- ix. व्यापार नोटिस के अनुसार जहां अनेक उत्पादक याचिकाकर्ताओं के रूप में हों, तब इस याचिका में कुछ आंकड़ों को सकल योग के रूप में जोड़े जाने और वास्तविक आंकड़ों में दिए जाने की आवश्यकता है परंतु वर्तमान याचिका में उसे अनुक्रमित रूप में दिया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने इस आवेदन के अंतर्गत यथा-अपेक्षित पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और वे दावा कर रहे हैं कि हमने प्रस्तुत की गई अपनी प्रश्नावली में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

- x. निम्नलिखित मानदंडों में, घरेलू उद्योग निर्धारित रूप में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया है:
- क. बिक्री की मात्रा
  - ख. प्रति इकाई बिक्री की लागत-निर्यात
  - ग. प्रति इकाई पीबीआईटी - घरेलू बिक्री
  - घ. कुल पीबीआईटी - घरेलू बिक्री
  - ड. एनआईपी की गणना

### घ3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की उस सीमा तक जांच और समाधान किया गया है जिस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा उसे संगत माना गया है और उसका विवरण नीचे दिया गया है।
27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, इस नियमावली के नियम 7 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है:

*गोपनीय सूचना* : (1) नियम उपनियमों के 6(2), (3) और (7) उपनियम के 12 नियम, (2) के 15 नियम, उपनियम (4) और नियम उपनियम के 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 उपनियम के (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों और क्षति के मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील सूचना को कार्यपद्धति के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी भी सूचना जो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीयता के रूप में नहीं माना जा सकता।

### ड. विविध अनुरोध

#### ड.1 घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण

29. निम्नलिखित विविध अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं:

- i. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में विरोधाभासी सूचना प्रस्तुत की है।
- ii. संबद्ध देशों से निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा अपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया गया है।
- iii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपूर्ण और विरोधाभासी सूचना के आधारों पर निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर अस्वीकार कर दें।
- iv. यह जांच बड़े हुए आयातों के विरुद्ध नहीं है बल्कि बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। बीआईएस लाइसेंस इस प्रकार के परिदृश्य में संगत नहीं है।
- v. बढ़ी हुई मांग और कोविड-19 की स्थिति के कारण उच्च कीमत निर्धारण अस्थायी है और निर्णय अस्थायी स्थिति के आधार पर नहीं लिया जा सकता।

## ड2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना उचित नहीं होगा और यह डाउनस्ट्रीम उद्योगों के समग्र हितों के विरुद्ध होगा।
- ii. याचिकाकर्ताओं के दावों के विपरीत, निर्णायक समीक्षा की शुरुआत विधिवत् प्रमाणित अनुरोध पर भी आवश्यक नहीं है, जैसाकि केसोराम रेयन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मान्य ठहराया गया।
- iii. इस आवेदन को विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है और उसे “क्षति के न होने” के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी क्षति को सिद्ध नहीं किया गया है और सऊदी अरब के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटन के न होने” के रूप में मान लिया गया है।
- iv. अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत किए गए किसी भी आयातों को पाटन और/अथवा क्षति के आंकलन और निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- v. शुल्क के समाप्त होने का प्रभाव केवल भुगतान किए गए आयातों के शुल्क पर होगा क्योंकि सबसे पहले अग्रिम लाइसेंस आयातों का विश्लेषण करने का प्रश्न नहीं उठता है।
- vi. इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि गैर प्रशुल्क अवरोधों को बिल्कुल निकट समय में शुरू करने (बीआईएस) के फलस्वरूप आयातों की मात्रा में कमी आएगी।
- vii. एसीटोन के आयातों का अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन आसन्न है और इसके कारण भारत में उत्पादों के निर्यातों के लिए प्रवेश की सुविधा समाप्त हो जाएगी।
- viii. लागतों का आबंटन एसीटोन और फिनोल की अलग-अलग उत्पादन अनुपात और मूल्य के कारण कारोबार अनुपात के आधार पर और न कि उत्पादन की मात्रा के अनुपात पर किया जाना चाहिए।
- ix. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस पाटन, क्षति और संभावना के आधार पर मौन है और इसकारण से नियम 6(6) के कारण कानून में सही नहीं है।
- x. इस जांच को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस कानूनी दृष्टि से सही नहीं है।
- xi. यह आवेदन व्यापार नोटिस सं. 02/2017 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं है क्योंकि इसे बिना किसी औचित्य के 270 दिनों की समय सीमा के समाप्त होने के बाद दायर किया गया था।

- xii. मिश्रित समीक्षा प्राधिकारी की समय सीमाओं के बारे में गतिरोध पैदा करने के वास्ते भी प्रस्तुत किया गया है।
- xiii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6, जो आवश्यक परिवर्तनों के साथ समीक्षा जांच पर लागू होती है, के अनुसार, उत्पादक यह अनुरोध करते हैं कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे किसी जांच की शुरुआत तब तक करें जब तक यह विधिवत् प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया यह निर्धारण न करे कि समीक्षा जांच की शुरुआत किया जाना अपेक्षित है जो याचिकाकर्ता कर पाने में सफल नहीं हैं।
- xiv. 2020 के दौरान जांच की अवधि के बाद की अवधि में, मांग में वृद्धि के संबंध में अनेक घटनाक्रम भारत तथा वैश्विक बाजार दोनों में एसीटोन आधारित आइसो-प्रोपील एल्कोहल (आईपीए) के निर्माण के लिए कोविड-19 महामारी के कारण हुई है, इसके अलावा मांग में वृद्धि आवश्यक है और इसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। घरेलू उद्योग बढ़ी हुई मांग आपूर्ति के अंतर को पूरा नहीं कर सकता है।

### **ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

- 31. घरेलू उद्योग द्वारा उनके द्वारा दायर किए गए आवेदन में उपलब्ध कराई गई अपर्याप्त सूचना के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस आवेदन में जांच की शुरुआत के उद्देश्य से सभी संगत सूचना दी गई थी। प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य वाले आवेदन के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, जांच की शुरुआत के बाद, आवेदक से उस सीमा तक सूचना मांगी गई है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया और वह वर्तमान जांच परिणामों के उद्देश्य से आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि साक्ष्य गुणवत्ता और मात्रा में जांच के आगे बढ़ने के साथ सुधार होता है।
- 32. इस तर्क के बारे में कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों को कुल आयातों से बाहर किया जाना चाहिए, की जांच की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों/निर्यातों पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि इसने घरेलू उद्योग अथवा घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव नहीं डाला है। अग्रिम लाइसेंस/अधिकरण धारक के पास यह विकल्प होता है कि या तो वे शुल्क मुक्त आधार पर इनपुट्स का आयात करें अथवा अग्रिम रिलीज आदेश के तंत्र का उपयोग करते हुए स्वदेशी स्रोतों से उसकी खरीद करें। क्षति के विश्लेषण का उद्देश्य घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना और उस पर कब्जा करना है। इस कारण से यह तर्कसंगत नहीं होगा कि शुल्क मुक्त आयातों को क्षति के विश्लेषण के बाद किया जाए। इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात उस कीमत के लिए बेंच मार्क है जिस पर इन वस्तुओं का आयात करें और शुल्कों के भुगतान के बिना किसी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इस तथ्य पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है। वास्तव में, निर्यातकों और आयातकों को चिंता नहीं करनी चाहिए यदि उनका यह दावा हो कि आयात केवल शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत होता है क्योंकि उस स्थिति में शुल्क लगाए जाने का उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 33. इन तर्कों के संबंध में कि अनिवार्य बीआईएस लाइसेंसिंग को आरंभ किए जाने के कारण, कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित आयातों का समाधान करना है। बीआईएस लाइसेंस के मौजूद रहने के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाने में कोई रोक नहीं है।

### **पाटन का आंकलन – पद्धति और मानदंड**

### **च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

#### **च.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

- 34. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किया:
  - i. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

- ii. संबद्ध देशों के लिए गणना की गई पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- iii. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए लागत के तत्वों का निर्धारण करते समय बेंजीन और प्रोपीलीन की निर्यात कीमत पर विचार करें।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और परिणामी पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों को स्वीकार किया है।
- ii. सामान्य मूल्य की गणना के लिए साक्ष्य न्यूनतम साक्ष्य संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करता है क्योंकि उपलब्ध कराई गई कीमतें उत्तर पूर्व एशिया न कि कोरिया के लिए है।
- iii. जनरल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसे डाई स्टफ मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम भारत सरकार के अनुसार नियम 6 के आशय से सर्वोत्तम सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- iv. सामान्य मूल्य को तय करने के लिए किए गए समायोजन इस नियमावली के अनुबंध-1 के अंतर्गत तर्क संगत नहीं हैं और वे केवल अनुमानों पर आधारित हैं।
- v. निर्यात कीमत के लिए किया गया समायोजन असामान्य रूप से अधिक और प्रमाणिक नहीं किया हुआ है। वेबसाइट से उपलब्ध कराया गया उद्धरण सही नहीं है और इसे अवैध अनुमानों का उपयोग करते हुए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

### च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

#### सामान्य मूल्य की गणना

36. इस अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य निम्नलिखित से है:

- i व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
  - क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
  - ख. परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच की शुरुआत की थी। जांच की शुरुआत के चलन में, प्राधिकारी ने सिंगापुर के आंतरिक लेन-देन के उपलब्ध नहीं रहने के कारण आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के साथ आगे की कार्रवाई की थी। हालांकि इस प्रकटन विवरण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।
38. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगे की कार्रवाई की। जांच की शुरुआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस का उत्तर देने के लिए सलाह दी और उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। निम्नलिखित याचिकाकर्ताओं से उत्तर प्राप्त हुए थे:
- क) हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर प्रा. लि.
  - ख) फॉर्मोसा केमिकल्स एंड फाइबर कार्पोरेशन(एफसीएफसी)
  - ग) ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कार्पोरेशन (टीपीसीसी)
  - घ) एलजी केम लि.
  - ङ) सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि.
  - च) विनमार इंटरनेशनल लिमिटेड
  - छ) कुमहो पी एंड बी केमिकल्स
  - ज) हुमादे कार्पोरेशन
  - झ) यूनिड ग्लोबल कार्पोरेशन
  - ञ) सैमसंग सी एंड सीएंडटी कार्पोरेशन
  - ट) आईएमएस कार्पोरेशन
  - ठ) कैनको मार्केटिंग इंडिया.
  - ड) सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (एसएबीआईसी)
  - ढ) सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल कंपनी (सऊदी कायन)
  - ण) सऊदी एशिया पैसिफिक लि.
  - त) रबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी(पैट्रो रबिघ)
39. चूंकि उपर्युक्त कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, प्राधिकारी ने इन उत्पादकों के लिए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुरोध की जांच की है और जहां भी उपयुक्त पाया गया पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।
40. संबद्ध देश में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग प्राप्त न होने पर, प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
41. तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया है:



**ताईवान के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक****मै. फोरमोसा केमिकल्स ऐंड फाइबर कारपोरेशन (एफसीएफसी – ताईवान)**

42. मै. फोरमोसा केमिकल्स ऐंड फाइबर कारपोरेशन (एफसीएफसी) ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं।
43. एफसीएफसी ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का \*\*\*मी.टन की बिक्री की है और इसने प्रत्यक्ष तौर पर जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्री से संबंधित लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार के जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ प्राप्त करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, सभी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 100 प्रतिशत थी।
44. कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक (एफसीएफसी) की बीजक कीमत से अंतरदेशीय भाड़े और ऋण लागत के आधार पर समायोजनों (यूएस डालर/मी.टन में) पर विचार किया है। तदनुसार कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल कारपोरेशन (टीपीसीसी-ताईवान)**

45. मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल कारपोरेशन ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है।
46. टीपीसीसी ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का \*\*\*मी.टन की बिक्री की है और इसने प्रत्यक्ष तौर पर जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्री से संबंधित लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार के जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ प्राप्त करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, सभी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 100 प्रतिशत थी।
47. कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक (टीपीसीसी) की बीजक कीमत से अंतरदेशीय भाड़े और ऋण लागत के आधार पर समायोजनों (यूएस डालर/मी.टन में) पर विचार किया है। तदनुसार कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना \*\*\* डॉलर/मी.टन के रूप में की और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**साउथ कोरिया के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक****मै. एलजी केम**

48. मै. एलजी केम ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है।
49. एफसीएफसी ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का \*\*\*मी.टन की बिक्री की है और इसने प्रत्यक्ष तौर पर जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू

बिक्री से संबंधित लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार के जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ प्राप्त करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, सभी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 100 प्रतिशत थी।

50. कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक (एलजी केम.) की बीजक कीमत से अंतररेखीय भाड़े और ऋण लागत के आधार पर समायोजनों (यूएस डालर/मी.टन में) पर विचार किया है। तदनुसार कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **मै. कुमहो ऐंड बी केमिकल्स आईएनसी.**

51. मै. कुमहो ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं। इसने घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर विचाराधीन उत्पाद का \*\*\*मी.टन की बिक्री की है और इसने प्रत्यक्ष तौर पर जांच की अवधि के दौरान 5 व्यापारियों के साथ संयुक्त रूप से तथा प्रत्यक्ष तौर पर भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्री से संबंधित लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार के जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ प्राप्त करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हों तब प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, सभी घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्री 100 प्रतिशत थी।
52. कारखानागत सामान्य मूल्य तय करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादक (कुमहो) की बीजक कीमत से अंतररेखीय भाड़े और ऋण लागत के आधार पर समायोजनों (यूएस डालर/मी.टन में) पर विचार किया है। तदनुसार कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **सऊदी अरब के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

##### **मै. सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी**

#### **सऊदी अरब के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

53. मै. सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (एसकेपीसी) ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है। इसने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं की है, हालांकि इसने जांच की अवधि के दौरान अपने संबंधित निर्यातकों मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी), निर्यातक और मै. सेबिक एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (एसएपीपीएल), व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उत्पादक ने अपने गृह देश में कोई घरेलू बिक्री नहीं की है। इस कारण से घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य उपलब्ध नहीं है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत को उचित सत्यापन के बाद स्वीकार किया है और सामान्य मूल्य तय करने के लिए उसमें 5 प्रतिशत लाभ को जोड़ दिया।
54. तदनुसार, कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

##### **मै. रबिघ रिफाइनिंग ऐंड पेट्रोकेमिल कंपनी (पेट्रो रबिघ)**

55. मै. पेट्रो रबिघ ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है। इसने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं की है, हालांकि इसने जांच की अवधि के दौरान अपने संबंधित

व्यापारी मै. सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि. सिंगपुर (सुमिटोमो), निर्यातक के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\*मी.टन निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उत्पादक ने अपने गृह देश में कोई घरेलू बिक्री नहीं की है। इस कारण से घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य उपलब्ध नहीं है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है और प्राधिकारी ने उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत को उचित सत्यापन के बाद स्वीकार किया है और सामान्य मूल्य तय करने के लिए उसमें 5 प्रतिशत लाभ को जोड़ दिया।

56. तदनुसार, कारखानागत सामान्य मूल्य की गणना और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

### **निर्यात कीमत**

#### **ताईवान के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

##### **मै. फोरमोसा केमिकल्स ऐंड फाइबर कारपोरेशन (एफसीएफसी-ताईवान)**

57. मै. फोरमोसा केमिकल्स ऐंड फाइबर कारपोरेशन ने निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं और उसके अलावा जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत की है। एफसीएफसी ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\*यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\*यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। इससे जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन भी निर्यात किया है। उत्पादक ने दस्तावेज तैयार करने संबंधी शुल्कों, नोटरी शुल्कों, व्यापार संवर्धन शुल्कों आदि सहित बंदरगाह सुविधा शुल्क, बंदरगाह के किनारे टैंक रखरखाव शुल्क, बंदरगाह प्रबंधन शुल्क, ऋण लागत, अन्य पोर्ट संबंधी खर्च को शामिल करते हुए पोर्ट के रखरखाव और संबंधित खर्च का दावा किया है जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे तालिका के अध्ययन के पश्चात् स्वीकार किया गया। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएस डॉलर \*\*\*/मी.टन तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि में यूएस डॉलर \*\*\*/ मी.टन के रूप में तय किया गया है।

##### **मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल कारपोरेशन(टीपीसीसी-ताईवान)**

58. मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल कारपोरेशन ने निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं और उसके अलावा जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत की है। टीपीसीसी ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तौर पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\*यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया। इसने तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\*मी.टन भी निर्यात किया है। उत्पादक ने दस्तावेज तैयार करने संबंधी शुल्कों, नोटरी शुल्कों, व्यापार संवर्धन शुल्कों आदि सहित बंदरगाह सुविधा शुल्क, बंदरगाह के किनारे टैंक रखरखाव शुल्क, बंदरगाह प्रबंधन शुल्क, ऋण लागत, अन्य पोर्ट संबंधी खर्च को शामिल करते हुए पोर्ट के रखरखाव और संबंधित खर्च का दावा किया है जिसकी जांच अचानक नमूने लिए गए आधार पर किया गया और उसे प्राधिकारी द्वारा तालिका सत्यापन के दौरान स्वीकार किया गया। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएस डॉलर \*\*\* मी.टन तय की गई है।

#### **साऊथ कोरिया के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

##### **मै. एलजी केम**

59. मै. एलजी केम ने निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं और उसके अलावा जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत की है। इसने जांच की अवधि के दौरान

प्रत्यक्ष तौर पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान शून्य मात्रा का निर्यात किया है। इसने जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन भी निर्यात किया है। उत्पादक ने सर्वेक्षण शुल्क, सीमा शुल्क दलाली शुल्क, बैंक प्रभार और ऋण लागत का दावा किया है जिसे अचानक नमूने लिए गए आधार पर किया गया और उसे प्राधिकारी द्वारा तालिका सत्यापन के दौरान स्वीकार किया गया। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएस डॉलर \*\*\*/मी.टन तय की गई है।

#### **मै. कुमहो पी ऐंड बी केमिकल्स आईएनसी (दक्षिण कोरिया)**

60. मै. कुमहो ने जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावलियां प्रस्तुत की हैं और उसके बाद जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए मांगी गई सूचना भी प्रस्तुत की है। इसने पांच व्यापारियों के माध्यम से कुल \*\*\* मी.टन का निर्यात किया है। उत्पादक ने भारत को प्रत्यक्ष तौर पर विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन तथा जांच की अवधि के दौरान असंबंधित व्यापारियों मै. केन्को मार्केटिंग इंक, मै. हुमाद कारपोरेशन, मै. यूनिड ग्लोबल कोर्ज, मै. सैमसंग सी ऐंड टी कारपोरेशन एवं मै. आईएमएस कारपोरेशन के माध्यम से क्रमशः \*\*\* मी.टन (सीआईएफ \*\*\* यूएस डॉलर), \*\*\* मी.टन (सीआईएफ \*\*\* यूएस डॉलर), \*\*\* मी.टन (सीआईएफ \*\*\* यूएस डॉलर), \*\*\* मी.टन (सीआईएफ \*\*\* यूएस डॉलर), \*\*\* मी.टन (सीआईएफ \*\*\* यूएस डॉलर) और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर मूल्य के बीजक सीआईएफ मूल्य के \*\*\* मी.टन का निर्यात किया है। इसने जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* यूएस डॉलर का सीआईएफ मूल्य के \*\*\* मी.टन और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर मूल्य के बीजक का भी निर्यात किया है।
61. उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, वेयर हाउस का अंतरदेशीय भाड़ा, वेयर हाउस किराया खर्च, पोर्ट तक अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट हैंडलिंग और संबंधित खर्च, ऋण लागत, निरीक्षक का शुल्क, बैंक शुल्क, शुल्क वापसी पैकिंग लागत, व्यापारी के घाटे आदि का दावा किया है जिसकी जांच नमूने लिए गए आधार पर की गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा तालिका के सत्यापन के दौरान स्वीकार किया गया है। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए केआरडब्ल्यू \*\*\* /किग्रा. तय की गई है।

#### **सऊदी अरब के सहयोगी उत्पादक/निर्यात**

##### **मै. सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (एसकेपीसी)**

62. मै. सऊदी कायान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी (एसकेपीसी) ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है और इसके बाद जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए मांगी गई सूचना भी प्रस्तुत की है। इसने अपने संबंधित व्यापारी-निर्यातक मै. सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी) और मै. सेबिक एशिया पैसिफिक प्रा. लि. (एसएपीपीएल) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। उत्पादक ने भारत को \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान भारत को शून्य निर्यात किया गया था। इसने जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* मी.टन मात्रा का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन का निर्यात किया है।
63. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, पोर्ट रखाव और संबंधित खर्च, विपणन शुल्क, डीमेरेज, सीमा शुल्क संबंधी खर्च, बैंक प्रभार आदि का दावा किया है जिसकी जांच नमूने लिए गए आधार पर की गई है और जिसे प्राधिकारी

द्वारा तालिका के सत्यापन के दौरान स्वीकार किया गया है। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएस डॉलर \*\*\* /मी.टन तय की गई है।

### **मै. रबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रो रबिघ)**

64. मै. रबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (पेट्रो रेबिघ) ने केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्रों में निर्यातक की प्रश्नावली प्रस्तुत की है और इसके बाद जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए मांगी गई सूचना भी प्रस्तुत की है। इसने अपने संबंधित व्यापारी-निर्यातक मै. सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि. सिंगापुर (सुमिटोमो) और आगे असंबंधित निर्यातकों अर्थात् मै. विनमर के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान शेष मै. हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर प्रा. लि. ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। इस प्रकार से उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। भारत को जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* मी.टन का निर्यात किया गया था। इसने जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* मी.टन मात्रा का \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य और जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान \*\*\* यूएस डॉलर के एफओबी मूल्य का \*\*\* मी.टन का निर्यात किया है।
65. संबंधित व्यापारी मै. सुमिटोमो ने उठाई गई हानि के साथ-साथ परिवहन लागत, ऋण लागत, अन्य खर्चों का दावा किया है जिसकी जांच नमूने लिए गए आधार पर की गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा तालिका के सत्यापन के दौरान स्वीकार किया गया है। तदनुसार, निर्यातक/उत्पादक के लिए निबल निर्यात कीमत जांच की अवधि के लिए यूएस डॉलर \*\*\*/मी.टन तथा जांच की अवधि की बाद की अवधि के लिए \*\*\* यूएस डॉलर/मी.टन के रूप में तय की गई है।

### **संबद्ध देश से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत**

66. बाद के पैराग्राफों में असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सिफारिश की गई है।

### **पाटन मार्जिन का निर्धारण**

67. सामान्य मूल्य और निबल निर्यात कीमत के आधार पर, प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया:

### **जांच की अवधि**

क्र. स.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/मी. टन)	निबल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
1	ताइवान	मै. फोरमोसा केमिकल्स	***	***	***	***	0-10
2		मै. ताईवान प्रोसपेरिटी	***	***	***	***	0-10
3	कोरिया गणराज्य	मै. कुमहो	***	***	***	***	0-10
4		मै. एलजी. केम.	***	***	***	***	ऋणात्मक
5	सऊदी अरब	मै. सऊदी कायान	***	***	***	***	180-200
6		मै. रबिघ रिफाइनिंग	***	***	***	***	ऋणात्मक

## **क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण**

### **घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण**

68. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि में मै. दीपक फिनोलिक्स द्वारा नई क्षमताओं को बढ़ाने के कारण वृद्धि हुई है।
- iii. नई क्षमताओं को बढ़ाने के कारण आयात में स्वतंत्र रूप में गिरावट आई है। पूर्व में भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर था और इस कारण से आयात आवश्यक नहीं था।
- iv. हाल की अवधि में आयातों में गिरावट पाटन में कमी नहीं है बल्कि देश में नई क्षमताओं के प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा हुआ है।
- v. अनावश्यक आयातों की मात्रा में बहुत अधिक मार्जिन में वृद्धि हुई है।
- vi. वर्तमान आयात के स्तर मांग और आपूर्ति में मामूली अंतर के कारण इस देश में आवश्यक और अपेक्षित आयातों की तुलना में बहुत अधिक है।
- vii. आयात की कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है। इसके अलावा, यह गिरावट बेसिक इनपुट्स की कीमतों में गिरावट के कारण लागतों में गिरावट से बहुत ज्यादा है।
- viii. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।
- ix. बिक्री कीमतें समग्र क्षति की अवधि के दौरान लागत से कम थी। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के भीतर भी कीमत में गंभीर गिरावट का सामना करना शुरू कर दिया।
- x. आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- xi. घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान घाटे में रही है। घरेलू उद्योग भारत में पाटित उत्पादों के मौजूद रहने के कारण लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं था।
- xii. घरेलू उद्योग के पास माल भंडार पूरी अवधि के दौरान पर्याप्त रही है और इसमें जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- xiii. घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। कारणात्मक संबंध पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच मौजूद है।
- xiv. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र समग्र क्रियाकलाप के लिए है और न कि विचाराधीन उत्पाद के घरेलू क्रियाकलापों के लिए है।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण**

69. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, उत्पादन, बाजार हिस्से, प्रतिदिन उत्पादकता, निवेश पर लाभ, पीबीआईटी में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग को आयातों के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ी है। सकारात्मक वृद्धि सभी मानदंडों में देखी जा सकती है।
- ii. संबद्ध देशों से आयातों में 61 प्रतिशत तक गिरावट आई है और ताईवान से आयातों में 85 प्रतिशत तक गिरावट आई है और इस कारण से घरेलू उद्योग पर मात्रा का कोई दबाव नहीं पड़ रहा है।

- iii. घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों से पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है। आयातों से कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iv. कीमत में कटौती को लाभप्रदता की तुलना में देखा जाना है। ताईवान से कीमत में कटौती सकारात्मक है परंतु पीबीआईटी में बहुत तेजी से सुधार आया है।
- v. संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में न्यूनतम है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और वह जांच की अवधि में सबसे अधिक है।
- vi. कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि हुई है जबकि रहस्यमय तरीके से मजदूरी वही रही है। कर्मचारियों की संख्या में क्षति के दौरान 119 से 352 तक वृद्धि हुई है।
- vii. कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को कीमत में कथित कटौती और कीमत न्यूनीकरण के बावजूद लाभ में वृद्धि हो रही है।
- viii. सऊदी अरब का कुल निर्यातों का 3 प्रतिशत से कम निर्यात है जो न्यूनतम आरंभिक सीमा से कम है जिसके कारण इस प्रकार के आयातों का प्रभाव न्यूनतम, यदि कोई हो, होगा।
- ix. बिक्री कीमत में 12 सूचकांकों तक कमी आई है जबकि बिक्री की लागत में 29 सूचकांकों तक गिरावट हुई है और उसके कारण कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
- x. उत्पादन, उपयोगिता, बिक्री मात्रा और लगाई गई पूंजी सभी ने क्षति की अवधि और जांच की अवधि में सकारात्मक रुझान दर्शाया है जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति के न होने को दर्शाता है। क्षमता का उपयोग 89 प्रतिशत मौजूदा मूल्य पर है जो जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक बिंदु है।
- xi. क्षति उच्चतर व्याज और ह्रास लागतों के कारण हुआ है जो केवल दीपक फिनोलिक्स द्वारा संयंत्र (नव स्थापित) के उच्च वित्त और ह्रास मूल्यों के कारण अधिक है।
- xii. मै. दीपक फिनोलिक्स के लिए वास्तविक क्षति के बजाय वास्तविक अवरुद्धता का विश्लेषण होना चाहिए।
- xiii. एक घरेलू उत्पादक (डीपीएल) के आंकड़ों के आधार पर एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III का पूर्ण रूप से उल्लंघन होगा।
- xiv. पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने के बावजूद एचओसीएल को एक रण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 2015-16 तक कोई प्रचालन नहीं था।
- xv. याचिका यह दर्शाती है कि किस प्रकार से कोरिया से आयात नवंबर, 2018 के बाद रुक गए हैं क्योंकि डीपीएल ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। केपीबी से सीधे निर्यात भी पूर्ण रूप से रुक गया है।
- xvi. कोरिया से आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से बहुत अधिक हद तक अर्थात् 39 प्रतिशत तक और जांच की अवधि में 11 प्रतिशत तक कमी आई है, इस कारण से मात्राओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जो मात्रा के प्रभाव को दर्शाता है। डीपीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के बाद, कोरिया से आयात नगण्य है।
- xvii. फिनोल के लिए हाल के रक्षोपाय आवेदन में, सकारात्मक आरओसीआई आंकड़े आवेदकों के लिए 2019-19 में सूचित की गई थी। ये आंकड़े एसीटोन और फिनोल के लिए अलग अलग नहीं हो सकते हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग डीपीएल को लागू किए जाने के पूर्व भी लगातार सुधार कर रहा था और इसलिए सभी सकारात्मक वृद्धि को नवंबर, 2018 में डीपीएल द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने का कारण नहीं माना जा सकता है।

- xix. नकद प्रवाह जांच की अवधि के अलावा हमेशा सकारात्मक रही है जिसे भी नए घटक के प्रति किए गए भारी मात्रा में पूंजी प्रवाह को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- xx. निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर हानि के प्रभाव के विस्तार की जांच करें।
- xxi. फिनोल और एसीटोन का उत्पादन एक साथ किया जाता है और एसीटोन की सभी मांग और आपूर्ति तथा उत्पादन फिनोल से संबंधित है क्योंकि फिनोल पहले से ही प्रमुख उत्पाद है।
- xxii. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग-आपूर्ति में असमानता है और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, इन वस्तुओं का आयात पर्याप्त मात्राओं में किया जाता है।
- xxiii. 2016 में, जापान और थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच की गई लेकिन उसके फलस्वरूप पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं होता है क्योंकि यह एचओसीएल के उत्पादन के पुनरुद्धार में सहायक नहीं होगा।
- xxiv. यह आयात मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर के कारण आवश्यक हो गया है।
- xxv. बाजार सूचना की रिपोर्टों के अनुसार, अलग-अलग देशों से संबद्ध वस्तुओं की मांग में संभवतः 2022 तक 11 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

#### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

- 70. प्राधिकारी द्वारा इसके नीचे किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
- 71. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 कि है प्रावधान यह में में निर्धारण के क्षति“... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटन नियमावली 11 के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
- 72. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान उत्पादों के लिए पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव; और (ख) इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों पर दबाव बनाएगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोकेंगे जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।



73. सीमा प्रशुल्क की धारा 9क(5) के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पूर्व में नहीं हटाया गया तब उसका इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर प्रभाव नहीं रहेगा, बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार किसी समीक्षा में इस मत का हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त होने के फलस्वरूप संभवतः पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, यह समय-समय पर आगे की पांच वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार के अधिरोपण की अवधि का समय-समय पर विस्तार कर सकती है और इस प्रकार की आगे की अवधि ऐसे समय विस्तार के आदेश की तिथि से आरंभ होगी।
74. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे सूचकांकों पर विचार किया है जिसका इस उद्योग की स्थिति अर्थात् उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री प्राप्ति, आकार और पाटन का मार्जिन आदि पर प्रभाव पड़ता हो।
75. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

i. **मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन**

76. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के उद्देश्य से परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग नीचे दी गई है:

मांग	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	25,428	26,041	32,306	83,134	1,44,475
प्रवृत्ति		100	102	127	327	568
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	94,173	56,869	42,257	36,510	15,646
अन्य देशों से आयात जिस पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	मी.टन	24,080	10,167	14,539	35,758	36,776
अन्य देशों से आयात	मी.टन	20,096	68,801	89,811	44,432	38,938
<b>कुल मांग</b>	मी.टन	<b>1,63,778</b>	<b>1,61,879</b>	<b>1,78,912</b>	<b>1,99,834</b>	<b>2,35,835</b>

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. **पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

**आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा**

78. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका में आयात की मात्रा और बाजार हिस्से के संबंध में वास्तविक स्थिति का सारांश दिया गया है:-

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद की अवधि (वार्षिकीकृत)
आयात की मात्रा						
संबद्ध देश	मी.टन	94,173	56,869	42,257	36,510	15,646
अन्य देश जिस पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	मी.टन	24,080	10,167	14,539	35,758	36,776
अन्य देश		20,096	68,801	89,811	44,432	38,938
कुल आयात	मी.टन	1,38,350	1,35,838	1,46,606	1,16,700	91,380
आयातों में बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	%	68.07	41.87	28.82	31.39	17
अन्य देश जिस पर पाटन रोधी शुल्क लगता है	%	17.40	7.48	9.92	30.64	40
अन्य देश	%	14.53	50.65	61.26	38.07	43
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
उत्पादन	%	377	213	129	42	9.94
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	56	34	11	3
भारतीय खपत	%	58	35	24	19	6.32
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	61	41	32	11

79. उपर्युक्त तालिका के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने और बाजार में नई क्षमताओं के कारण गिरावट आई है।

i. **घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव**

क. **कीमत में कटौती**

80. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक कीमतों में ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुआ होता। इस संबंध

में, उत्पाद का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जिसमें व्यापार के समान स्तर पर सभी छूट और करों की निबल राशि शामिल है, के बीच तुलना की गई है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। जांच की अवधि के लिए सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	सऊदी अरब	ताईवान	कोरिया गणराज्य
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***
कीमत में कटौती	%	10-15	5-10	0-5

81. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निबल कीमत से कम है। संबद्ध देशों से इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती हो रही है।

#### ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

82. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा उसमें ह्रास हो रहा है तथा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पश्च - पीओआई (ए)
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	101	64	58
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	115	88	71
पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	43,133	46,215	53,157	49,987	32,246
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	123	116	75

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों का न तो ह्रास करती है और न ही न्यूनीकरण करती है। तथापि जाँच के बाद की अवधि में आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रही हैं।

#### ii. घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मानदंड

84. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि नुकसान के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की निष्पक्ष जाँच होगी। पाटनरोधी नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभों, परिणाम, बाजार की हिस्सेदारी, उत्पादकता,

निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों और सूचकांकों का एक वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

85. तदनुसार यहाँ नीचे घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण किया गया है:

**क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा**

86. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता का उपयोग निम्नानुसार रहा:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई-पश्चात (ए)
संस्थापित क्षमता	एमटी	47,140	47,140	47,140	97,140	1,67,140
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	206	355
उत्पादन	एमटी	24,959	26,696	32,872	86,112	1,57,335
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	132	345	630
क्षमता उपयोग	%	53	57	70	89	94
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	132	167	177
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	25,428	26,041	32,306	79,972	1,56,122
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	127	315	614

87. प्राधिकारी उस क्षमता को नोट करते हैं जिसके साथ घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि में बढ़ोतरी की। यह नवंबर, 2018 में दीपक फेनोलिक लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि हुई है। पीओआई के बाद की अवधि में भी यही प्रवृत्ति देखी गई।

**ख. माँग में बाजार की हिस्सेदारी**

घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार रही:

माँग में बाजार हिस्सेदारी	इकाइयाँ	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई-पश्चात
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	16	16	18	41	63
संबद्ध देशों की बिक्री	%	57	35	24	18	6
अन्य देशों से आयात जिस पर एडीडी लगता है	%	15	6	8	18	15
अन्य देशों से आयात	%	12	43	50	23	16
कुल माँग	%	100	100	100	100	100

88. यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह जाँच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं में बढ़ोतरी और पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के कारण हुआ है। पीओआई के बाद की अवधि में भी घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है।

**ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ**

89. लाभों, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई- पश्चात
बिक्री की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	101	64	59
बिक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	115	88	71
लाभ / (हानि)	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(53)	(42)	38	(9)
लाभ / (हानि)	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(51)	(52)	123	(56)
पीबीआईटी	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	2	(10)	297	89
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(49)	(52)	151	(2)
निवेश की गई पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	3	(12)	109	14

90. वर्ष 2017-18 तक घरेलू उद्योग नुकसान का सामना कर रहा था और उसके बाद जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। पीबीआईटी, नकद लाभों और किए गए निवेश पर आय में भी जाँच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। पीओआई के बाद की अवधि के दौरान उपर्युक्त तीनों मानदंडों में गिरावट देखी गई है।

**घ) मालसूची**

91. घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई- पश्चात
औसत स्टॉक	एमटी	422	514	1,125	4,714	5,939
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	266	1,117	1407

92. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। जाँच अवधि में मालसूची का आंकड़ा बहुत अधिक रहा है, और बाद में जाँच अवधि के बाद की अवधि में यह और बढ़ा है।

**ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

93. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है-

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई-पश्चात (ए)
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	132	346	654
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	296	145
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	153

94. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में दीपक फेनोलिक्स के जुड़ने के कारण जाँच अवधि में रोजगार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हुई है। मजदूरी के भुगतान में भी वृद्धि देखी गई है। यह प्रवृत्ति पीओआई के बाद की अवधि में जारी रही है।

**च) पाटन का मार्जिन**

95. पाटन का स्तर उस सीमा का सूचक होता है जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। विश्लेषण यह दर्शाता है कि पीओआई में 4 सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में पाटन का मार्जिन सकारात्मक है और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान संभावना विश्लेषण के आधार पर दो अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सकारात्मक है।

**छ. पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता**

96. न तो घरेलू उद्योग द्वारा कोई सत्यापित की जा सकने वाली सूचना प्रस्तुत की गई है और न ही रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध है जिसका यह अर्थ निकाला जा सके कि इस क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले निवेश को संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति से क्षति पहुँच सके।

**ज. क्षति का स्तर और क्षति का अंतर**

97. पीओआई के दौरान क्षति के मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक III की शर्तों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुँच कीमत से की गई है और इस प्रकार निर्धारित किया गया क्षति का मार्जिन निम्नानुसार है:

**पीओआई**

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी (अमेरिकी \$/एमटी)	पहुँच मूल्य (अमेरिकी \$/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी \$/एमटी)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
1	ताइवान	मैसर्स फोर्मोसा केमिकल्स	***	***	***	***	नकारात्मक
2		मैसर्स ताइवान प्रोस्पेरिटी	***	***	***	***	नकारात्मक
3	कोरिया आरपी	मैसर्स कुम्हो	***	***	***	***	नकारात्मक
4		मैसर्स एलजी केम	***	***	***	***	नकारात्मक
5	सऊदी अरब	मैसर्स सऊदी कायन	***	***	***	***	20-40
6		मैसर्स राबिग रिफाईनिंग	***	***	***	***	नकारात्मक

**पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

98. घरेलू उद्योग ने पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित अनुरोध किए -
- निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया का एक विश्लेषण, पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप क्षति की संभावना दर्शाता है।
  - उत्पाद के संबंध में पूर्व के सभी अन्वेषणों में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है।
  - पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति में उल्लेखनीय मात्रा में आयात शुल्क समाप्ति की स्थिति में आयात बढ़ने की संभावना दर्शाता है।
  - संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा धारित अधिक उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय है।
  - निर्यातकों के पास मौजूद अप्रयुक्त क्षमताएँ चिंताजनक हैं।
  - विदेशी उत्पादकों के पास आसानी से उपलब्ध क्षमता शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात में वृद्धि की संभावना दर्शाती है।
  - संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों का निर्यात की ओर अत्यधिक झुकाव है। उत्पादक मुख्य रूप से निर्यात उन्मुखी हैं, और भारतीय बाजार उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - बाजार में भरमार होने के बावजूद संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा और अधिक विस्तार।
  - उत्पादकों के पास फीडस्टॉक की आसानी से उपलब्धता उन्हें लागत और बाजार में कच्चे माल की उपलब्धता से मुक्त कर देती है।
  - उत्पादक पाटन के आदि हैं, जैसा कि तृतीय देश पाटन मार्जिन से देखा जा सकता है।

- xi. एशियाई देशों में आवश्यकता से अधिक क्षमता, चीन के उद्योग की आत्मनिर्भरता से बाजार में एसीटोन की आपूर्ति मांग से अधिक हो गई है। इससे बाजार का परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से बदल गया है।
- xii. एसीटोन के व्यापार में शिफ्टिंग पैटर्न, जिसमें भारत में आयात का स्रोत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और समाप्त किए जाने के साथ बदलता है।
- xiii. तृतीय देश पाटनरोधी शुल्क जाँच से संबद्ध देशों के लिए कुछ बाजार बंद हो जाएंगे।
- xiv. संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए भारत एक आकर्षक बाजार है, और कोई अन्य बाजार ऐसी संभावनाएँ प्रस्तुत नहीं करता जितना कि भारतीय बाजार करता है।

**क. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा धारित अधिक उत्पादन क्षमता**

99. घरेलू उद्योग ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो संबद्ध देशों के पास निम्नानुसार क्षमताएँ दर्शाते हैं –

क्र. सं.	निर्यातक	देश	क्षमता (टन में)
ए1	एलजी केमिकल्स	कोरिया आरपी	3,60,000
ए2	कुम्हो पी एंड बी	कोरिया आरपी	4,20,000
ए3	<b>कुल कोरिया आरपी</b>		7,80,000
ए4	माँग	कोरिया आरपी	5,42,000
ए5	अधिक क्षमताएँ	कोरिया आरपी	2,38,000
बी1	सऊदी कायन पेट्रोकेमिकल्स	सऊदी अरब	1,40,000
बी2	पेट्रो राबिग	सऊदी अरब	1,50,000
बी3	<b>कुल सऊदी अरब</b>		2,90,000
बी4	माँग	सऊदी अरब	59,358
बी5	अधिक क्षमताएँ	सऊदी अरब	230,642
सी1	चांग चुन प्लास्टिक्स	ताइवान	1,86,000
सी2	फोर्मोसा केमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन	ताइवान	2,50,000
सी3	टीपीसीसी	ताइवान	2,20,000
सी4	<b>कुल ताइवान</b>		6,56,000
सी5	माँग	ताइवान	3,25,000
सी6	अधिक क्षमताएँ	ताइवान	3,31,000

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास अधिक क्षमताएँ हैं जो भारत की सम्पूर्ण माँग को आसानी से पूरा कर सकती हैं।



**ख. निर्यातकों के पास मौजूद अप्रयुक्त क्षमता**

101. उपर्युक्त के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं;

कोरिया आरपी					
विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
उत्पादन	एमटी	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	89,250	1,17,000	1,17,000	1,17,000

सऊदी अरब					
विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	1,40,000	1,40,000	1,40,000	2,90,000
उत्पादन	एमटी	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	21,000	21,000	21,000	43,500

ताइवान					
विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
उत्पादन	एमटी	5,76,490	5,84,229	5,65,323	5,68,484
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	79,510	71,771	90,677	87,516

102. यह देखा जा सकता है कि निर्यातकों के पास संबद्ध देशों में उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं। यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में प्रवेश करना जारी रह सकता है।

**ग. विदेशी उत्पादकों के पास मौजूद आसानी से उपलब्ध क्षमता**

103. आसानी से उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं के लिए प्रमाणों के साथ प्रस्तुत आंकड़े निम्नानुसार हैं;

**कोरिया**

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
उत्पादन	एमटी	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	89,250	1,17,000	1,17,000	1,17,000
निर्यात	एमटी	1,94,849	2,36,153	2,87,449	3,28,427
आसानी से उपलब्ध क्षमता	एमटी	2,84,099	3,53,153	4,04,449	4,45,427

**सऊदी अरब**

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	140,000	140,000	140,000	290,000
उत्पादन	एमटी	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	21,000	21,000	21,000	43,500
निर्यात	एमटी	64,855	54,707	65,297	1,87,142
आसानी से उपलब्ध क्षमता	एमटी	85,855	75,707	86,297	2,30,642

**ताइवान**

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
उत्पादन	एमटी	5,76,490	5,84,229	5,65,323	5,68,484
अप्रयुक्त क्षमताएँ	एमटी	79,510	71,771	90,677	87,516
निर्यात	एमटी	2,51,692	2,59,473	2,40,554	2,43,665
आसानी से उपलब्ध क्षमता	एमटी	3,31,202	3,31,244	3,31,231	3,31,181

104. यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों की मुक्त रूप से निस्तारणीय (डिस्पोजेबल) क्षमता है जो आसानी से भारत में पूरी मांग का प्रबंध कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातों को भारत की ओर अपवर्तित किया जा सकता है।

**घ. संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण**

105. निर्यात उन्मुखीकरण के लिए प्रमाणों के साथ आंकड़े निम्नानुसार हैं;

106. कोरिया से निर्यातों की स्थिति का सार निम्नानुसार है –

वर्ष	मूल्य (बाकी विश्व)	
	अमेरिकी \$ (मिलियन)	रुपये करोड़
2008	100.24	693
2009	66.01	457
2010	68.31	473
2011	101.60	703
2012	78.54	543
2013	170.92	1,182
2014	239.44	1,656
2015	106.62	738
2016	127.32	881
2017	203.72	1,409
2018	199.13	1,378

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
घरेलू माँग	एमटी	5,42,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000
उत्पादन	एमटी	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
निर्यात	एमटी	1,94,849	2,36,153	2,87,449	3,28,427
निर्यात निम्नलिखित के % के रूप में					
क्षमता	%	33%	30%	37%	42%
माँग	%	36%	44%	53%	61%
उत्पादन	%	39%	36%	43%	50%

107. सऊदी अरब से निर्यातों की स्थिति का सार निम्नानुसार है -

वर्ष	मूल्य (बाकी विश्व)	
	अमेरिकी \$ (मिलियन)	रुपये करोड़
2011	31.29	217
2012	48.68	337
2013	40.58	281
2014	62.54	433
2015	38.13	264
2016	26.11	181
2017	63.96	443
2018	121.96	845

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	1,40,000	1,40,000	1,40,000	2,90,000
घरेलू माँग	एमटी	56,226	65,445	54,654	59,358
अधिक क्षमताएँ	एमटी	83,774	74,555	85,346	2,30,642
प्रचालन दरें	%	85	85	85	85
उत्पादन	एमटी	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
निर्यात	एमटी	64,855	54,707	65,297	1,87,142
क्षमता के % के रूप में निर्यात	%	46%	39%	47%	65%
माँग के % के रूप में निर्यात	%	115%	84%	119%	315%
उत्पादन के % के रूप में निर्यात	%	55%	46%	55%	76%

108. ताइवान में निर्यातों की स्थिति का सार निम्नानुसार है –

वर्ष	मूल्य (बाकी विश्व)	
	अमेरिकी \$ (मिलियन)	रुपये करोड़
2011	238	1,649
2012	190	1,320
2013	209	1,448
2014	191	1,327
2015	115	799
2016	117	813
2017	160	1,110
2018	140	970

विवरण	यूओएम	2015	2016	2017	2018
क्षमताएँ	एमटी	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
घरेलू माँग	एमटी	3,25,000	3,25,000	3,25,000	3,25,000
अधिक क्षमताएँ	एमटी	3,31,000	3,31,000	3,31,000	3,31,000
प्रचालन दरें	%	85	85	85	85
उत्पादन	एमटी	5,57,600	5,57,600	5,57,600	5,57,600
निर्यात	एमटी	2,51,692	2,59,473	2,40,554	2,43,665
क्षमता के % के रूप में निर्यात	%	38%	40%	37%	37%
माँग के % के रूप में निर्यात	%	77%	80%	74%	75%
उत्पादन के % के रूप में निर्यात	%	45%	47%	43%	44%

109. उपर्युक्त सूचना से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों का ज़ोर निर्यात पर है और उनका निर्यात की ओर झुकाव बहुत अधिक है। संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की तुलनात्मक रूप से कम माँग के कारण संबद्ध देशों में क्षमताएँ और उत्पादन माँग से अधिक हैं।

**ड. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा और अधिक विस्तार**

110. यह निवेदन किया जाता है कि साक्ष्य कोरियाई उत्पादकों, कुम्हो और एल जी केम, दोनों द्वारा विस्तार करने की योजना को दर्शाते हैं और उनकी प्रक्षेपित क्षमताओं में 2020 में वृद्धि होने का अनुमान है। संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा क्षमता में वृद्धि, ए डी शुल्क की समाप्ति पर पाटन की संभावना की सुदृढ़ संकेतक है।

**च. फीडस्टॉक की आसान उपलब्धता**

111. घरेलू उद्योग ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि सऊदी अरब के उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के लिए पञ्चवर्ती रूप से एकीकृत हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसी व्यवस्था से उत्पादकों को कच्चे माल की कीमतों तथा उपलब्धता में उतार-चढ़ाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। ऐसी परिस्थितियाँ संबद्ध निर्यातकों को अतिरिक्त लाभ की स्थिति में लाती हैं।

**छ. तृतीय देश पाटन**

112. याचिकाकर्ताओं ने तीसरे देशों में संबद्ध देश के निर्यातकों के कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार के संबंध में संगणना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से निर्यात अन्य देशों में भी पाटन की प्रथा को प्रकट करते हैं। इस बात की संभावना है कि निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तुओं को पाटित करना जारी रखेंगे।

**ज. एशियाई देशों में माँग से अधिक क्षमता**

113. वर्तमान में भारत को छोड़ कर पूरी दुनिया के सामने अधिक क्षमता की समस्या है। प्रस्तुत किए गए प्रमाण एशिया के सभी अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं के लिए अधिक क्षमताएँ दर्शाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से बाजार की स्थिति, पाटन तथा क्षति की संभावना की जाँच में प्रासंगिक है।

**झ. एसीटोन में व्यापार का शिफ्टिंग पैटर्न**

114. भारत संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए एक पसंदीदा स्थान है। पूर्व की जाँच के इतिहास के अनुसार आयात के स्रोत का विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात में व्यापार का एक शिफ्टिंग पैटर्न है। भारत में ऐसे देशों से आयात होता है जहाँ शुल्क समाप्त हो जाते हैं।

**ञ. अन्य देशों द्वारा व्यापार सुधार जाँच**

115. 2008 में चीन जन. गण. पर एसीटोन के आयातों पर एक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था, 2014 में इसका विस्तार किया गया और 2019 में इस अधिरोपण को जारी रखने के लिए पुनरीक्षा जांच आरंभ की गई थी। यह जांच दक्षिण कोरिया और ताईवान से आयातों के विरुद्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी जांच तीसरे देशों में वस्तुओं को पाटित करने की संबद्ध देश के निर्यातकों की प्रवृत्तियों और अभ्यासों तथा भारत को निर्यातों के विपथन की संभावना को दर्शाती हैं।

**ट. चीन के उद्योग की आत्मनिर्भरता**

116. रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रमाण दर्शाते हैं कि चीन में संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयात की बड़ी माँग है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार चीन जन. गण. में क्षमताएँ 1.2 मिलियन एमटी तक बढ़ रही हैं, जो संबद्ध देशों से आयात को प्रभावित करेगा। ऐसी परिस्थितियों में चीन जन. गण. से डायवर्जन के कारण भारत में आयात बढ़ सकता है।

**ठ. एसीटोन की अधिक आपूर्ति**

117. पूरे विश्व में एसीटोन के लिए क्षमताएँ प्रचुर मात्रा में हैं जबकि भारत के बाहर इसकी माँग इस अनुपात में नहीं बढ़ी है। संबद्ध वस्तुओं की अधिक आपूर्ति हो रही है और इसके परिणामस्वरूप भारत में इसकी आयात कीमत में अत्यधिक गिरावट आ गई है। इस बात की संभावना है कि देश में प्रचुर माँग के कारण संबद्ध वस्तुओं की अधिक आपूर्ति भारत की ओर मोड़ दी जाएगी।

**ड. संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए भारत एक लाभप्रद बाजार है**

118. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखते हुए भारत संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार है;
- जब पूरे विश्व में एसीटोन की उत्पादन क्षमता माँग से अधिक है, भारत में इसकी माँग बढ़ रही है। एसीटोन के प्रमुख उत्पादक देश आत्मनिर्भर बन गए हैं और इसीलिए निर्यातकों द्वारा भारत जैसे देश में अपना निर्यात बढ़ाए जाने की संभावना है जहाँ माँग बढ़ रही है।

- ii. संबद्ध देशों के प्रमुख बाजार चीन और अमेरिका ने उपाय आरंभ कर दिए हैं या लागू कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये बाजार निर्यातकों के लिए आकर्षक नहीं रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इन निर्यातों के भारत की ओर शिफ्ट किए जाने की संभावना है।
- iii. संबद्ध देशों के उत्पादकों ने पूर्व में शेष विश्व की तुलना में भारत में बेहतर कीमतें प्राप्त की हैं, और इसलिए, भारत इन उत्पादकों के लिए एक लाभप्रद बाजार रहा है।
- iv. अन्य देशों द्वारा भारत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार उन देशों की आसानी से उपलब्ध क्षमताओं के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार बन जाएगा। यह पाटनरोधी शुल्क लगाने/न लगाने की स्थिति में भारत में आयातों के शिफ्टिंग पैटर्न के माध्यम से और पुख्ता रूप से स्थापित हो जाता है।
- v. कोरिया, सऊदी अरब और ताइवान के उत्पादक आमतौर पर अपने उत्पादों का पाटन कर रहे हैं जो अमेरिका और चीन की जाँच और भारत तथा तृतीय देशों में मौजूदा पाटन मार्जिन से स्पष्ट है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत में इन उत्पादों का पाटन कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

119. पाटन के जारी रहने और इसके परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं –
- i. क्षति की संभावना स्थापित नहीं की जा सकती है क्योंकि चीन जन. गण. से विस्कोस फ़िलामेंट यार्न में प्राधिकारी के अनुसार पीओआई के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
  - ii. क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूएई से प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड्स में प्राधिकारी के अनुसार कोई सत्यसाधनीय प्रमाण नहीं था।
  - iii. अन्य देशों द्वारा सऊदी अरब से आयातों पर कोई एडीडी लागू नहीं की गई है।
  - iv. उच्च निर्यात झुकाव के आरोप और भारतीय बाजार के कीमत आकर्षण की किसी सत्यसाधनीय प्रमाण द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।
  - v. तृतीय देश के पाटन आंकड़े सत्यसाधनीय नहीं हैं, और केवल सकारात्मक मार्जिन लेन-देन पर विचार नहीं किया जा सकता।
  - vi. “संभावना” का सर्वप्रथम मानदंड ही पूरा नहीं होता क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आ रही है। सऊदी अरब से आयात अत्यल्प (2.67%) है। संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई है।
  - vii. सऊदी अरब के पास मौजूद अधिक अप्रयुक्त क्षमता के लगभग 15% होने का दावा किया गया है जिसे बहुत अधिक नहीं माना जा सकता।
  - viii. संबद्ध निर्यातक वस्तुओं का अधिक स्टॉक नहीं रखते और इसे घरेलू और/या तृतीय देश के बाजारों में बेच देते हैं, और यहाँ उच्च क्षमता उपयोग दर है।
  - ix. याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों का झुकाव तृतीय बाजारों की ओर है।
  - x. इस तर्क के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि सऊदी अरब के वस्तुओं के साथ पश्चवर्ती रूप से एकीकृत होने के कारण उनके पास फीडस्टॉक की आसान उपलब्धता है। यदि सऊदी अरब के उत्पादकों के पास कच्चे माल की आसान उपलब्धता है भी तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आयातों में वृद्धि कर दी जाएगी। वास्तव में सऊदी अरब के निर्यातकों ने कभी भी बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं किया है।

- xi. प्रतिवादी के निर्यात की ओर झुकाव को कच्चे माल की उपलब्धता से नहीं मापा जा सकता क्योंकि विनिर्माण संयंत्र के ऊर्ध्वाधर एकीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य कच्चे माल की अधिप्राप्ति 'थोड़ी सी दूरी' के आधार पर की जाती है।
- xii. तृतीय देश में पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति के मार्जिन का अनुमान एसएसआर की जाँच में न तो एक आवश्यकता है और न ही ऐसी कोई प्रथा है।
- xiii. चीन द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध एसएसआर जाँच शुरू की गई है परंतु सऊदी अरब के विरुद्ध नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में जाँच शुरू की है। तथापि प्रारंभिक विश्लेषण के बाद यह जाँच रोक दी गई है।
- xiv. **कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में पीओआई के बाद की अवधि में पाटन और क्षति की संभावना नहीं है।**
- पीओआई के बाद का विश्लेषण, सनसेट समीक्षा के दौरान शुरू किए गए संभावना विश्लेषण का एक अनिवार्य घटक है। प्राधिकारी को भविष्य में शुल्क जारी रखे जाने की स्थिति में क्षति की संभावना पर विचार करना चाहिए। वर्तमान समीक्षा में जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2018 से मार्च 2019 है। प्राधिकारी ने आगे पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जाँच करने के लिए अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की अवधि को पीओआई के बाद की अवधि माना है। तथापि उपर्युक्त स्थापित पीओआई-पश्चात अवधि के बाद से कोविड-19 महामारी को देखते हुए विश्व बाजार में बहुत सी घटनाएँ हुई हैं, विशेष रूप से एसीटोन बाजार में, और संभावना का विश्लेषण करते हुए इन पर भी विचार किया जाना चाहिए।
  - स्थापित पीओआई-पश्चात अवधि की समाप्ति के बाद से भारत सहित सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है। यह महामारी दिसंबर 2019 में शुरू हुई और आज की तारीख तक इसके मामले उल्लेखनीय रूप से लगातार बढ़ रहे हैं।
  - भारत की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए, हैंड-सैनिटाइजर्स और डिसइन्फेक्टेंट की माँग कई गुना बढ़ गई है और भविष्य में भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ती रहेगी। एसीटोन आइसो-प्रोपिल एल्कोहोल ("आईपीए") के लिए एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, जो डिसइन्फेक्टेंट और हैंड सैनिटाइजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। वास्तव में मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वर्ष 2020 के दौरान पीओआई के बाद की अवधि में एसीटोन की माँग और कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया कि वृद्धि की यह प्रवृत्ति एक अल्पकालिक घटना है।
  - इस संदर्भ में घरेलू उद्योग के दावे सही नहीं हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, कोविड-19 महामारी की प्रकृति को देखते हुए, हैंड-सैनिटाइजर्स और डिसइन्फेक्टेंट की माँग में वृद्धि लंबे समय तक जारी रहेगी और वह भी सतत रूप से क्योंकि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने आस-पास के वातावरण और हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एसीटोन आधारित हैंड-सैनिटाइजर्स और डिसइन्फेक्टेंट बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध सैनिटाइजर्स का सर्वाधिक सुलभ स्वरूप है। एसीटोन आधारित आईपीए की बढ़ती हुई माँग की पुष्टि बाजार रिपोर्टों द्वारा की गई है जैसे इंडियन केमिकल न्यूज़, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:
  - कोविड-19 महामारी ने भारत और वैश्विक बाजार में आईपीए की माँग बढ़ा दी है। बाजार शोध के अनुसार 2020-2024 के दौरान आईपीए की वैश्विक माँग का पूर्वानुमान 522,000 टीपीए तक पहुँच जाएगा और इसमें से आधी वृद्धि एपीएसी से होगी।
  - स्रोतों के अनुसार भारत में आईपीए की कुल माँग 200,000 टीपीए तक की है चूंकि सैनिटाइजर्स के लिए आईपीए की बड़े स्तर पर माँग है और इसमें दुगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

- यहाँ तक कि घरेलू उद्योग के संघटक – मैसर्स दीपक फेनोलिक्स ने हैंड-सैनिटाइजर्स की जरूरत को पूरा करने और आने वाले वर्षों में आईपीए की माँग में वृद्धि की अपेक्षा में हाल ही में एसीटोन-आधारित आईपीए का निर्माण शुरू किया है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हैंड-सैनिटाइजर्स और डिसइन्फेक्टेंट की माँग बढ़ रही है और भविष्य में भी सतत रूप से बढ़ती रहेगी, यह स्वाभाविक है कि एसीटोन, जो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, की माँग भी बढ़ रही है और भविष्य में भी बढ़ती रहेगी। इसलिए इस दावे का कोई मजबूत आधार नहीं है कि हैंड-सैनिटाइजर्स की माँग में यह वृद्धि और इसके लिए एसीटोन की माँग में वृद्धि अल्पकालिक होगी और इस दावे को खारिज किया जाना चाहिए।
- माँग में वृद्धि के अतिरिक्त, पीओआई के बाद की अवधि के दौरान एसीटोन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से। जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है, पीओआई के बाद से एसीटोन की कीमतें लगभग दुगुनी हो गई हैं। पीओआई के दौरान इसकी कीमतों के साथ तुलना करने पर विश्वव्यापी कीमतें निम्नलिखित प्रवृत्ति दर्शाती हैं:

वर्ष	2018	पीओआई	2019	अप्रैल-20	मई-20	जून-20
	-	-	-	(पिछला सप्ताह)	(पिछला सप्ताह)	(पिछला सप्ताह)
आईसीआईएस कीमत एसीटोन थोक	612	533	449	693	958	1,030
पीओआई की तुलना में बदलाव	-	-	-	30%	80%	93%

- कोविड महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से पीओआई की तुलना में जून 2020 के दौरान एसीटोन की कीमतें लगभग दुगुनी हो गई हैं। वृद्धि की इस प्रवृत्ति में कोविड-19 महामारी के समाप्त होने तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि एसीटोन आधारित डिसइन्फेक्टेंट की माँग में वृद्धि जारी रहेगी। माँग में वृद्धि और इसके कारण कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान प्रचलित कीमतों पर एसीटोन का निर्यात करना संभव नहीं है। उपर्युक्त मौजूदा परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि एसीटोन के आयात के कारण भविष्य में क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- इस तथ्य के अतिरिक्त कि एसीटोन की माँग और कीमतें भविष्य में कई गुना बढ़ती रहेंगी, जो यह दर्शाता है कि भविष्य में पाटन की कोई संभावना नहीं है, यह भी नोट किया जाना चाहिए कि भारतीय घरेलू उद्योग भारतीय डिसइन्फेक्टेंट/सैनिटाइजर की माँग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। पीओआई के दौरान 1,99,834 एमटी की घरेलू माँग की तुलना में घरेलू उद्योग के पास केवल 97,140 एमटी की क्षमता थी। इस प्रकार डिसइन्फेक्टेंट उद्योग सहित आधे से अधिक भारतीय अनुप्रवाह उद्योगों को हर समय आयातित एसीटोन पर निर्भर रहना होगा। एसीटोन के आयात पर कोई भी प्रतिबंध कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई के लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि एसीटोन और इसके परिणामस्वरूप डिसइन्फेक्टेंट की आपूर्ति में और कमी आ जाएगी।
- इस प्रकार बढ़ती हुई माँग और घरेलू उत्पादकों की सीमित क्षमताओं को देखते हुए, और यह देखते हुए कि भविष्य में एसीटोन की कीमतें ऊँची रहने की संभावना है, प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारत के बड़े सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। उपर्युक्त कारणों से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए।



**प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियाँ****120. मै. सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि. और मै. विनमार इंटरनेशनल लिमिटेड,****मै. ईएलपी द्वारा दिया गया आवेदन**

- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग के संबंध में की गई जांच अपने इस जांच परिणाम के पीछे वस्तुपरक कारण नहीं देते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा “बीज का विपणन” के लिए आयात किए गए थे क्योंकि इसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि जांच की अवधि के दौरान कुल आयातों का 6 प्रतिशत से अधिक आयात “बीज का विपणन” के कारण किया गया था जो संबद्ध देशों में से कुछ देशों द्वारा आयातों की तुलना में मात्रा में अधिक है।
- ख. शुल्क मुक्त आयातों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चयनित रूप से बाहर नहीं किया जाना चाहिए जब याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल करने के लिए सही कारण देने हेतु सुविधाजनक हो और शुल्क मुक्त आयातों को संपूर्ण रूप में वर्तमान जांच से बाजार किया जाना चाहिए।
- ग. वैकल्पिक तौर पर, याचिकाकर्ता जिन्हें आयातक के रूप में पाया जाता है, को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए।
- घ. याचिकाकर्ताओं को निदेश दिया जाना चाहिए कि वे दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अंतर्गत यथा-निर्दिष्ट अत्यधिक गोपनीयता के उनके दावों और गोपनीयता संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं करने के मुद्दे को सही करें। हितबद्ध पक्षकारों को दिए जा रहे तत्काल सही किए गए आंकड़ों के अभाव में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत अपने दायित्वों का अवश्य ही पालन करना चाहिए तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को अस्वीकार करना चाहिए।
- ड. अग्रिम लाइसेंस आयातों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि जारी न रखे गए अथवा समाप्त किए गए शुल्कों का प्रभाव शुल्क भुगतान किए गए आयातों पर ही महसूस किया जाएगा। इस कारण से अग्रिम लाइसेंसों को वर्तमान जांच के क्षेत्र से पूर्ण रूप से बाहर किया जाना चाहिए – यदि शुल्क मुक्त आयातों को घरेलू उद्योग के आंकलन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाहर किया जा रहा हो तब उसी मानक को निष्पक्ष रूप से और समान रूप से पालन किया जाना चाहिए।
- च. एसीटोन के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक का होना पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि बीआईएस प्रमाणन आवश्यकता और उससे संबद्ध लागतों के फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आएगी। तदनुसार, संभावना के आंकलन पर बीआईएस की आवश्यकता के प्रभाव को बाहर करना अनुचित होगा। तदनुसार यदि शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तब घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- छ. कीमत में कटौती के संबंध में यह नोट करना संगत है कि उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री, मांग में बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, माल सूची, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता जैसे घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि उसी सीमाओं में कटौती हुई है। इस कारण से कारणात्मक संबंध में कोई स्पष्ट विच्छेद नहीं है क्योंकि कथित कीमत में कटौती और घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- ज. निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II और पूर्व के उदाहरणों के अनुसार संभावना कि कारकों का व्यापक आंकलन करने में असफल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसके लिए कारण दिए बिना केवल कुछ कारकों (जैसे पूर्व की जांच में पाटन मार्जिन, सतत् आयात और निर्यात उन्मुखीकरण) पर चयनित रूप से विचार किया गया है।
- झ. सुमिटोमो केमिकल्स एशिया प्रा. लि. और विनमार इंटरनेशनल लिमिटेड मूल जांचों में भागीदार नहीं थे और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से उत्पन्न होने की संभावना का आंकलन करते समय पूर्व की जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं।

- ट. सऊदी अरब से आयातों को पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के बावजूद समझने योग्य मात्रा पर भारत में जारी रहना नहीं माना जा सकता है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं से आयात सऊदी अरब से कुल किए गए आयातों की तुलना में अधिक है।
- ठ. ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी क्षमताओं जिसका उपयोग घरेलू बिक्री के लिए “स्वतंत्र रूप में बिक्री योग्य” के रूप में समान माना है जो वाणिज्यिक रूप से अवास्तविक और तर्कहीन है क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि उत्पादक का अन्य देशों में प्रतिबद्धताएं और मौजूदा बाजार हुई होती तथा एक देश के लिए सभी बिक्री अन्य बाजार में आसानी से हस्तांतरण किए जाने योग्य नहीं है।
- ड. चूंकि सऊदी अरब निर्यात उन्मुख है अथवा इसके उत्पादन का प्रतिशत के रूप में 70-80 प्रतिशत निर्यात है, इसका यह अभिप्राय नहीं होता है कि सऊदी अरब से समग्र निर्यात सामग्री का आयात भारत में किया गया है अथवा किए जाने की संभावना है। वास्तव में, भारत निर्यातकों के लिए बिल्कुल भी कीमत आकर्षक नहीं है क्योंकि तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत भारत के लिए निर्यात कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। इस कारण से अन्य बाजार भारत की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में अधिक कीमत आकर्षक है जिसके कारण यदि शुल्कों को समाप्त ही कर दिया जाता है तब भारत की ओर संबद्ध वस्तुओं को फिर से भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है।
- ढ. पाटन और क्षति की संभावना के विश्लेषण के लिए इस तथ्य का आंकलन आवश्यक है कि क्या शुल्क को जारी न रखे जाने के बाद पाटन अथवा क्षति की अभी भी कोई संभावना है जिसे घरेलू उद्योग को सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान भी संबद्ध वस्तुओं पर लागू थी और जांच की अवधि की बाद की अवधि का आंकलन इस तथ्य का सही विश्लेषण नहीं उपलब्ध कराता है कि क्या घरेलू उद्योग को संभवतः इन शुल्कों को जारी न रखे जाने के बाद पाटन अथवा क्षति का सामना करना पड़ेगा बल्कि वास्तव में वर्तमान जांच की अवधि तक इसका विस्तार हो सकता है। इस कारण से, जांच की अवधि के बाद की अवधि का आंकलन जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तुओं पर किसी शुल्कों के लागू न रहने पर भी संभावना का द्योतक होगा।
- ण. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर विचार करते हुए कोई कारणात्मक संबंध नहीं है और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी उठाई गई कोई क्षति अन्य कारकों जैसे दीपक फिनोलिक्स को 14 दिनों की अवधि के लिए बंद किए जाने के कारण हुई है।
- ट. कोविड-19 महामारी जो जांच की अवधि की बाद की अवधि के बाद उत्पन्न हुई है, के फलस्वरूप हैंड सेनिटाइजर में इसके उपयोग के कारण एसिटोन के लिए मांग और कीमतों में वृद्धि हुई है। यह आशा है कि बढ़ी हुई मांग भविष्य में भी जारी रहेगी।
- ठ. वास्तव में, इन याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता, मैसर्स दीपक फिनोलिक्स ने हाल में एक एसिटोन आधारित आईसोप्रोपिल एल्कोहल (आईपीए) निर्माण संयंत्र स्थापित किया है जिसके प्रभाव पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद की मांग और आपूर्ति पर विचार करना चाहिए। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- ड. मांग में लगातार वृद्धि के कारण, विचाराधीन उत्पाद की कीमत में हाल की अवधि में बहुत अधिक सीमा तक वृद्धि हुई है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना कोविड-19 के विरुद्ध देश की लड़ाई के व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा।

## 121. मै. एफसीएफसी, मै. टीपीसीसी और मै. एलजी. केम

### डब्ल्यू टी सी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

- क. कोरिया गणराज्य से एसिटोन का निर्यात भारत की मांग की तुलना में बहुत कम रहा है।
- ख. कोरिया गणराज्य में एसिटोन के केवल दो उत्पादक हैं। मूल पाटनरोधी जांच में, कोरिया गणराज्य से कुल निर्यात केवल 4414 मी.टन (कुल मांग का 4.4 प्रतिशत) था और कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उक्त जांच में भाग नहीं लिया।

- ग. प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में, कोरिया गणराज्य से कुल निर्यात (कुल मांग का 6.06 प्रतिशत) की तुलना में 8486 मी.टन; था। इस निर्णायक समीक्षा जांच में, इन उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों को मूल्य सीमा अवधारणा को लागू करने के कारण साफ इंकार कर दिया गया था।
- घ. पूर्व की दोनों जांचों में डीजीटीआर ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और न कि कोरिया गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पाटन/पाटन मार्जिन तय किया है।
- ड. वर्तमान दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में, कोरिया गणराज्य के दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने भाग लिया है और डीजीटीआर ने एलजी केम के मामले में नकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन तथा अन्य उत्पादक के मामले में नकारात्मक क्षति मार्जिन तय किया है।
- च. भारत कोरिया गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात और पाटन के वास्ते एक लक्ष्य देश नहीं है।
- छ. जांच की अवधि की बाद की अवधि से संबंधित आंकड़ों जिस पर डीजीटीआर द्वारा विचार किया गया है, में, यह सिद्ध किया गया था कि एलजी केम ने जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019) भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।
- ज. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि के दौरान केवल लघु मात्रा में निर्यात एलजी केम द्वारा किया गया था और वह भी जांच की अवधि के पहले चार महीनों में ही किया गया था। एलजी केम ने अप्रैल 2019 से जून, 2020 तक भारत को केवल चार खेप एसिटोन का निर्यात किया है।
- झ. टीपीसीसी द्वारा भारत को एसिटोन का निर्यात देश की मांग की तुलना में बहुत कम रहा था। निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि के दौरान टीपीसीसी ने केवल \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। भारत को कोई भी निर्यात उसके बाद नहीं किया गया था।
- ट. डीजीटीआर ने टीपीसीसी और ताइवान के अन्य उत्पादक के मामले में नकारात्मक पाटनरोधी क्षति मार्जिन तय किया है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि इस तथ्य को सिद्ध करता है कि भारत टीपीसीसी द्वारा निर्यातों के लिए एक लक्ष्य देश नहीं है। टीपीसीसी ने यह अनुरोध किया है कि वर्तमान अवधि में टीपीसीसी द्वारा बेची गई एसिटोन की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। घरेलू तथा निर्यात बिक्री 1000 यूएस डॉलर प्रति मी.टन. के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इन कीमत स्तरों को पाटित और क्षतिकारक कीमत के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस कारण से मौजूदा शुल्क के लगातार लगाए रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है। टीपीसीसी द्वारा किए गए दावे के समर्थन में, उन्होंने अक्टूबर 2019 से जून, 2020 की अवधि के लिए घरेलू बिक्री और निर्यातक बिक्री के संबंध में टी बिक्री आंकड़ों के द्वारा टी प्रस्तुत किया है।
- ठ. चीन जन.गण में कोविड-19 महामारी के शुरु होने के बाद आईसीआईएस द्वारा यथा-प्रकाशित विभिन्न देशों द्वारा निर्यात कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है और जून, 2020 के दौरान 1046 यूएस डॉलर प्रति मी.टन के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।
- ड. टीपीसीसी और एफसीएफसी ने ताइवान से चीन को किए गए निर्यात की टी बाई टी कीमत उपलब्ध कराई है जिसे ताइवान की सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात आंकड़ों से देखा जा सकता है।
- ढ. डीजीटीआर द्वारा जारी प्रकटन विवरण के अनुसार, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एफसीएफसी के मामले में, इन वस्तुओं का निर्यात भारत को उपर्युक्त क्षति रहित स्तरों पर किया गया था और इस कारण से क्षति मार्जिन को नकारात्मक के रूप में निर्धारित किया गया था।
- ण. एफसीएफसी अगस्त, 2018 से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नियमित रूप से नहीं करता रहा है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की जांच की अवधि के दौरान केवल लघु मात्रा में निर्यात एफसीएफसी द्वारा किया गया था। एफसीएफसी ने अक्टूबर 2019 से जून, 2020 तक भारत को एसिटोन का लघु मात्रा में निर्यात किया है। एफसीएफसी ने नमूना बीजकों के साथ अक्टूबर, 2019 से जून, 2020 तक की अवधि के लिए घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के संबंध में टी बाई टी बिक्री आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

- त. वैश्विक रूप से कोविड-19 महामारी की शुरुआत जनवरी, 2020 से हुई और इसका प्रभाव एसिटोन की मांग पर पड़ा है क्योंकि उसका उपयोग आईसोप्रोपिल एल्कोहल (आईपीए) का निर्माण करने के लिए किया गया है। प्राधिकारी को वर्तमान परिस्थितियों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए।
- थ. आईपीए सबसे अधिक आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला फार्मास्युटिकल उद्योग में कीटनाशक है और इसका व्यापक रूप से उपयोग एल्कोहल वाइप्स, स्वाद, हैंड सेनिटाइजर, कीटनाशक और ओरल माऊथ में भी किया जाता है। कोविड 19 महामारी ने भारत तथा वैश्विक बाजार दोनों में आईपीए की मांग में वृद्धि की है। बाजार के अनुसंधान के अनुसार, आईपीए की वैश्विक मांग के लिए पूर्वानुमान 2020-2024 के दौरान 5,22,000 टीपीए तक पहुंच जाएगा।
- द. आईपीए की मांग और कीमतों में वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप एसिटोन की मांग में भी वृद्धि कई गुना हुई है। इसके फलस्वरूप वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा किए गए विचार के अनुसार जांच की अवधि और जांच के बाद की अवधि (6 महीने) सहित पूर्व की किसी अवधि की तुलना में एसिटोन की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। इंडियन केमिकल न्यूज में नीचे दिए गए अनुसार उल्लेख है:
- “हम आश्चर्य हैं कि अधिक से अधिक फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्माण भारत में आईपीए की निर्बाध आपूर्ति के कारण की जाएगी।”* कोविड 19 महामारी के कारण भारत तथा वैश्विक बाजार दोनों में आईपीए की मांग में वृद्धि हुई है। बाजार के अनुसंधान के अनुसार, आईपीए की वैश्विक मांग के लिए पूर्वानुमान 2020-2024 के दौरान 5,22,000 टीपीए तक पहुंच जाएगा और इस वृद्धि का आधा हिस्सा एपीएसी से आएगा।
- ध. स्रोतों के अनुसार, आईपीए के लिए भारत की कुल मांग 200,000 टीपीए के लगभग है क्योंकि सेनिटाइजर के लिए आईपीए की मांग बहुत अधिक है और यह दुगुना हो गया है।
- न. आईपीए की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप एसिटोन की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी। एसिटोन पर किसी पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना उत्पादन के विरुद्ध होगा क्योंकि भारत में एसिटोन की मांग और आपूर्ति में पहले से ही बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। भारतीय उद्योग मांग का केवल 50 प्रतिशत पूरा करता है और इस महामारी के फैलने के कारण मांग में अतिरिक्त तीव्र वृद्धि के साथ इस अंतर में और वृद्धि होगी।
- प. भारत को निर्यात दीपक फिनोलिक्स द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने के बाद लगभग रुक गया है।
- फ. एसिटोन का प्रमुख निर्यात चीन जन.गण को किया जा रहा है और वह भी बहुत अधिक कीमतों पर किया जा रहा है। इस व्यवहार में किसी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। यह प्रवृत्ति संभवतः पूरे विश्व में वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखकर जारी रहेगी।
- ब. जांच की अवधि के तत्काल बाद, एसिटोन की कीमतों में वैश्विक स्तर पर नीचे की ओर फिसलन होती है। इससे सभी देशों से आयात की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।
- भ. विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, संपूर्ण विश्व को इसके बाद से कोविड-19 के साथ जीना पड़ेगा और सभी आवश्यक पूर्वोपाय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सेनिटाइजर का उपयोग एक जीवन का तरीका हो गया है और इस कारण से एसिटोन की मांग उच्च स्तरों पर बनी रहेगी। एसिटोन की मांग और कीमतों में वृद्धि होना जारी रहेगा और भविष्य में किसी पाटन के होने की कोई संभावना नहीं है।
- म. वैश्विक बाजार में प्रचलित कीमत के वर्तमान स्तर के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है और प्राधिकारी द्वारा वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात होने की कोई संभावना नहीं है।
- य. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग के बुक्स का विश्लेषण करें क्योंकि वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग बहुत अधिक लाभ कमा रहा है और भविष्य में भी वैसा करना जारी रहेगा।
- कक. घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ है तथा संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को लगाने से एसिटोन की कीमतें कम हो जाएंगी। यह अनुरोध है कि अंतिम प्रयोक्ता के हितों और देश के हितों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग को किसी अनुचित संरक्षण के कारण बाजार में एकाधिकारवादी स्थिति

उत्पन्न हो जाएगी जहां संबद्ध वस्तुओं की मांग केवल ऊपर की ओर जा रही हो और उसके साथ ही इसकी कीमतें भी ऊपर की ओर जा रही हों।

- खख. डीजीटीआर को पाटन एवं क्षति की संभावना का विश्लेषण करते समय मौजूदा परिस्थिति और एसिटोन की मांग और कीमतों की संभावित प्रवृत्तियों पर विचार करना चाहिए।
- गग. कोविड 19 महामारी का प्रभाव कई वर्षों तक चलेगा और एसिटोन की खपत पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जिसके फलस्वरूप आईपीए की खपत में वृद्धि होगी।
- घघ. अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 के दौरान कीमतों में अल्पकालिक गिरावट मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना के बारे में निर्णय लेने के लिए मानदंड नहीं होगा।
- ड.ड. वर्तमान आपवादिक परिस्थितियाँ जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 से प्रभावित है, के दौरान डीजीटीआर से अनुरोध है कि वे महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के आधार पर संभावना के विश्लेषण की जांच करें।
- चच. हम आशा करते हैं कि डीजीटीआर वर्तमान जांच को समाप्त कर देगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाता है तब घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।

## 122. सरवदा द्वारा

**निम्नलिखित के लिए अभ्यावेदन:** (1) कुमहो पी ऐंड बी केमिकल्स, (2) हुमादे कारपोरेशन, (3) यूनिद ग्लोबल कारपोरेशन, (4) सैमसंग सी ऐंडटी कारपोरेशन (5) आईएमएस कारपोरेशन और, (6) कानको मार्केटिंग इंक

### क. जांच की अवधि के बाद और कोविड 19 के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए संभावना के विश्लेषण की जांच अवश्य की जानी चाहिए।

- क. एसिटोन की मांग और कीमतों का कोविड 19 के फैलने के बाद अचानक वृद्धि जारी है क्योंकि एसिटोन आईपीए हैंड-सेनिटाइजर, जिसकी मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, का निर्माण करने में एक प्रमुख अवयव है।
- ख. जांच की अवधि के दौरान एसिटोन की प्रचलित कीमतों से तुलना किए जाने पर, एसिटोन की विश्व-व्यापी कीमतें यह दर्शाती हैं कि अप्रैल 2020, मई 2020 और जून, 2020 के दौरान इनकी कीमतों में क्रमशः 30 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 93 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई प्रवृत्ति के आगे तब तक भी जारी रहने की आशा है जब तक कोविड 19 महामारी समाप्त न हो जाए क्योंकि एसिटोन आधारित कीटनाशकों की मांग में तीव्र गति से बढ़ना जारी रहेगा। इसी प्रकार से जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान भारत और तीसरे देशों को केपीबी की अपनी निर्यात कीमतें विश्वव्यापी कीमतों की तुलना में समान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- ग. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान प्रतिवादियों के लिए पहले ही नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। ऐसी स्थिति होने के कारण जहां कीमतें जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि और कोविड-19 के बाद की अवधि के दौरान बहुत अधिक सीमा तक अधिक थी, पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना का प्रश्न ही नहीं उठता।

### ख. प्रतिवादियों के लिए स्थापित नकारात्मक क्षति मार्जिन

- घ. प्राधिकारी ने प्रतिवादियों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि प्रतिवादियों द्वारा उत्पादन और निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण किसी भी तरीके से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है और घरेलू उद्योग आयात की गई वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की अच्छी स्थिति में है। पाटनरोधी शुल्क का एकमात्र उद्देश्य पाटन के क्षतिकारक प्रभावों को नियंत्रित करना है जिसे वर्तमान मामले में प्राप्त कर लिया गया है।

**ग. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को किसी क्षति की पुष्टि नहीं की गई**

ड. प्रकटन विवरण में, प्राधिकारी ने निम्नलिखित का निर्धारण किया है:

- i. घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि और आयातों में अनुरूप गिरावट: घरेलू उद्योग की बिक्री में 2017-18 और जांच की अवधि के बीच 148 प्रतिशत तक तथा जांच की अवधि और जांच के बाद की अवधि के बीच 95 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, संबंधित अवधियों के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों में बहुत अधिक गिरावट अर्थात् 14 प्रतिशत और 57 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। प्रतिवादियों द्वारा निर्यातों में गिरावट और अधिक तीव्र अर्थात् लगभग 85 प्रतिशत तक हुई थी जो स्पष्ट रूप से आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के बीच कारणात्मक संबंध के न होने को दर्शाता है।
- ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता और उपयोग में सुधार: प्राधिकारी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इसकी मात्रा संबंधी मानदंडों में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शाई है। जांच की अवधि की बाद की अवधि के आंकड़े भी तीव्र वृद्धि को दर्शाते हैं जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को भविष्य में किसी प्रतिकूल क्षति के होने की संभावना नहीं है।
- iii. कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं: प्रतिवादियों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के अलावा, प्राधिकारी ने इस तथ्य का भी निर्धारण किया है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न तो न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभप्रदता, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
- v. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता: प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जो यह सुझाव देता हो कि इस क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण समाप्त हो सकता है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग स्वस्थ है और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहेगा।

**घ. प्रतिवादियों के संबंध में पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं**

च. जहां तक प्रतिवादियों के हित का संबंध है, निम्नलिखित कारणों से पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है:

- i. पाटन मार्जिन का विगत निर्धारण असंगत है: मूल जांच और प्रथम निर्णायक समीक्षा के दौरान मौजूद बाजार गतिशीलता में पिछले 12 वर्षों से अधिक से बहुत अधिक सीमा में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से, 2008 अथवा 2014 में मौजूद पाटन मार्जिन की केवल तुलना और उसका 2020 में पाटन मार्जिन से तुलना के फलस्वरूप उचित तुलना नहीं हो पाएगी।
- ii. चीन जन.गण से “4, 4 डायमिनो स्ट्राइबिन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डासडा)” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा और यूरोपीय यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से “मेलामाइन” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों को वापस लिए जाने की सिफारिश की यद्यपि इसने सकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया। वर्तमान मामले के तथ्य पाटनरोधी शुल्क के वापस लिए जाने के संबंध में तमाम अथवा उससे अधिक मजबूत है।
- iii. प्रतिवादियों द्वारा भारत को निर्यातों में बहुत अधिक गिरावट: आयात की मात्रा में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। प्रतिवादियों के आंकड़े भारत को वास्तविक निर्यात के संबंध में यह दर्शाते हैं कि निर्यातों में 2018 और जांच की अवधि के बीच 31 प्रतिशत; जांच की अवधि और जांच की बाद की अवधि के बीच 85 प्रतिशत और 2018 तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के बीच 90 प्रतिशत तक गिरावट आई।

ऐसी स्थिति होने के कारण ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि ये आयातों के अत्यधिक मात्राओं पर जारी रहने का संकेत देते हैं।

- iv. कोई निर्यात उन्मुखीकरण नहीं: निर्यात उन्मुखीकरण अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना मौजूद है। प्रस्तुत किए गए प्रतिवादियों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अपने कुल निर्यातों में से तथा अपने उत्पादन की तुलना में भारत को प्रतिवादियों का कुल निर्यात बहुत मामूली था क्योंकि भारत को निर्यात जांच की अवधि से लगभग रुक गया है। यह निर्यात उन्मुखीकरण न होने को दर्शाता है।
- v. व्यापार में कोई विपठन नहीं: सबसे पहले, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि व्यापार विपठन की कोई संभावना है। दूसरा नकारात्मक क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादियों के लिए किया गया है। इस प्रकार से यदि पाटनरोधी शुल्कों को जारी नहीं भी रखा जाता है तब तीसरे देश का निर्यात भारतीय बाजार में क्षति रहित स्तर पर प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप क्षति के फिर से होने की संभावना नहीं होती है।
- vi. भारत प्रतिवादियों के लिए आकर्षक बाजार नहीं: भारत प्रतिवादियों के लिए एक आकर्षक बाजार नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा भारत को निर्यात लगभग पूर्ण रूप से रुक गया है।
- vii. प्रतिवादियों के पास कोई स्वतंत्र रूप से कोई बिक्री योग्य क्षमता नहीं है: प्रारंभ में, संबद्ध देशों में केवल क्षमताओं का मौजूद रहने के फलस्वरूप वास्तव में भारत को बढ़ा हुआ निर्यात होता है। वास्तव में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रतिवादी पहले से ही आदर्शतम क्षमता उपयोग से अधिक पर प्रचालन कर रहे हैं। इस प्रकार से उपयोग न की गई और स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता का प्रश्न नहीं उठता है।
- viii. विस्तार के लिए कोई योजना नहीं: घरेलू उद्योग के इस दावे का कोई आधार नहीं है कि प्रतिवादियों की विस्तार की कोई योजना है। इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। घरेलू उद्योग का उक्त दावा वास्तविक रूप से सही नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन: घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण इसके कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक और सतत सुधार को दर्शाता है। यह तथ्य कि पिछले तीन वर्षों से अधिक से घरेलू उद्योग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इस तथ्य का स्पष्ट संकेत देता है कि संबद्ध देशों से आयात अब घरेलू उद्योग के लिए खतरा नहीं है।
- x. निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रतिवादियों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करें।
- xi. क्षति मार्जिन का निर्धारण इस तथ्य को सिद्ध करता है कि प्रतिवादियों द्वारा उत्पादन किए जा रहे और निर्यात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को किसी भी रूप में क्षति नहीं हो रही है और घरेलू उद्योग आयात की गई वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। वास्तव में, घरेलू उद्योग आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर समान वस्तु की बिक्री करने में सक्षम रहा है और साथ ही बहुत अधिक लाभ कमाने में सक्षम रहा है।
- xii. प्रतिवादी वर्तमान निर्णायक सीक्षा जांच को तत्काल समाप्त करने का निवेदन करते हैं।

## 123. एलकेएस द्वारा सेबिक और पेट्रो राबिघ की ओर से अनुरोध

### क. घरेलू उद्योग

- i. यह अनुरोध किया जाता है कि एसआई ग्रुप और दीपक फिनोलिक्स ने भारत में बहुत अधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात कुल संबद्ध आयातों का लगभग 15 प्रतिशत होता

है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा “नगण्य” के रूप में दावा किया जा रहा है। आयातों में सऊदी अरब का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है और उसे बहुत अधिक नहीं माना जाना चाहिए।

- ii. इसके अलावा एचओसीएल एक रुग्ण इकाई है और इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसे इस जांच के उद्देश्य से अर्थक्षम घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है।
- iii. यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के आशय से घरेलू उद्योग होने के लिए भारत में कोई अर्थक्षम घरेलू उत्पादक नहीं है। ऐसे आधारों पर वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- iv. यदि प्राधिकारी इस जांच को जारी रखने के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं तब घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को इस जांच में विश्लेषण के उद्देश्यों से कुल संबद्ध आयातों से अवश्य बाहर किया जाना चाहिए।

## **ख. गोपनीयता**

- v. प्रतिवादियों द्वारा कोई अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है। ये अनुरोध विधिवत् रूप से व्यापार नोटिस 10/2018 की अपेक्षाओं का पालन करते हैं।
- vi. इस याचिका के “व्यापार नोटिस स्थिति – कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान से एसिटोन के आयातों के मामले में निर्णायक समीक्षा जांच” भाग में, याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचना से “दो उत्पादकों से अधिक” मानक के बजाए एकमात्र उत्पादक/दो उत्पादक के मानदंड पर विचार किया है।
- vii. निम्नलिखित मानकों में घरेलू उद्योग निर्धारित रूप में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुआ है:

क. बिक्री की मात्रा

ख. प्रति इकाई बिक्री की लागत – निर्यात

ग. प्रति इकाई पीबीआईटी – घरेलू बिक्री

घ. कुल पीबीआईटी – घरेलू बिक्री

ड. एनआईपी की गणना

## **ग. आयातों का संचयन**

- viii. सऊदी अरब का जांच की अवधि में आयातों का 2.67 प्रतिशत, 2017-18 में 0.71 प्रतिशत है और पूर्व के वर्षों में सऊदी अरब से कोई आयात नहीं हुआ है। सऊदी अरब से आयात न्यूनतम स्तर पर हुआ है और उसका आंकलन पृथक् रूप से किया जाना चाहिए।

## **घ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटिन मार्जिन**

- ix. इस याचिका में समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य संबंधी आंकड़े नहीं हैं। आवेदकों ने इस तथ्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है कि क्या इन शुल्कों को ऐसे उच्च स्तर पर क्यों रखा गया है। इसके कारण अनुचित रूप से निर्धारित निर्यात कीमत कम हो गई है।
- x. कच्चे माल का मूल्यांकन इसके द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में जैसा कि मूल जांच में किया गया है, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

## **ड. क्षति**

- xi. संबद्ध आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में दोनों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- xii. सऊदी अरब का आयात मामूली मात्रा में हुआ है और इसका कुल आयात में 2.67 प्रतिशत का हिस्सा है।



- xiii. याचिकाकर्ताओं ने 2018 में दीपक फिनोलिक्स द्वारा संयंत्र की स्थापना के साथ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि की है।
- xiv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता का उपयोग 89 प्रतिशत पर है जो बहुत अधिक हद तक ज्यादा है और यह पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है।
- xv. घरेलू उद्योग जांच की अवधि में अपनी क्षमता को दुगुना करने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अपनी क्षमता के उपयोग को बहुत अधिक हद तक बढ़ाने में सक्षम रहा है। दीपक फिनोलिक्स के मामले में, यह उत्पादक वित्तीय 2018-19 की चौथी तिमाही में 100 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम रहा है।
- xvi. याचिकाकर्ता के संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में 2015-16 में 24,959 मी.टन से जांच की अवधि में 86,112 मी.टन अर्थात् 245 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- xvii. याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान बढ़े हुए उत्पादन के अनुपात में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में भी जांच की अवधि में तीन गुना वृद्धि हुई है।
- xviii. कुल पीबीआईटी में 2015-16 में 1,565 लाख भारतीय रुपए की हानि से जांच की अवधि में 1,352 लाख भारतीय रुपए के लाभ तक वृद्धि हुई है।
- xix. बिक्री की लागत तथा बिक्री की कीमत में गिरावट आई है लेकिन बिक्री की कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से कम है जिसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक लाभ मार्जिन प्राप्त हुआ है।
- xx. लगाई गई पूंजी में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का लगाई गई पूंजी पर लाभ में जांच की अवधि में पिछले वर्ष 2017-18 में नकारात्मक रहने के बाद वृद्धि हुई है।
- xxi. कर्मचारियों की संख्या में बढ़ी हुई क्षमता के अनुपात में क्षति की अवधि के दौरान 119 से 352 तक वृद्धि हुई है।
- xxii. प्रति दिन उत्पादकता में 71 मी.टन प्रतिदिन से 246 मी.टन/प्रति दिन तक बहुत अधिक वृद्धि बेहतर कार्य क्षमताओं को दर्शाता है।

#### च. क्षति की संभावना

- xxiii. कीमत निर्धारण संबंधी देखी गई प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि संबद्ध देशों की कीमत निर्धारण संबंधी नीति इन याचिकाकर्ताओं की कीमत निर्धारण संबंधी नीति को प्रभावित नहीं करता है।
- xxiv. पाटनरोधी शुल्क को जोड़े बिना सभी आयातों का पहुंच मूल्य सतत् रूप से बढ़ता आ रहा है।
- xxv. सऊदी अरब में उपयोग न की गई क्षमता केवल लगभग 15 प्रतिशत है जो 43,500 मी.टन है। प्रतिवादी के पास संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मालसूची नहीं है बल्कि इसके बजाय वे घरेलू बाजार और/अथवा तीसरे देश के निर्यात बाजारों में उसकी बिक्री करता है।
- xxvi. याचिकाकर्ताओं ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना को दर्शाने के लिए जांच की अवधि की बाद की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, यद्यपि जांच की अवधि के बाद की 6 महीने की अवधि के आंकड़ों की आसानी से आपूर्ति की जा सकती थी।
- xxvii. संबद्ध देशों से उत्पादकों ने तृतीय देश के बाजारों को स्थापित किया है जैसाकि यूरोप के मामले में हुआ है और इस कारण से इसको मानने का कोई साक्ष्य नहीं है कि इस प्रकार की बिक्री को भारतीय बाजार में फिर से भेजा जाएगा अथवा यह कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने पर भारत को निर्यातों में अचानक वृद्धि होगी।
- xxviii. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि क्षति की अवधि के दौरान सऊदी कायान की क्षमता में 37 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि यह सही नहीं है क्योंकि क्षमता में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है।

- xxix. उन्होंने यह दावा किया है कि कंपनी के पास मालसूची में वृद्धि हुई है। यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मालसूची में कमी आई है और वह संगत कारक है जिसका विश्लेषण किया ही जाना चाहिए।
- xxx. सऊदी अरब से आयात हमेशा मामूली रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए अपने निर्यातोन्मुखी करण के बावजूद यह भारत को मुश्किल से कोई निर्यात करता है। पाटनरोधी शुल्क 2015 में सऊदी अरब से आयात किए गए एसिटोन पर लगाया गया था। सऊदी अरब पिछले दशक के लिए भारत को एसिटोन की केवल लघु मात्राओं का निर्यात उन पर लगाए गए शुल्क पर विचार किए बिना करता रहा है।
- xxxii. शुल्क को लागू किए जाने के 5 वर्षों तक लागू किए जाने के साथ, व्यापार के माध्यमों को फिर से अनुरूप बनाया गया है और इसका अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादियों सहित सऊदी अरब के उत्पादक और निर्यातक शुल्कों को समाप्त किए जाने पर भारत में निर्यातों में अचानक उछाल लाने के लिए अपने व्यापार मार्गों में संशोधन करेंगे।
- xxxiii. बैकवर्ड एकीकरण के माध्यम से कच्चे माल की आसान उपलब्धता का अभिप्राय भारत में आयातों में वृद्धि नहीं है। इस तर्क पर विचार करते हुए, सऊदी अरब के उत्पादकों को हमेशा बैकवर्ड एकीकरण प्राप्त हुआ है लेकिन भारत को अधिक मात्राओं में कभी भी निर्यात नहीं किया है। उनकी पहुंच कीमत भी हमेशा अपेक्षाकृत अधिक सीमा पर रही है।
- xxxiv. क्षति की अवधि में, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और सऊदी अरब से तीसरे देशों तक आयातों के कारण हुई कीमत में कटौती नकारात्मक रही है।
- xxxv. तीसरे देशों में पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन का आंकलन निर्णायक समीक्षा जांच करने में प्राधिकारी के लिए न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई कार्य-पद्धति।
- xxxvi. सऊदी अरब के विरुद्ध चीन द्वारा किसी जांच की शुरुआत नहीं की गई है।
- xxxvii. संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने निम्न आयातों के कारण सऊदी अरब से एसिटोन पर पाटनरोधी शुल्क जांच समाप्त कर दिया है।

#### **छ. कारणात्मक संबंध**

- xxxviii. एक निवेशक के दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के पत्र के अनुसार, दूसरी तिमाही, 2019-20 के लिए, दीपक फिनोलिक्स ने यह उल्लेख किया कि कंपनी को हुई क्षति कई अन्य कारणों जिसका सऊदी अरब से आयातों से कोई संबंध नहीं है, के कारण हुई है:

क. वैश्विक स्तर पर धीमी आर्थिक वृद्धि

ख. ऑटोमेटिव और रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रियाकलाप का धीमा स्तर

ग. इस तिमाही के दौरान 14 दिनों के लिए इस संयंत्र को योजनाबद्ध

तरीके से बंद करना

- xxxix. एचओसीएल एक रुग्ण इकाई है और यह अपनी एसिटोन निर्माण इकाईयों के साथ प्रचालनबद्ध कठिनाईयों का सामना करता रहा है।
- xl. अन्य देशों को मिलाकर किए गए आयातों की मात्रा संबद्ध देशों विशेष रूप से सऊदी अरब से आयातों की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक हद तक उच्चतर है।

#### **ज. विविध**

- xi. प्राधिकारी ने पिछले दो दशकों (1999-2019) में विभिन्न देशों से आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में 10(दस) से अधिक व्यापार उपचार जांच की है।

- xli. यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा एसिटोन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है अतः यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है।
- xlii. घरेलू उद्योग के दावे के प्रतिकूल, विपणन के चैनल में सेबिक की भूमिका का कोई अन्य संकेत नहीं है। प्रश्नावली के उत्तरों में एक स्पष्ट फ्लो चार्ट दिया गया है और उसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

#### 124. घरेलू उद्योग की टिप्पणियों का सार

- i. एसिटोन की क्षमताओं से अधिक मांग केवल आयातों और न कि पाटन के औचित्य को ठहराएगा।
- ii. अनिवार्य आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को अपनी लागत कीमत और कच्चे माल की लागतों पर ध्यान नहीं देना है और विदेशी निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही पाटित कीमतों के अनुसार अपनी बिक्री कीमत तय करनी है।
- iii. डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेसटेट ने यह माना कि मांग आपूर्ति का अंतर निर्यातकों को इन वस्तुओं को पाटित करने का अधिकार नहीं देता है। यदि मांग को पूरा करना उद्देश्य है तक निर्यात उस कीमत पर किया जा सकता है जो सामान्य मूल्य के समतुल्य हो।
- iv. कार्य-पद्धति के रूप में प्राधिकारी ने कभी भी पूर्व की जांच परिणामों में मांग आपूर्ति के मुद्दे को संगत नहीं माना है जब अन्य कारकों ने यह स्थापित किया है कि घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश मांग और आपूर्ति के और ऊपर के अंतरों पर किया गया है।
- v. जांच की अवधि के बाद की अवधि से आगे के किसी आंकड़ों अथवा सूचना पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोविड-19 स्थिति केवल अस्थायी है। पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के संबंध में कोई भी निर्णय अस्थायी स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
- vi. कार्य-पद्धति के रूप में प्राधिकारी ने फिनोल सहित अपनी पूर्व की जांचों में जांच की अवधि के बाद 6 महीने के रूप में जांच की अवधि के बाद की अवधि को सीमित किया है। एसओपी मैनुअल का बिंदु 17.30 में भी जांच की अवधि के बाद की अवधि के रूप में जांच की अवधि के बाद के 6 महीने का उल्लेख है।
- vii. जैसाकि पूर्व में अनुरोध किया गया है, सेनिटाइजर को सरकार द्वारा आवश्यक मदों की सूची से हटाया गया है और इस कारण से आईपीए आधारित एसिटोन एक आवश्यक मद नहीं है।
- viii. चूंकि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में क्षति नहीं उठानी पड़ रही है अतः इस मामले के संबंध में निर्णय संभावना/खतरे की जांच के आधार पर लिया जाना अपेक्षित है। यह उपयुक्त नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में शुल्क में संशोधन किया जाए।
- ix. क्षति मार्जिन तभी संगत है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता हो कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में क्षति उठानी पड़ रही है। कार्य-पद्धति के रूप में प्राधिकारी क्षति के फिर से होने की संभावना के आधारों पर शुल्क की उसी मात्रा में विस्तार करते हैं। उसकी पुष्टि फिर से गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निरमा लिमिटेड बनाम संघ सरकार में की गई है।
- x. नियम 17(2) के अनुसार, क्षति की मात्रा प्रश्न तभी उठेगा जब केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति होने के निष्कर्ष पर पहुंचते हों।
- xi. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति के होने का पता नहीं चलता है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे क्षति मार्जिन का निर्धारण करें। वास्तव में जब कोई क्षति नहीं होती हो तब क्षति के मार्जिन का निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- xii. जैसा कि प्रकटन विवरण में नोट किया गया है, इस बात की संभावना है कि शुल्कों को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होगी। यह देखा जा सकता है कि वर्तमान जांच तथा पूर्व की जांचों में पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तरों से ऊपर थी।
- xiii. संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद बहुत अधिक मात्रा में जारी रहा है।

- xiv. प्रतिवादी निर्यातक उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार बहुत अधिक निर्यातोन्मुख हैं, भारत को उनका निर्यात जांच की अवधि अथवा जांच की बाद की अवधि के दौरान क्षति कारक कीमतों पर और पाटित कीमतों पर हुआ है, इसके अलावा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भारत की ओर संभावित विपणन पर भारत को छोड़कर तीसरे देशों को निर्यात क्षतिकारक होगा।
- xv. संगत दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रकटन का अनुरोध सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने हेतु किया जाता है, विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई पूरक सूचना का अगोपनीय पाठ, यदि कोई हो, विदेशी उत्पादकों को जारी किए गए कमियों का अगोपनीय पाठ, यदि कोई हो, उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रति और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति, प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोधों की प्रति, सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- xvi. उस अवधि जिसके लिए शुल्क लागू रहा है, इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए कोई संगत विचार नहीं है कि क्या आगे विस्तार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारियों ने अनेक अधिकार क्षेत्रों में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार बीस वर्षों से आगे तक किया है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस सं. 1/2013 के अनुपालन में जांच की अवधि की बाद की अवधि संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- xviii. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना डीजीटीआर की स्थापित कार्य-पद्धति के अनुसार है। इसयाचिका में सभी आवश्यक सूचना निहित है जिसकी एक प्रति अभी ज्ञात निर्यातकों और संबंधित दूतावासों को उपलब्ध कराई गई है।
- xix. जब जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस को इस याचिका के साथ पढ़ा जाना अपेक्षित है, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत संबंधी सूचना में कथित सूचना के न होने के कारण उनके साथ किए गए किसी पूर्वाग्रह को सिद्ध नहीं किया है।
- xx. क्षति की अवधि के दौरान उनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए संगत दिन/सप्ताह/माह/तिमाही/वर्ष के कारोबार पर विचार करना पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होगा।
- xxi. प्राधिकारी की विगत कार्य-पद्धति के अनुसार, एसिटोन और फिनोल जांचों सहित जहां कहीं भी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, प्राधिकारी ने उस शुल्क का विस्तार क्षति के फिर से होने की संभावना के आधार पर किया है।
- xxii. प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार, इस शुल्क को यूएस डालर (\$) के संबंध में लगाया जाना चाहिए। रुपए में बहुत अधिक हद तक अवमूल्यन हुआ है और इस कारण से, कृपया निश्चयात्मक शुल्क को यूएस डालर में व्यक्त किया जाए। भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव कच्चे मालों की लागतों, यूटिलिटी और अन्य लागतों पर पड़ा है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

- 125.. प्राधिकारी ने सभी संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रकटीकरण विवरण में पी ओ आई और पी ओ आई पश्चात अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का प्रकटीकरण किया है। प्रकटीकरण की प्रतिक्रिया में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी उचित रूप से जांच की गई है। जहां तक पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयातों का संबंध है, प्राधिकारी ने मै० दीपक फिनोलिक्स लि० और मै० एस आई ग्रुप इंडिया लि० द्वारा किए गए आयातों पर, जो कुल आयातों का 2 प्रतिशत थे, पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है। मै० दीपक फिनोलिक्स लि० ने इसका आयात बीज विपणन के प्रयोजन हेतु किया था। प्राधिकारी पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के मात्रा के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफों में धारित करते हैं कि आकलन करने के पश्चात, पी ओ आई का विश्लेषण वर्तमान ए

डी डी को जारी रखने का समर्थन नहीं करते किंतु एस एस आर पाटन और क्षति के संभावित विश्लेषण का औचित्य सिद्ध करते हैं जिसके अनुसार पी ओ आई पश्चात अवधि में भी विश्लेषण की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना का एक पी ओ आई -पश्चात विश्लेषण किया है जैसा कि समान परिस्थितियों में लगातार किया जाता रहा है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II (vii) की शर्तों में उल्लेखनीय क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच निम्नानुसार की है :-

**क. पिछली जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मूल जांचों और तदवर्ती पुनरीक्षा महत्वपूर्ण पाटन की विद्यमानता को निम्नानुसार प्रकट करती है :-

जांच की प्रकृति	पाटन मार्जिन (%)	संबद्ध देश
मूल जांच	32.77%	कोरिया गणराज्य
निर्णायक पुनरीक्षा जांच	15-25%	
मूल जांच	5-45%	सउदी अरब और ताईवान

प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई में, चार सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों, अर्थात् एस ए बी आई सी, टीपीसीसी, एफसीएफसी और कुम्हो के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिनके लिए पाटन पी ओ आई में न्यूनतम सीमा से निम्न बना रहा है, विशेष रूप से पी ओ आई - पश्च अवधि के दौरान पाटन की संभावना की जांच की है।

**ख. पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में आयातों का जारी रहना**

आयातों में हालांकि कमी आई है, किंतु भारत में पाटनरोधी शुल्कों के उद्ग्रहण के बावजूद पर्याप्त मात्रा में आयातों का आना जारी है जिस पर पाटन और क्षति की संभावित जांच के लिए विचार किया गया है, जैसाकि बाद के पैराग्राफों में कहा गया है।

**ग. संबद्ध देशों का निर्यातों का स्थिति निर्धारण**

प्राधिकारी ने अधिशेष क्षमता और उच्च निर्यात स्थिति पर पूर्ववर्ती पैराग्राफों में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे पर विचार किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 3 संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात स्थिति का अवलोकन निम्नानुसार किया गया है जो वृहत रूप से डी आई के दावे से सह संबंधित है :-

देश	उत्पादन के प्रतिशत के रूप में निर्यात
दक्षिण कोरिया	30-40
ताईवान	40-50
सउदी अरब	70-80

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि सिर्फ अधिशेष क्षमता के साथ, संबद्ध देश भारत को लक्ष्य नहीं बना सकते। प्राधिकारी धारित करते हैं कि यदि प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के साथ ऐसी स्थिति है तो ए डी शुल्क के जारी रहने से भारत के अलावा अन्य देशों को निर्यात का उनका व्यवसाय मॉडल प्रभावित

नहीं होगा। तथापि, ऐसे अन्य उत्पादक/निर्यातक हो सकते हैं जो निर्यातों के लिए भारत की ओर देखते हैं और इसलिए संभावित विश्लेषण के पश्चात ए डी शुल्क को जारी रखने की जरूरत हो सकती है।

#### घ. पाटन और क्षति पर संभावित विश्लेषण

प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान एस एस आर में, संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक पी ओ आई के दौरान भारत में पी यू सी के लगभग 83 प्रतिशत आयातों के लिए उत्तरदायी हैं। सहयोगी उत्पादकों ने अनुरोध किए जाने पर पी ओ आई - पश्चात डाटा भी उपलब्ध कराया है। भागीदारी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, भारत को संबद्ध देशों से पी ओ आई पश्चात की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिक हैं और इनका पाटन अथवा क्षति की संभवना के लिए विश्लेषण किया गया है जैसाकि न्याय संगत और उचित समझा गया था।

प्राधिकारी ने पाटन या क्षति की संभवना का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों के 6 महीनों के पी ओ आई पश्चात आंकड़ों को संदर्भित किया है। अपनाई गई इन आंकड़ों के विश्लेषण की अपनाई गई कार्य प्रणाली निम्नानुसार हैं :-

- क. पी ओ आई के दौरान ऋणात्मक/न्यूनतम सीमा से कम, जैसा भी मामला हो, पाए जाने पर पी ओ आई पश्चात अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मूल्यांकन किया गया है।
- ख. (i) यदि पी ओ आई पश्चात अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किए गए हैं अथवा भारत के लिए पी ओ आई - पश्चात अवधि में डी एम / आई एम भी न्यूनतम सीमा से कम/ऋणात्मक रहा है तो पाटन मार्जिन का भारत के अलावा तीसरे देशों को निर्यातों के लिए मूल्यांकन किया गया है, और  
(ii) तीसरे देशों भारत के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के संभावित विपथन पर विचार करते हुए पी ओ आई - पश्चात क्षति का मूल्यांकन किया गया है, यदि ऊँची कीमत की संभावना के कारण उत्पादकों/निर्यातकों को भारतीय बाजार अधिक आकर्षित लगता है। उपर्युक्त कार्य प्रणाली को लागू करने के द्वारा निम्नलिखित को धारित किया गया है:-

#### सउदी अरब

1. मै० सउदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एस ए बी आई सी) – एस ए बी आई सी से निर्यात पी ओ आई के दौरान लगातार पाटित और क्षति पूर्ण बने रहे जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पाटन और क्षति सारणी से प्रमाणित होता है।
2. मै० राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी (राबिघ) – पी ओ आई - पश्चात अवधि के दौरान भारत को राबिघ द्वारा किए गए निर्यात पाटित और क्षति कारक के रूप में नोट किए गए।
3. प्राधिकारी ने सउदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों की टिप्पणियां भी नोट की हैं कि उनके निर्यात बहुत नगण्य हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना इस जांच परिणाम में कहे गए अनुसार विभिन्न मापदंडों के संभावित विश्लेषण आधारित है। यदि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक भारत को निर्यात करने के इच्छुक नहीं हैं तो पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, घरेलू उद्योग को होने वाले संभावित पाटन और परिणामी क्षति से सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

#### ताईवान

1. मै० ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कारपोरेशन (टी पी सी सी) – पी ओ आई के दौरान टी पी सी सी द्वारा किए गए निर्यातों को पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पाटन सारणी में दर्शाए गए अनुसार पाटन के रूप में नोट किया गया है, पी ओ आई – पश्चात अवधि के दौरान तीसरे देशों से निर्यातों के भारत को संभावित रूप से विपथन को क्षतिकारक समझा गया है।

2. मै० फारमोसा केमिकल्स एंड फाइबर कारपोरेशन (एफ सी एफ सी) – जहां एफ सी एफ सी द्वारा पी ओ आई के दौरान भारत को किए गए निर्यातों को पाटित समझा गया है, तीसरे देशों (भारत के अतिरिक्त) से भारत को पी ओ आई पश्चात अवधि के दौरान एफ सी एफ सी के निर्यातों के संभावित विपथन का क्षतिकारक होने के रूप में अवलोकन किया गया है।

### **दक्षिण कोरिया**

1. मै० एल जी केम, लि० (एल जी) – पी ओ आई के दौरान एल जी के निर्यातों को गैर-पाटित और गैर-क्षतिकारक नोट किया गया है, तथापि, भारत के अतिरिक्त तीसरे देशों को किए गए निर्यातों को पाटित समझा गया है और भारत को उनका संभावित विपथन इंगित करता है कि वे क्षतिकारक होंगे।
2. मै० कुम्हो पी एंड बी केमिकल्स (कुम्हो) – पी ओ आई के दौरान भारत के मै० कुम्हो द्वारा किए गए निर्यात के रूप में पाटन नोट किए गए हैं और पी ओ आई – पश्चात अवधि के दौरान भारत के अतिरिक्त तीसरे देशों के निर्यात भारत को संभावित विपथन पर क्षतिकारक होंगे।  
प्राधिकारी मानते हैं कि उल्लिखित विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए पाटन और क्षति की संभावना है। प्राधिकारी ने गोपनीय संगणना में त्रुटि के संबंध में कुम्हो द्वारा किए गए निवेदन को नोट किया, जिसकी आगे पुनः जांच की गई तथा उचित रूप से सही किया गया।  
उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान किया गया उपचार असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों पर भी लागू होता है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती ए डी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जो इस जांच परिणाम के तदवर्ती पैराओं पर पिछली जांच के अनुसार उन पर लगाया गया था।

### **कारणात्मक संबंध**

126. आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और उनके ह्रासात्मक प्रभाव को नोट किया गया है। इसके अलावा कीमत प्रभावों के कारण याचिकाकर्ता वित्तीय हानियों का सामना कर रहे हैं।  
धारा 9क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति की संभावना तथा इसके बावजूद शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता के लिए यह जांच किया जाना अनिवार्य है कि क्या पुनरीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात किया गया है अथवा नहीं। ए डी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य मापदंड जो घरेलू उद्योग को क्षति में सहयोग कर सकते हैं, निम्नानुसार नोट किए गए हैं और उनका मूल्यांकन किया गया है जैसाकि नीचे प्रदर्शित किया गया है :-

- क. तृतीय देश- तृतीय देश से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लागू है या ए डी डी जांच के तहत उच्चतर कीमतों पर उपलब्ध हैं।
- ख. मांग- आधार वर्ष के बाद से विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।
- ग. निर्यात निष्पादन- घरेलू उद्योग ने नगण्य मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
- घ. प्रौद्योगिकी- विचाराधीन उत्पाद को उत्पादित करने की उत्पादन प्रक्रिया साथ ही प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में संभव विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
- ड. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन- याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना जो वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत सूचना है, पर सभी क्षति पैरामीटरों के संबंध में विचार किया गया है।

- च. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां :- कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति नहीं मौजूद है जो घरेलू उद्योग को क्षति में सहयोग कर सके।
- छ. खपत के पैटर्न में परिवर्तन :- पी ओ आई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बहुत से हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि चालू कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है जो पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग नहीं करता। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि कोविड महामारी के कारण 2020 के आरंभ में एसीटोन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि यह सेनिटाइजर्स बनाने के लिए एक इनपुट है और इसलिए ए डी शुल्क को इस उत्पाद पर जारी रखने की जरूरत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020 की पहली तिमाही के दौरान एसीटोन की कीमतें 600 डॉलर/मी. टन से 1000 डॉलर/ मी. टन की सीमा के भीतर थी और बाद में मई से जून, 2020 में यह 800 डॉलर/मी. टन की औसत रेंज पर थे। पी ओ आई - पश्चात की अवधि को सामान्यतः 1/4/2019 से 30/09/2019 अर्थात् 6 महीने के रूप में विचारित किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में जिनमें 6 महीने के बाद विकासों की जांच की जरूरत थी, 6 महीने से अधिक की पी ओ आई पश्चात अवधि पर विचार किया गया है। तत्पश्चात मामले में, परिस्थितियां वर्तमान तथ्यों की जांच की मांग करती हैं, जारी महामारी को भी ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने हाल ही में आयात आंकड़े भी प्राप्त किये हैं जैसाकि ऊपर कहा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसीटोन की कीमतें अभी भी उच्च सीमा में हैं, और जारी स्थिति और लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उद्योग पर हितबद्ध पक्षकारों की राय को ध्यान में रखते हुए, एक कीमत ट्रिगरिंग तंत्र की सिफारिश करना उचित समझा गया ताकि ए डी शुल्क को तभी लागू किया जाए जब आयात की कीमत स्थापित ट्रिगर कीमत से निम्न हो। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि तत्कालीन मामले में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है, जो पूर्ववर्ती पैराओं में स्थापित की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों की पिछली जांच में, ए डी शुल्क को क्षति मार्जिन के अनुसार संदर्भित किया गया था और वर्तमान परिदृश्य में चालू कीमतों को ध्यान में रखते हुए उचित ट्रिगर बिंदु और एक ऐसी कीमत का उल्लेख किए जाने की जरूरत है, जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति कारक न हो, जिसके लिए पी ओ आई के दौरान एन आई पी को मूल्यांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कीमत जो वर्तमान समय में क्षतिकारक न हो, एक ट्रिगर मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त और यथार्थवादी मानी जाएगी, क्योंकि पिछली जांचों की तुलना में वर्तमान एस एस आर में डी आई के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए प्राधिकारी 508 डॉलर/मी. टन (सी आई एफ) के रूप में एक ट्रिगर कीमत की सिफारिश करते हैं। ए डी शुल्क भुगतान किए जाने के लिए देय होगा यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की सी आई एफ आयात कीमत 508 डॉलर/मी. टन से कम है।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दक्षिण कोरिया से आयातों के मामले में, वर्तमान मामला दूसरी एस एस आर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में दक्षिण कोरिया से आयातों पर दूसरी एस एस आर शामिल है जबकि सउदी अरब और ताईवान के लिए यह प्रथम एस एस आर है। पाटन और क्षति की संभावना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी सउदी अरब, ताईवान और दक्षिण कोरिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान ए डी डी के विस्तार की सिफारिश करते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लिखित (पैरा 132) कीमत ट्रिगरिंग तंत्र के अधीन सी एन सं. 05/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 18.02.2015 और सी एन सं. 13/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 16.04.2015 के अनुसार अधिसूचित किया गया है।
129. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विद्यमान सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 07/2020 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 15.04.2020 को प्रतिस्थापित करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने के लिए अधिसूचना की तारीख से और 5 अधिक वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम (7) में संबद्ध देश



मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाने की सिफारिश करते हैं।

### शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	समूह का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि*	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2914 11 00	एसीटोन	ताईवान	कोई भी	फारमोसा केमिकल्स एंड फाइबर कारप.	86.10	यूएस डॉलर	मी. टन
2	-वही-	-वही-	ताईवान	कोई भी	ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कारपोरेशन	205.05	यूएस डॉलर	मी. टन
3	-वही-	-वही-	ताईवान	कोई भी	ऊपर क्रम सं. 1 और 2 के अतिरिक्त कोई भी	271.37	यूएस डॉलर	मी. टन
4	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देश के अतिरिक्त कोई भी देश	ताईवान	कोई भी	271.37	यूएस डॉलर	मी. टन
5	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कुम्हो पी एंड बी केमिकल्स इंक	79.75	यूएस डॉलर	मी. टन
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोई भी	एल जी केम, लि०	79.75	यूएस डॉलर	मी. टन
7	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोई भी	ऊपर क्रमसं. 5 और 6 के अतिरिक्त कोई भी	79.75	यूएस डॉलर	मी. टन

8	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देश के अतिरिक्त कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	79.75	यूएस डॉलर	मी. टन
9	-वही-	-वही-	सउदी अरब	कोई भी	सउदी कयान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी	132.98	यूएस डॉलर	मी. टन
10	-वही-	-वही-	सउदी अरब	कोई भी	राबिघ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी	203.85	यूएस डॉलर	मी. टन
11	-वही-	-वही-	सउदी अरब	कोई भी	ऊपर क्रम सं. 9 और 10 के अतिरिक्त कोई अन्य	203.85	यूएस डॉलर	मी. टन
12	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देश के अतिरिक्त कोई भी देश	सउदी अरब	कोई भी	203.85	यूएस डॉलर	मी. टन

\* ऊपर उल्लिखित ए डी शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब आयात की सी आई एफ कीमत 508 अमरीकी डॉलर/मी. टन से कम हो।

### **आगे की प्रक्रिया**

130. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसरण में, सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi , the 29th September, 2020

**(Final Findings)****Case No. ADD-SSR 03/2019****Subject: Sunset review Investigation concerning imports of “Acetone” originating in or exported from the Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan.**

**F. No. 7/9/2019-DGTR:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) thereof;

**Background of the case**

1. The original investigation on acetone was initiated by the Authority to examine the nature and extent of dumping and its impact on the performance of various economic parameters of the Domestic Industry with respect to imports of “Acetone” originating in or exported from Russia and Korea RP. The product under consideration for the purpose of investigation was “Acetone” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or PUC). The Authority vide Notification No. 14/13/2006 dated 14th March 2008 terminated the investigation concerning the subject goods, originating in or exported from Russia. Thereafter, Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/13/2006-DGAD dated 9th May 2008 recommending the imposition of definitive Anti-Dumping duty against imports from Korea RP. The definitive Anti-Dumping duty was imposed vide Notification No.75/2008-Customs dated 10<sup>th</sup> June 2008. A review investigation was carried out and the Authority recommended continued imposition of duty on imports from Korea RP. The Ministry of Finance extended definitive Anti-Dumping duty vide Notifications No. 05/2015-Customs (ADD) dated 18<sup>th</sup> February 2015 and was last amended, *vide* Customs Notification No. 07/2020- Customs (ADD) dated the 15<sup>th</sup> April 2020, the current duties are valid up to 14<sup>th</sup> October, 2020.
2. The original investigation concerning imports of the subject goods from the Taiwan and Saudi Arabia was initiated by the Authority. Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/16/2012-DGAD dated 22<sup>nd</sup> January 2015 recommending imposition of definitive Anti-Dumping duty which was imposed vide Notification No. 13/2015-Customs (ADD) dated 16<sup>th</sup> April 2015 and was last amended, *vide* Customs Notification No. 07/2020- Customs (ADD) dated the 15<sup>th</sup> April 2020, the current duties are valid up to 14<sup>th</sup> October, 2020.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping-duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Before the expiry of the said duties, SI Group India Pvt. Ltd, Hindustan Organics Chemical Limited and Deepak Phenolics Ltd, constituting the Domestic Industry (hereinafter referred to as the “Applicant” ) have filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “ Acetone ” originating in or exported from Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties.
5. The Authority on the basis of the prima facie evidence, considered the application for conducting review investigation in respect of imports from Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan and initiated sunset review investigation through Public Notice No. 7/09/2019-DGTR dated 07.08.2019 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan (hereinafter referred to as subject country) are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
6. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 14/13/2006-DGAD dated 9th May 2008 and No. 14/16/2012-DGAD dated 22<sup>nd</sup> January 2015 concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**A. PROCEDURE**

7. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority issued a notification dated 07.08.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject sunset review anti-dumping investigation.
- ii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassies and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- iii. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - a) Kumho P&B Chemical Inc
  - b) LG Chem, Ltd
  - c) Cowin Global Co. Ltd
  - d) HUMADE Corporation
  - e) Jisan Chemical Co., Ltd
  - f) OCI Corporation
  - g) Saudi Kayan Petrochemical Company
  - h) Rabigh Refining and Petrochemical Company
  - i) Chang Chun Plastics Co., Ltd.
  - j) Taiwan Prosperity Chemical Corporation
  - k) Formosa Chemicals and Fibre Corporation
- iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the respective country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the concerned Embassy along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.
- v. Further on the request of interested parties, the Authority extended the time period for submission of Questionnaire responses by the interested parties up to 14.10.2019.
- vi. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
  - a) Haresh Petrochem Singapore Pte. Ltd.
  - b) Formosa Chemicals & Fibre Corporation(FCFC)
  - c) Taiwan Prosperity Chemical Corporation(TPCC)
  - d) LG Chem Ltd.
  - e) Sumitomo Chemicals Asia Pte Ltd.
  - f) Vinmar International Limited.
  - g) Kumho P&B Chemicals
  - h) Humade Corporation
  - i) UNID Global Corporation
  - j) Samsung C&T Corporation
  - k) IMS Corporation
  - l) Canko Marketing Inc.
  - m) Saudi Basic Industries Corporation(SABIC)

- 
- n) Saudi Kayan Petrochemical Company(Saudi Kayan)
  - o) Saudi Asia Pacific Ltd.
  - p) Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a) M/s. C.J. Shah and Company
  - b) M/s. PCL Oil & Industries
  - c) M/s Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd
  - d) M/s Sonkamal Enterprises
  - e) M/s. Khetan Brothers
  - f) M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
  - g) M/s Acron Enterprises
  - h) M/s. Naiknavare Chemicals Limited
  - i) M/s. Paras Dyes & Chemicals
  - j) M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited,
  - k) M/s. United Phosphorus Ltd.
  - l) M/s. Resins & Plastic Ltd.
  - m) M/s. Kailash Polymers
  - n) M/s Centrum Metalics Pvt. Ltd.
  - o) M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
  - p) M/s. Meghdev Enterprises
  - q) M/s. Satguru International
  - r) M/s. High Polymer Labs Ltd.
  - s) M/s. Rainbow Colours & Chemicals
  - t) M/s Haresh Kumar & Co.
  - u) M/s Bleach Marketing Pvt. Ltd.
  - v) M/s Karmen International (P) Ltd.
  - w) M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
  - x) M/s NGP Industries Ltd.
  - y) M/s Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd.
  - z) M/s India Glycols Ltd.
  - aa) M/s Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
  - bb) M/s National Plywood Industries Ltd.
  - cc) M/s Kundan Rice Mills Ltd.
- viii. None of the importers or users have filed a response to the questionnaire.
- ix. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a) ASSOCHAM
  - b) FIEO
  - c) CII
  - d) FICCI

- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and period prior to it, and also the period of investigation, and Post POI. The Authority has relied upon the DGCIS data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions. The Authority also obtained data from DG-Systems for POI to correlate quantum of exports from specified exporters to validate the responses filed, to the extent feasible.
- xii. Further, keeping in view the submissions made regarding quantum and price of subject goods in Post POI especially the pandemic period, the Authority has further obtained the DGCIS import data.
- xiii. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 29.10.2019. Subsequently, fresh oral hearings were held on 06.12.2019 and 03.07.2020 in view of the change of the Designated Authority, which was attended by interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter.
- xv. On the spot verification of the information provided by the Applicant was conducted to the extent considered relevant by the Authority.
- xvi. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 01.04.2018 to 31.03.2019 (12 months). The examination of trends in the context of injury and the likelihood analysis covered the periods April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, the POI and also Post POI (6 months). The import price trends of subject goods even beyond the above Post POI period have been examined keeping in view the submission made by the interested parties on the circumstances emerging due to Covid Pandemic.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xx. A Disclosure Statement was issued on 24.7.2020 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 28.7.2020 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. ‘\*\*\*’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate for the POI (1/4/2018 to 31/3/2019) has been taken by the Authority as Rs.70.82 = 1 US\$. & for Post-POI (1/4/2019 to 30/9/2019) is referenced as Rs. 69.15 per USD.

## **B. Scope of product under consideration and like article**

### **B.1 Views of the Domestic Industry**

8. Following submissions were made by the domestic industry with regard to the product under consideration –
  - i. The product under consideration for the purpose of the present investigation is the same as in the earlier investigations.

- ii. The PUC is an organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used for manufacturing bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals.
- iii. Since the present investigation is a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation, no significant developments have taken place over the period. Therefore, the domestic industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to product under consideration.

## **B.2 Views of the other interested parties**

9. No submission has been made by any other producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

## **B.3 Examination by the Authority**

10. The product under consideration in the present investigation is “Acetone” (hereinafter also referred to as the “subject goods”). The subject product is an organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals.
11. The subject goods are classified under the category “Organic Chemicals” in Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 29141100 as per Indian Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primacy over the ITCHS as the same is indicative.
12. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigation. Moreover, none of the interested parties have made any quantified submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.
13. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules
14. With regard to “like article”, Rule 2(d) of the Rules provides as under:
 

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
15. After considering the information on record, the Authority is of the view that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration in terms of chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority is of the view that subject goods produced by the Applicant/ domestic industry are like article to the product under consideration which is imported from subject country in accordance with the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
16. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bishphenol A. Besides this, it is used in the manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate.
17. The Authority, therefore, confirms that the scope of the product under consideration in the present review remains the same as that of the original investigations.

## **C. Scope of domestic industry & standing**

### **C1. Views of the Domestic Industry**

18. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
  - i. The current application for the sunset review has been filed by M/s SI Group India Pvt. Ltd (SIG), M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) and M/s Deepak Phenolics Ltd (DPL) which account for 100% of the Indian production.

- ii. As per the information on record, the Applicant has imported the subject goods from the subject country although they are not related to any other producer/exporter of subject goods in the subject country or any importer in India. Further, the Applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods.
- iii. There is no legal bar in the law that the company who has commenced its production for only 6 months cannot file an application for continuation of antidumping duty despite the fact it is suffering injury.
- iv. The volume of imports made by SIG were very low in quantity and was under advance licence.
- v. In the last 22 findings of the Designated Authority in the matter of Acetone and Phenol, the Authority has considered SI Group as eligible domestic industry when they have imported the product under consideration under advance licence.
- vi. M/s Deepak Phenolics Ltd has imported insignificant quantity of product under consideration from subject countries before it started manufacturing the product concerned.
- vii. The imports by M/s Deepak Phenolics were made for seed marketing purposes. Once the company started manufacturing the product, the company has stopped its imports.

## **C2. Views of the other interested parties**

19. The opposing interested parties have made the following submissions:

- i. Two of the major producers (i.e. Deepak Phenolics and SI Group) have imported substantial quantities of product under consideration and unless the DGTR exercises its discretion to include these producers as part of the domestic industry they should not be included.
- ii. The imports made by petitioners accounts for about 5-15% of the total imports during the POI, and have been termed as “insignificant”. Saudi Arabia’s share in imports is lesser than 3%, and should not be considered significant.
- iii. SI Group has been importing the subject goods under advance licence without providing any tenable reasons for these imports.
- iv. Reasoning for imports by M/s Deepak Phenolics is absurd, since Acetone is an established product and does not require seed marketing. M/s Deepak Phenolics acts like any other trader in the market.
- v. M/s SI Group has a related party in Korea as per the financials, which has not been disclosed by the Petitioner.
- vi. HOCL is a sick unit and is under a restructuring process. It cannot be considered a viable domestic producer for the purposes of this investigation.
- vii. There is no viable domestic producers in India to constitute a domestic industry within the meaning of Rule 2(d) of the AD Rules. On such grounds, the current investigation should be terminated.
- viii. According to para no. 4.9.20 of the DGTR Manual interpreting Rule 2(b), domestic producers which import the subject goods are ‘ineligible’ to be considered as domestic industry unless the Hon’ble Designated Authority considers it fit in the overall interest of the investigation to ask for further information.
- ix. If the Authority exercises its discretion to continue the investigation, the imports made by the Domestic Industry must be excluded from the total subject imports for the purposes of analysis in this investigation. It is submitted that both Deepak Phenolics and SI Group must not be considered as eligible domestic industry and therefore, the review investigation should be terminated immediately.

## **C3. Examination by the Authority**

20. The application for sunset review was unitedly filed by M/s SI Group India Pvt. Ltd, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd. Apart from the Applicants, there is no other producer of the subject goods in India. As per the information available on record, the applicants accounts for 100 % of the total Indian production.
21. The Authority notes that the Applicants are not related (either directly or indirectly) to an exporter or producer of product under consideration produced in subject countries or an importer of product under consideration in India. Two of the applicant companies have imported the product under consideration, details of which are as follows:



Particulars	UoM	SI Group	Deepak Phenolics
Total Imports from Subject countries	MT	350	1,997
Imports in relation to Company's production	%	1.70	11.91
Imports in relation to Indian Production	%	0.41	3.55
Imports in relation to total Imports to India	%	0.30	6.88
Imports in relation to Demand	%	0.18	1.25

22. On the basis of information furnished, the Authority notes that the Applicant companies have made imports of the subject goods from the subject countries during the POI, however, the same are under duty free scheme, as well as for seed marketing purposes before the new plant entirely operational. The Authority has also addressed the issue later in response to the post disclosure comments.
23. In view of the above, the Authority holds that the production by the Applicant constitutes 'a major proportion' of total Indian production of the like product and that the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the Rules and constitutes 'Domestic Industry' (DI) in terms of Rule 2(b) of the Rules.

#### **D. CONFIDENTIALITY**

##### **D1. Views of the Domestic Industry**

24. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality claims of the exporters/importers and other interested parties are as follows:
- The petition is in compliance with the Trade Notice No 1/2013. The opposing interested parties have not provided any instances wherein the domestic industry has claimed excessive confidentiality except for costing formats A-L, and such costing information is by nature confidential and is not amenable to summarization.
  - Interested parties have claimed excessive confidentiality in violation of the Trade Notice no. 10/2018 dated September 7, 2018.
  - No meaningful summary has been provided by the interested parties in the non-confidential version of the questionnaire filed.
  - Authority is requested to reject the exporter questionnaire responses on the grounds of excessive confidentiality and violation of Trade Notice.

##### **D2. Views of the other interested parties**

25. Various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality claims of the Domestic Industry are as follows:
- Producer/exporters submitted that the petitioners have claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition. In response to Section-VI (Costing Information) of the Application, the petitioners have not furnished any information at all. The domestic industry has replied to all the questions raised in Part VI of the petition "*The costing formats A to L are enclosed as Annexure 5.6*". However, Annexures 5.6 has been claimed as confidential
  - Parameters listed in Rule 11, such as Unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided and analyzed in narrative of the petition, thereby lacking meaningful analysis.
  - Petitioners have not provided sufficient reasons as to why confidentiality was claimed and why summarization was not possible for certain information. The petitioners are required to show justification for their claim but have failed to do so. Accordingly, it is evident that the petitioners have not provided complete information as required under the Application
  - The Petitioners have claimed excessive confidentiality. Basic information such as individual sales, capacity, purchase, sales and accounting policy have been claimed confidential. Even the complete project report of DPL has been claimed confidential.
  - Costing information in Section VI has not been provided in an indexed manner.
  - Production quantities have been provided in the Annual Reports, however, the same has been claimed confidential contrary to the mandates for disclosure of information in public domain in Trade Notice 10/2018 dated September 7, 2018.

- vii. Further, as far as confidentiality is concerned, producers/exporters have provided all the information as per the trade notices and guidelines issued by the Authority from time to time whereas on the contrary, the Domestic Industry has itself not fulfilled the criteria of confidentiality in respect of the petition filed. The non-confidential version of the petition clearly violates the requirement of non-confidentiality as per the Trade Notice No 10/2018 dated September 7th, 2018 issued by the Director General.
- viii. In the “Trade Notice Status- Sunset Review Investigations in the matter of imports of Acetone from Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan” section of the Petition, the Petitioners have considered the Single Producer/Two Producer standard instead of the “More than Two Producers” standard from the Trade Notice.
- ix. As per the Trade Notice when there are multiple producers as petitioners, then certain data in the petition needs to be aggregated and provided in actual figures but in the present petition the same is provided in indexed form. Accordingly, it is evident that the petitioners have not provided complete information as required under the Application and they are claiming that we have made excessive confidentiality in our questionnaire filed.
- x. In the following standards, the Domestic Industry has failed to provide the required information in the prescribed manner:
  - a. Sales Quantity
  - b. Cost of Sales per Unit- Exports
  - c. PBIT per Unit- Domestic Sales
  - d. Total PBIT- Domestic Sales
  - e. Calculation of NIP

### **D3. Examination by the Authority**

26. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:

27. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as under:

*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

28. As regards the contention with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

### **E. Miscellaneous submissions**

#### **E1. Views of the Domestic Industry**

29. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:

- i. Producers/exporters from the subject countries have filed contradictory information in the Exporter questionnaire response.
- ii. Incomplete responses have been filed by exporters and producers from subject countries.
- iii. Authority is requested to reject the exporter questionnaire responses on the grounds of incomplete and contradictory information.
- iv. Investigation is not against increased imports, but dumped imports causing injury to the Domestic Industry. BIS licence is irrelevant in such a scenario.
- v. The increased demand and high pricing due to COVID-19 situation is temporary and decision may not be taken on the basis of a temporary situation.

## **E2. Views of the other interested parties**

30. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. Any imposition of ADD shall be improper and against overall interests of downstream industries.
- ii. Contrary to the claim of the Petitioners, initiation of sunset review is not mandatory even on a duly substantiated request, as upheld by Kesoram Rayon vs. The Designated Authority.
- iii. The application is not duly substantiated and should be dismissed on the basis of 'Lack of Injury', as no injury is established and 'Lack of Dumping', as acknowledged by Petitioners against Saudi Arabia.
- iv. Any imports made under the advance licence scheme should not be included in the assessment and determination of dumping and/or injury.
- v. Effect of expiry of duty would only be on duty paid imports such that the question of analyzing advance licence imports does not arise in the first place.
- vi. There should be no imposition since the imminent introduction of non-tariff barriers (BIS) will result in lower import volumes.
- vii. The mandatory BIS certification of Acetone imports is imminent and would stifle the ease of entry for exports of the products into India.
- viii. Costs should be allocated based on turnover ratio and not on production quantity ratio because of different output ratios and value of Acetone and Phenol.
- ix. Initiation notice is silent on the basis on dumping, injury and likelihood, and hence bad in law due to Rule 6(6).
- x. Investigation should be terminated since the notice of initiation was bad in law.
- xi. The Application is not as per the prescribed timelines under the Trade Notice No. 02/2017 as it was filed after the expiry of 270 day deadline, without proper justification.
- xii. The combined review has been filed only to circumvent the timelines of the Authority.
- xiii. As per Rule 6 of the AD Rules which applies, mutatis mutandis, to a review investigation, the Exporter submits that the Hon'ble Designated Authority is not required to initiate an investigation unless it is prima facie, based on duly substantiated evidence, determines that a review investigation is required to be initiated which the Petitioners have failed to do so.
- xiv. After Post-POI during 2020 a lot of developments with respect to rise in demand have taken place due to the COVID-19 pandemic for manufacturing of Acetone based Iso-Propyl Alcohol (IPA) both in India as well as in global market, further growth in demand is certain and likely to be continued in future also. The DI cannot cater the heightened demand supply gap.

## **E3. Examination by the Authority**

31. With respect to the argument of insufficient information provided by the domestic industry in the application filed by them, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the Applicant for the purpose of the present findings. The Authority notes that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses.
32. The argument that imports made under advance licence should be excluded from the total imports was examined. The Authority notes that imports/exports made under advance licence be considered to have not affected the

domestic industry or the price in the domestic market. An Advance licence/authorization holder has a choice either to import the inputs on a duty-free basis or procure the same from indigenous sources by using the mechanism of Advance Release Order. The purpose of injury analysis is to examine and capture the effect of dumped imports on the domestic industry. Therefore, it would not be reasonable to exclude the duty-free imports from the injury analysis. Further, import under advance licence is a benchmark for the price at which goods can be imported by a consumer without payment of taxes and duties. It would not be appropriate to consider that imports made under advance licence do not cause injury to the domestic industry. In fact, exporters and importers should not worry if their claim is that imports take place only under duty free scheme because in that case imposition of duty will not impact them at all.

33. As regards to the arguments that due to the introduction of mandatory BIS Licensing, no anti-dumping duties should be imposed. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to address the unfair imports. There is no bar in imposition of anti-dumping duty because of existence of BIS licence.

#### **Assessment of dumping – Methodology and Parameters**

#### **F. Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin**

##### **F1. Views of the Domestic industry**

34. The domestic industry inter alia submitted as follows:
- i. The Domestic Industry has provided ample evidence to support their claim of normal value and export price in their application for the purpose of the initiation.
  - ii. Dumping margin calculated for the subject countries is positive and significant.
  - iii. Authority is requested to consider the market price of benzene and propylene while determining elements of cost for computing normal value.

##### **F2. Views of other interested parties**

35. Following submissions have been made by the other interested parties:
- i. DA appears to have simply accepted the assertions of the DI regarding normal value, export price and consequent dumping margin.
  - ii. The evidence for calculation of Normal Value fails to meet the minimum evidentiary standards as the prices provided are for North East Asia and not Korea.
  - iii. The journals cannot be relied upon and considered as best information in meaning of Rule 6, as per *Dye Stuff Manufacturers Association v. Govt. of India*.
  - iv. Adjustments made for construction of normal value are not tenable under Annexure I of the Rules and are based on mere presumptions.
  - v. Adjustments made to Export price are abnormally high and unsubstantiated. The quote provided from the website is untrue and inflated by using invalid presumptions.

##### **F3. Examination by Authority**

##### **F.3.1 Determination of normal value and export price**

##### **Normal value computation**

36. Under section 9A (1) (c), of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
  - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

37. As regards the issue of normal value, export price and dumping margin, it is noted that the Authority had initiated the investigation based on the *prima facie* evidence given by the Domestic Industry. At the stage of initiation, the Authority had proceeded with the prices of subject goods based on information submitted by the Applicant based on the prices published in ICIS LOR due to non-availability of internal transactions of Singapore. However, for the purpose of this disclosure statement, the Authority has relied upon the verified data provided by the interested parties.
38. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the Petitioner. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in the subject countries to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their normal value and export price. Responses were received from the following –
- a) Haresh Petrochem Singapore Pte. Ltd.
  - b) Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC)
  - c) Taiwan Prosperity Chemical Corporation (TPCC)
  - d) LG Chem Ltd.
  - e) Sumitomo Chemicals Asia Pte Ltd.
  - f) Vinmar International Limited.
  - g) Kumho P&B Chemicals
  - h) Humade Corporation
  - i) UNID Global Corporation
  - j) Samsung C&T Corporation
  - k) IMS Corporation
  - l) Canko Marketing Inc.
  - m) Saudi Basic Industries Corporation
  - n) Saudi Kayan Petrochemical Company
  - o) Saudi Asia Pacific Ltd.
  - p) Rabigh Refining and Petrochemical Company
39. Since the above-mentioned companies have filed the questionnaire responses, the Authority has examined the request for determination of individual dumping margin based on verified data for these producers and have determined dumping margin, wherever appropriate.
40. In the absence of cooperation from the other producers/exporters in the subject country, the Authority has determined the normal value, on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of the Rules.
41. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of various producers/exporters of the subject country as follows:

#### **Cooperative Producers/Exporters from Taiwan**

##### **M/s. Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC-Taiwan)**

42. M/s. Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC) have filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI only.
43. FCFC has sold \*\*\* MT of the PUC in the domestic market and it has exported \*\*\* MT of the subject goods to India directly during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were 100%.
44. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the producer (FCFC). Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

**M/s Taiwan Prosperity Chemical Corporation (TPCC-Taiwan)**

45. M/s. Taiwan Prosperity Chemical Corporation have filed Exporter questionnaire in the formats prescribed for the POI only.
46. TPCC has sold \*\*\* MT of the PUC in the domestic market and it has exported \*\*\* MT of the subject goods to India directly during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, the profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value.
47. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the producer (TPCC). Accordingly, the ex-factory normal value is calculated as \*\*\* \$/MT and mentioned in the dumping margin table.

**Cooperative Producers/Exporters from South Korea****M/s LG Chem**

48. M/s. LG Chem have filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI only.
49. M/s LG Chem has sold \*\*\* MT of the PUC in the domestic market and it has exported \*\*\* MT of the subject goods to India directly during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, the profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value.
50. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the producer (LG Chem). Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

**M/s Kumho P&B Chemicals INC.**

51. M/s. Kumho has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI only. It has sold \*\*\* MT of the PUC directly in the domestic market and it exported \*\*\* MT of the subject goods to India directly as well as jointly with five traders during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, the profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value.
52. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the producer (Kumho). Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

**Cooperative Producers/Exporters from Saudi Arabia****M/s Saudi Kayan Petrochemicals Company**

53. M/s. Saudi Kayan Petrochemicals Company (SKPC) has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI only. It has not sold PUC in the domestic market, however, it has exported \*\*\* MT of the subject goods to India through its related exporters M/s Saudi Baic Industries Corporation (SABIC), exporter and M/s SABIC Asia Pacific Pvt. Ltd. (SAPPL), trader during the POI. Based on their response, it is noted that the producer has not made any domestic sales in their home country. Therefore, normal value based on domestic sales is not available. The producer has provided cost of production of PUC and the Authority, after due verification accepted the cost of production provided by them and added 5% profit to arrive at the normal value.

54. Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

**M/s Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)**

55. M/s. Petro Rabigh has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI only. It has not sold PUC in the domestic market, however, it has exported \*\*\* MT of the subject goods to India through its related trader M/s SUMITOMO Chemicals Asia Pt. Ltd. Singapore (SUMITOMO), Exporter during the POI. Based on their response, it is noted that the producer has not made any domestic sales in their home country. Therefore, normal value based on domestic sales is not available. The producer has provided cost of production of PUC and the Authority, after due verification accepted the cost of production provided by them and added 5% profit to arrive at the normal value.

56. Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

**Export price:**

**Cooperative Producers/Exporters from Taiwan**

**M/s. Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC-Taiwan)**

57. M/s. Formosa Chemicals & Fibre Corporation have filed Exporter questionnaires in the formats prescribed and also in addition furnished the required information by the Authority for the Post-POI. FCFC has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the subject goods to India directly during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI. It has also exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI. The producer has claimed port handling and related expenses including harbor facility charges, harbor shore tank handling charges, harbor management charges, credit cost, other port related expenses including documentation charges, notary charges, trade promotion charges etc. which are verified and accepted on table study by the Authority. Accordingly, the Net Export Price for the producer/exporter has been worked out as US\$ \*\*\*/MT for POI and US\$ \*\*\*/MT in Post-POI.

**M/s Taiwan Prosperity Chemical Corporation (TPCC-Taiwan)**

58. M/s. Taiwan Prosperity Chemical Corporation have filed Exporter questionnaire in the formats prescribed and also, in addition, furnished the required information by the Authority for the Post-POI. TPCC has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the PUC to India directly during the POI and did not export to India during the Post-POI. It has also exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI. The producer has claimed port handling and related expenses including harbor facility charges, harbor shore tank handling charges, harbor management charges, credit cost, other port related expenses including documentation charges, notary charges, trade promotion charges etc. which are examined on random sampling basis and accepted by the Authority during the table verification. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out as US\$ \*\*\*/MT for POI.

**Cooperative Producers/Exporters from South Korea**

**M/s LG Chem**

59. M/s. LG Chem have filed Exporter questionnaires in the formats prescribed and additionally furnished the required information by the Authority for the Post-POI. It has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the PUC to India directly during the POI and nil volume during the Post-POI. It has also exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI. The producer has claimed survey fee, customs brokerage fee, bank charges and credit cost which are examined on random sampling basis and accepted by the Authority during the table verification. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out as US\$ \*\*\*/MT for POI.

**M/s Kumho P&B Chemicals INC (South Korea)**

60. M/s. Kumho has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI and subsequently the required information also for Post-POI. It has exported total \*\*\* MT including through five traders. Producer has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the PUC to India directly and \*\*\* MT (CIF \*\*\* USD), \*\*\* MT (CIF \*\*\* USD), \*\*\* MT (CIF \*\*\* USD), \*\*\* MT (CIF \*\*\* USD), \*\*\* MT (CIF \*\*\* USD) through unrelated traders namely M/s Canko Marketing Inc, M/s Humade Corporation, M/s UNID Global Corz, M/s Samsung C&T Corp and M/s IMS Corporation respectively during the POI and \*\*\* MT, invoice value of \*\*\* USD during the Post-POI. It has also exported \*\*\* MT, CIF value of \*\*\* USD of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, invoice value of \*\*\* USD during Post-POI.

61. The producer has claimed Ocean freight, inland freight to ware house, ware house rent expenses, inland freight to port, port handling and related expenses, credit cost, inspector's charge, bank charges, duty drawback packing cost, loss of the trader etc. which are examined on random sampling basis and accepted by the Authority during

the table verification. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out as KRW \*\*\* /Kg for POI.

#### **Cooperative Producers/Exporters from Saudi Arabia**

##### **M/s Saudi Kayan Petrochemicals Company (SKPC)**

62. M/s. Saudi Kayan Petrochemicals Company (SKPC) has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI and subsequently the required information also for Post-POI. It has exported \*\*\* MT of the subject goods to India through its related trader-exporters M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) and M/s SABIC Asia Pacific Pvt. Ltd. (SAPPL) during the POI. Producer has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the PUC to India. Nil export was made during the Post-POI to India. It has exported FOB value of \*\*\* USD of volume \*\*\* MT of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI.
63. The producer/exporter has claimed Ocean freight, port handling and related expenses, marketing fee, demurrage, customs expenses, bank charges, etc. which are examined on random sampling basis and accepted by the Authority during the table verification. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out as US\$ \*\*\* /MT for POI.

##### **M/s Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)**

64. M/s. Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) has filed Exporter questionnaires in the formats prescribed for the POI and subsequently the required information also for Post-POI. It has exported \*\*\* MT of the subject goods to India through its related trader i.e. M/s SUMITOMO Chemicals Asia Pt. Ltd. Singapore (SUMITOMO) and further to unrelated exporters i.e. M/s Vinmar \*\*\* MT and remainder to M/s Haresh Petrochem Singapore Pte Ltd. during the POI. Thus the Producer has exported \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD of the PUC to India during the POI. \*\*\* MT export was made during the Post-POI to India. It has exported FOB value of \*\*\* USD of volume \*\*\* MT of the subject goods to third countries during the POI and \*\*\* MT, FOB value of \*\*\* USD during Post-POI.
65. The related trader M/s SUMITOMO has claimed shipping cost, credit cost, other expenses along with losses made which are examined on random sampling basis and accepted by the Authority during the table verification. Accordingly, the Net Export Price for this producer/exporter has been worked out as US\$ \*\*\* /MT for POI and US\$\*\*\*/MT for Post POI.

#### **Normal value/Export Price for all other producers/exporters from subject countries**

66. The recommendation regarding non cooperative producers/exporters have been made in the later paras.

#### **Determination of Dumping Margin**

67. Based on normal value and net export price, the dumping margin on weighted average basis for each co-operating producers is determined as follows:

##### **POI**

Sl. No	Country	Producer	Normal Value (USD/MT)	Net Exp. Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
1	Taiwan	M/s. Formosa Chemicals	***	***	***	***	0-10
2		M/s Taiwan Prosperity	***	***	***	***	0-10
3	Korea RP	M/s Kumho	***	***	***	***	0-10
4		M/s LG Chem	***	***	***	***	Negative
5	Saudi Arabia	M/s Saudi Kayan	***	***	***	***	180-200
6		M/s Rabigh Refining	***	***	***	***	Negative



**DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****Views of the Domestic industry**

68. Following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

- i. Demand for the subject goods has increased over the injury period.
- ii. Production and sales of the Domestic Industry have increased due to the addition of new capacities by Deepak Phenolics in the Period of investigation.
- iii. Imports have declined in absolute terms due to the addition of new capacities. Earlier, there was demand-supply gap in India and hence imports were necessary.
- iv. Decline in imports in the recent period is not a reduction in dumping, but response to fresh capacities in the Country.
- v. Volume of non-essential imports have increased by a big margin.
- vi. Current import levels are much higher than the essential and required imports in the country due to the marginal demand supply gap.
- vii. There is a very significant decline in the import price. Further, the decline is far beyond the decline in the costs due to decline in prices of basic inputs.
- viii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and are depressing the prices of domestic industry in the market.
- ix. The selling prices were below cost during the entire injury period. The domestic industry started facing severe price decline even within the POI.
- x. Imports are resulting in price underselling.
- xi. The Domestic Industry has been in losses throughout the injury period. The domestic industry is unable to earn profits due to presence of dumped products in India.
- xii. Inventories with the Domestic Industry have been significant throughout and have increased significantly in the period of investigation.
- xiii. Injury to Domestic Industry is because of dumped imports. Causal link exists between dumped imports and injury of Domestic Industry.
- xiv. Annual Reports and balance sheet of the Domestic industry are for overall operations and not just the domestic operations of the product under consideration.

**Views of the Other Interested Parties**

69. Following submissions have been made by the other interested parties -

- i. Domestic sales, production, market share, productivity per day, return on investment, PBIT etc of Domestic Industry is increased and Domestic Industry has not suffered any material injury due to imports. Positive growth can be seen in all parameters.
- ii. Imports from subject countries have declined by 61%, and from Taiwan have declined by 85%, and therefore are not putting any volume pressure on the Domestic Industry.
- iii. Cost and Selling price of the Domestic Industry have declined, whereas the Landed price from subject countries has increased. There is no price effect from the imports.
- iv. Price undercutting is to be seen in relation to profitability. The price undercutting from Taiwan is positive, but the PBIT has improved sharply.
- v. Market share of the subject countries has declined and is the lowest in the POI, whereas that of the Domestic Industry has increased and is the highest in the POI.
- vi. No. of employees and productivity has increased, whereas mysteriously the wages have remained the same. The number of employees increased from 119 to 352 during the injury.
- vii. There is no causal link since the Petitioners are enjoying growth in profits notwithstanding the alleged price undercutting and price suppression;
- viii. Saudi Arabia accounts for less than 3% of total imports, which is below the de minimis threshold, whereby the impact of such imports would be minimal, if any.

- ix. The selling price has decreased by 12 indexed points whereas the cost of sales decreased by 29 indexed points, thereby showing no effect of suppression or depression.
- x. Production, utilization, sales volume and capital employed have all evidenced a positive trend in the injury period as well as the POI which clearly indicates absence of injury to the domestic industry. Capacity utilization is at 89% current value, which is the highest point during POI.
- xi. Injury is because of higher interest and depreciation costs, which are higher only because of high finance and depreciation values of the (newly set up) plant by Deepak Phenolics Ltd.
- xii. There must be an analysis of material retardation instead of material injury for M/s Deepak Phenolics Ltd.
- xiii. Determination of NIP based on data of one (DPL) domestic producer would be in gross violation of Annexure III of AD Rules.
- xiv. Despite anti-dumping duties in force, HOCL was classified as a sick company and there was no operation till 2015-16.
- xv. Petition shows how imports from Korea have stopped after Nov, 2018 since DPL has started commercial production. Direct exports from KPB have completely stopped too.
- xvi. Import volumes from Korea have evidently reduced significantly over the injury period, by 39% and in the POI by 11%, hence there are no adverse volumes showing volume effect. Post commercial production by DPL, imports from Korea are negligible.
- xvii. In a recent Safeguard application for Phenol, positive ROCE figures were reported for the Applicants in 2019-19. The figures cannot be different for Acetone and Phenol.
- xviii. The DI was making constant improvements even before the introduction of DPL, so all the positive growth cannot be attributed to commencing of production by DPL in November, 2018.
- xix. Cash flow has always been positive apart from the POI, which can also be attributed to the huge capital flow made towards the new constituent.
- xx. DA is requested to examine the effect of crack spread on the profitability of the DI.
- xxi. Phenol and Acetone are produced together, and all demand supply and production of Acetone is linked to Phenol, since Phenol is the pre-dominant product.
- xxii. There is demand- supply disparity for the subject goods and to meet the requirements, goods is imported in significant quantities.
- xxiii. In 2016, a SSR investigation conducted against the imports of subject goods from Japan and Thailand but does not result in extension of AD Duty as it would not help in revival of production of HOCL.
- xxiv. The import is necessitated by substantial demand- supply gap.
- xxv. As per market intelligence reports, the demand of subject goods from different industries is likely to grow at a rate of 11% till 2022.

#### **Examination by Authority**

70. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
71. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
72. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product

in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

73. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
74. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
75. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before examination of the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

**i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption**

76. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand for the product under consideration is given below:

Demand	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI(A)
Sales of Domestic Industry	MT	25,428	26,041	32,306	83,134	1,44,475
Trends						
Imports from Subject countries	MT	94,173	56,869	42,257	36,510	15,646
Import from other countries attracting ADD	MT	24,080	10,167	14,539	35,758	36,776
Import from Other Countries	MT	20,096	68,801	89,811	44,432	38,938
Total Demand	MT	1,63,778	1,61,879	1,78,912	1,99,834	2,35,835

77. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased over the injury period.

**ii. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry**

**Import volume and Market Share**

78. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The table below summarizes the factual position with regard to import volumes and market share:-

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POST POI (A)
Import Volumes						
Subject Countries	MT	94,173	56,869	42,257	36,510	15,646
Other Countries attracting ADD	MT	24,080	10,167	14,539	35,758	36,776
Other Countries		20,096	68,801	89,811	44,432	38,938
Total Imports	MT	1,38,350	1,35,838	1,46,606	1,16,700	91,380
Market Share in Imports						
Subject Countries	%	68.07	41.87	28.82	31.39	17
Other Countries attracting ADD	%	17.40	7.48	9.92	30.64	40
Other Countries	%	14.53	50.65	61.26	38.07	43

Imports from Subject Countries in relation to						
Production	%	377	213	129	42	9.94
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	56	34	11	3
Indian Consumption	%	58	35	24	19	6.32
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	41	32	11

79. Based on the table above the Authority notes that the imports from subject countries have declined over the injury period. The Applicants submitted that the imports from the subject countries have declined due to anti-dumping duty in existence and fresh capacities in the market.

**i. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry**

**a. Price Undercutting**

80. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the subject goods. The information for the Period of investigation is as follows-

Particulars	Unit	Saudi Arabia	Taiwan	Korea RP
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***
Price undercutting	%	10-15%	5-10%	0-5%

81. From the above, the Authority notes that the landed price of imports of subject goods from subject countries is below the net selling price of the domestic industry. The imports from subject countries are undercutting the selling prices of domestic industry.

**b. Price Suppression/ Depression**

82. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI(A)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	101	64	58
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	116	115	88	71
Landed Value	Rs/MT	43,133	46,215	53,157	49,987	32,246
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	123	116	75

83. The Authority notes that the import price of the product under consideration is neither depressing nor suppressing the prices of the domestic industry during the period of investigation. However, in the post period of investigation, the imports price are depressing the prices of the domestic industry.

**ii. Economic Parameters relating to the Domestic Industry**

84. Annexure II to the AD Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry,

including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

85. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

**a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume**

86. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post-POI(A)
Installed Capacity	MT	47,140	47,140	47,140	97,140	1,67,140
Trend	<i>Indexed</i>	100	100	100	206	355
Production	MT	24,959	26,696	32,872	86,112	1,57,335
Trend	<i>Indexed</i>	100	107	132	345	630
Capacity Utilisation	%	53	57	70	89	94
Trend	<i>Indexed</i>	100	107	132	167	177
Domestic Sales Volume	MT	25,428	26,041	32,306	79,972	1,56,122
Trend	<i>Indexed</i>	100	102	127	315	614

87. The Authority notes the Capacity with which the Domestic Industry increased in the Period of investigation. This is due to commencement of production by Deepak Phenolic Ltd. in November 2018. Consequently, the production and sales of the Domestic Industry has increased. The same trend is observed in Post POI period.

**b) Market Share in Demand**

The market share of the domestic industry moved as shown below:

Market Share in Demand	Units	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI
Sales of Domestic Industry	%	16	16	18	41	63
Sales of subject countries	%	57	35	24	18	6
Import from other countries attracting ADD	%	15	6	8	18	15
Import from Other Countries	%	12	43	50	23	16
Total Demand	%	100	100	100	100	100

88. It is noted that the market share of the domestic industry has increased in the period of investigation whereas the market share of the subject countries has declined. This is due to the addition of capacities by the Domestic Industry in the Period of investigation and anti-dumping duty in force. The market share of DI has increased in Post POI as well.

**c) Profitability, return on investment and cash profits**

89. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	104	101	64	59
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	116	115	88	71
Profit / (Loss)	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(53)	(42)	38	(9)
Profit / (Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(51)	(52)	123	(56)
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	2	(10)	297	89
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	(49)	(52)	151	(2)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	(100)	3	(12)	109	14

90. The Domestic Industry is suffering losses till 2017-18 and thereafter, the performance of the Domestic Industry has improved during period of investigation. PBIT, cash profits and Return on capital employed has also increased during period of investigation. During Post POI, the above three parameters have shown down turn.

**d) Inventories**

91. Inventories with the Domestic Industry is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post POI
Average Stock	MT	422	514	1,125	4,714	5,939
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	122	266	1,117	1407

92. It is seen that inventories with the Domestic Industry have increased over the injury period. The inventories are very high in the period of investigation, and further increased during the post period of investigation.

**e) Employment, wages and productivity**

93. Performance of the Domestic Industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	Post PoI(A)
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	132	346	654
Employment	Nos	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	94	92	296	145
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	100	100	153

94. On the basis of the above, the Authority notes that the levels of employment and productivity have increased in the period of investigation due to the addition of Deepak Phenolics in the period of investigation. Wages paid have also shown an increase. This trend continues in post POI.

**f) Magnitude of Dumping**

95. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis shows that the dumping margin in case of 4 cooperative producers/exporters is positive in POI and for the other two producers/exporters is positive on the basis of likelihood analysis during Post POI.

**g) Ability to raise Capital Investment**

96. There is no verifiable information presented by the Domestic Industry and neither available on records that can imply that future investment in the sector can be marred by the presence of dumped imports from subject countries.

**h) Magnitude of Injury and injury margin**

97. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

**POI**

S.No.	Country	Producer	NIP (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1	Taiwan	M/s. Formosa Chemicals	***	***	***	***	Negative
2		M/s Taiwan Prosperity	***	***	***	***	Negative
3	Korea RP	M/s Kumho	***	***	***	***	Negative
4		M/s LG Chem	***	***	***	***	Negative
5	Saudi Arabia	M/s Saudi Kayan	***	***	***	***	20-40
6		M/s Rabigh Refining	***	***	***	***	Negative

**LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY****Views of the Domestic Industry:**

98. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

- i. An analysis of exporter questionnaire responses shows likelihood of continuation of dumping and consequent injury.
- ii. Dumping margin determined in all previous investigations relating to the product has been positive.
- iii. Significant imports in presence of anti-dumping duty showing likelihood of increased imports in the event of cessation of duty.
- iv. Excess production capacities held by the producers in the subject countries are significant.
- v. Unutilized capacities with the exporters are concerning.
- vi. Freely disposable capacities with the foreign producers show likelihood of increased imports in the event of cessation of duty.
- vii. Export orientation of producers and exporters in subject countries is very high. The producers are predominantly export oriented, and India market is important to their interests.
- viii. Further expansions by producers in the Subject countries despite a glut in the market.
- ix. Easy availability of feedstock for producers makes them independent of cost and raw material availability of the market,
- x. Producers are habitual of dumping, as can be seen from the third country dumping margins.
- xi. Overcapacity in Asian Countries, Self-sufficiency of Chinese industry have led to oversupply of Acetone in the market. This has significantly changed the market scenarios.
- xii. Shifting pattern of trade in Acetone, whereby the source of the imports into India changes in tandem with the imposition and cessation of anti-dumping duties.
- xiii. Third country anti-dumping duty investigations sees the closure of certain markets for the subject countries.
- xiv. India is a lucrative market for the exporters from subject countries, and no other market offers such prospects, as the Indian market.

**a. Excess production capacities held by producers in subject countries**

99. Domestic industry has furnished evidences showing capacities with the subject country's producers as given below-

Sr. No.	Exporter	Country	Capacity in Tons
A1	LG Chemicals	Korea RP	3,60,000
A2	Kumho P&B	Korea RP	4,20,000
A3	Total Korea RP		7,80,000
A4	Demand	Korea RP	5,42,000
A5	Excess capacities	Korea RP	2,38,000
B1	Saudi Kayan Petrochemicals	Saudi Arabia	1,40,000
B2	Petro Rabigh	Saudi Arabia	1,50,000
B3	Total Saudi Arabia		2,90,000
B4	Demand	Saudi Arabia	59,358
B5	Excess capacities	Saudi Arabia	230,642
C1	Chang Chun Plastics	Taiwan	1,86,000
C2	Formosa chemicals and fibre corporation	Taiwan	2,50,000
C3	TPCC	Taiwan	2,20,000
C4	Total Taiwan		6,56,000
C5	Demand	Taiwan	3,25,000
C6	Excess capacities	Taiwan	3,31,000

100. The Authority notes that the exporters in subject countries have excess capacities, which can easily cater to the entire demand in India.

**b. Unutilized capacities with the exporters**

101. The data with evidences submitted by the Domestic Industry regarding above is as under;

Korea RP					
Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
Production	MT	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
Unutilized capacities	MT	89,250	1,17,000	1,17,000	1,17,000

Saudi Arabia					
Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	1,40,000	1,40,000	1,40,000	2,90,000
Production	MT	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
Unutilized capacities	MT	21,000	21,000	21,000	43,500



Taiwan					
Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
Production	MT	5,76,490	5,84,229	5,65,323	5,68,484
Unutilized capacities	MT	79,510	71,771	90,677	87,516

102. It would be seen that the exporters in the subject countries hold significant unutilized capacities. This shows that subject goods may continue to enter India.

**c. Freely disposable capacities with the foreign producers**

103. The data submitted with evidences for freely disposable production capacities as below;

**Korea**

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
Production	MT	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
Unutilized capacities	MT	89,250	1,17,000	1,17,000	1,17,000
Exports	MT	1,94,849	2,36,153	2,87,449	3,28,427
Freely Disposable Capacity	MT	2,84,099	3,53,153	4,04,449	4,45,427

**Saudi Arabia**

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	140,000	140,000	140,000	290,000
Production	MT	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
Unutilized capacities	MT	21,000	21,000	21,000	43,500
Exports	MT	64,855	54,707	65,297	1,87,142
Freely Disposable Capacity	MT	85,855	75,707	86,297	2,30,642

**Taiwan**

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
Production	MT	5,76,490	5,84,229	5,65,323	5,68,484
Unutilized capacities	MT	79,510	71,771	90,677	87,516
Exports	MT	2,51,692	2,59,473	2,40,554	2,43,665
Freely Disposable Capacity	MT	3,31,202	3,31,244	3,31,231	3,31,181

104. It would be seen that the subject countries have freely disposable capacity which can easily cater to entire demand in India. Moreover, the exports are likely to be diverted to India in the event of cessation of Anti-dumping duties.

**d. Export orientation of producers and exporters in subject countries**

105. The data with evidences for export orientation are as under;

106. Summarized position of exports from Korea is as follows -

Year	Value (Rest of World)	
	US\$ (million)	Rs. Crores
2008	100.24	693
2009	66.01	457
2010	68.31	473
2011	101.60	703
2012	78.54	543
2013	170.92	1,182
2014	239.44	1,656
2015	106.62	738
2016	127.32	881
2017	203.72	1,409
2018	199.13	1,378

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	5,95,000	7,80,000	7,80,000	7,80,000
Domestic demand	MT	5,42,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000
Production	MT	5,05,750	6,63,000	6,63,000	6,63,000
Exports	MT	1,94,849	2,36,153	2,87,449	3,28,427
Exports as a % of					
Capacity	%	33%	30%	37%	42%
Demand	%	36%	44%	53%	61%
Production	%	39%	36%	43%	50%

107. Summarized position of exports from Saudi Arabia is as follows -

Year	Value (Rest of World)	
	US\$ (Million)	Rs. Crore
2011	31.29	217
2012	48.68	337
2013	40.58	281
2014	62.54	433
2015	38.13	264
2016	26.11	181
2017	63.96	443
2018	121.96	845

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	1,40,000	1,40,000	1,40,000	2,90,000
Domestic demand	MT	56,226	65,445	54,654	59,358
Surplus capacities	MT	83,774	74,555	85,346	2,30,642
Operating rates	%	85	85	85	85
Production	MT	1,19,000	1,19,000	1,19,000	2,46,500
Exports	MT	64,855	54,707	65,297	1,87,142
Exports as % of capacity	%	46%	39%	47%	65%
Exports as % of demand	%	115%	84%	119%	315%
Exports as % of production	%	55%	46%	55%	76%

108. Summarized position of exports from Taiwan is as follows -

Year	Value (Rest of World)	
	US\$ (million)	Rs. Crores
2011	238	1,649
2012	190	1,320
2013	209	1,448
2014	191	1,327
2015	115	799
2016	117	813
2017	160	1,110
2018	140	970

Particulars	UOM	2015	2016	2017	2018
Capacities	MT	6,56,000	6,56,000	6,56,000	6,56,000
Domestic demand	MT	3,25,000	3,25,000	3,25,000	3,25,000
Surplus capacities	MT	3,31,000	3,31,000	3,31,000	3,31,000
Operating rates	%	85	85	85	85
Production	MT	5,57,600	5,57,600	5,57,600	5,57,600
Exports	MT	2,51,692	2,59,473	2,40,554	2,43,665
Exports as % of capacity	%	38%	40%	37%	37%
Exports as % of demand	%	77%	80%	74%	75%
Exports as % of production	%	45%	47%	43%	44%

109. It can be seen from the above information that the producers in the subject countries are export focused and have a high degree of export orientation. The Capacities and production in the subject countries are surplus in nature due to the relatively low demand for the product under consideration in the subject countries.

**e. Further expansions by producers in Subject countries**

110. It is submitted that evidences show both the Korean producers, Kumho and LG Chem have plans for expansions and their projected capacities are estimated to increase in 2020. The increase in capacities by subject country producers is a strong indicator of likelihood of dumping on cessation of AD Duty.

**f. Easy availability of feedstock**

111. Domestic Industry has submitted evidences that show producers in Saudi Arabia are backward integrated for the subject goods. Petitioners also submit, that such a setup helps the producers mitigate the negative affect of fluctuations in raw material pricing and availability. Such circumstances may give subject exporters and added advantage.

**g. Third country dumping**

112. Petitioners have provided calculation with regards to pricing behavior of the subject country exporters in third countries. It is noted that the exports from subject countries reveal dumping practices in other countries as well. It is likely that the exporters will continue to dump the subject goods into India.

**h. Overcapacity in Asian Countries**

113. At present the world is faced with over capacity with an exception of India. Evidences submitted show overcapacities in all other countries in Asia for the subject goods. The overall market situation for product under consideration is relevant in the examination of likelihood of dumping and injury.

**i. Shifting pattern of trade in Acetone**

114. India is the preferred destination for export of subject goods. Analysis of the source of import in accordance with the history of past investigation shows that the imports of subject goods has a shifting pattern of trade. Imports come into India from countries where duties expire.

**j. Trade Remedial investigation by other countries**

115. China PR imposed an anti-dumping duty on imports of Acetone in 2008, the same were extended in 2014 and the review investigation for continued imposition was initiated in 2019. The investigation is against imports from South Korea and Taiwan. The Authority notes that such investigations show the tendencies and practices of subject country exporters to dump goods in third countries as well and the likelihood of diversion of exports to India.

**k. Self-sufficiency of Chinese industry**

116. Records evidences show that China has a big demand for the subject goods and imports from the subject countries. As per the information submitted by the Petitioners, the capacities in China PR are increasing by 1.2 Million MT, which shall affect the imports from the subject countries. Such circumstances may lead to increase in imports into India due to diversion from China PR.

**l. Over supply of Acetone**

117. Capacities all over the world for Acetone are abundant whereas the demand outside India has not grown with the same extent. The subject goods face an oversupply and consequently the import price into India has declined severely. It is likely that the over-supply will divert the subject goods into India due to abundant demand in the country.

**m. India is a lucrative market for the exporters from subject countries**

118. The Petitioners submit that India is the most lucrative market for the exporters from subject countries, on account of following factors;

- i. When the world is faced with overcapacity for Acetone, India has increasing demand. The major acetone producing countries have become self-sufficient and therefore the exporters are likely to increase their exports to a country like India where there is increase in demand.
- ii. China and US, being the major market for the subject countries, have initiated or imposed measures, resulting in these markets not being attractive for the exporters. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exports are likely to shift to India.
- iii. The producers from subject countries have historically fetched better prices in India as compared to rest of the world, and therefore, India has always been a lucrative market for the producers.

- iv. With other countries attracting anti-dumping duty in India, in the event of cessation of anti-dumping duty, Indian market will become the most lucrative market for its freely disposable capacities. This is further established through shifting patterns of imports into India with levy/non levy of anti-dumping duty.
- v. The producers in Korea, Saudi Arabia and Taiwan are habitually dumping the product which is evident from US and China investigations and current dumping margins in India and third countries. In the event of cessation of anti-dumping duty, the subject country exporters are likely to export the product to India at dumped prices.

#### **Views of the Other Interested Parties**

119. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –

- i. The likelihood of injury cannot be established as the post-POI data was not provided, per the Authority in *Viscose Filament Yarn from China PR*.
- ii. There is no likelihood of continuation or recurrence of injury as there was no verifiable evidence, per the Authority in *Plain Gypsum Plaster Boards from China PR, Indonesia, Thailand & UAE*.
- iii. No ADD has been imposed by other countries on imports from Saudi Arabia.
- iv. Allegations of high export orientation & price attractiveness of Indian market are not substantiated by any verifiable evidence.
- v. Third country dumping data is unverifiable, and only positive margin transactions cannot be considered.
- vi. The very first criteria of “likelihood” is not satisfied as the imports of the subject goods is declining. The imports from Saudi Arabia is de minimis (2.67%). Imports of the subject goods have declined.
- vii. The Excess unutilized capacities with Saudi Arabia is alleged to be around 15% which cannot be termed as Significant.
- viii. Subject exporters do not hold much inventory of the goods and sell it to the domestic and/or third country markets, and there is a high capacity utilisation rate.
- ix. The data provided in the petition shows that subject country exporters are oriented towards the third markets.
- x. No evidence has been provided for the argument that producers from Saudi Arabia have easy availability for feedstock as they are backward integrated with the goods. Even if Producers from Saudi Arabia have easy availability of raw materials, it does not imply a surge in imports. In fact, producers of Saudi Arabia have never exported in large quantities.
- xi. Respondent propensity to export cannot be measure by availability of raw material as apart from vertical integration of the manufacturing plant every other raw material is procured on arm length’s basis.
- xii. The estimation of dumping margins, price undercutting and injury margin into third country is neither a requirement nor a practice in the investigation of SSR.
- xiii. SSR investigation has been initiated by China against several countries but not against Saudi Arabia. United States has also initiated AD duty investigations on imports of subject goods from different countries including Saudi Arabia. However, the investigation has been terminated after preliminary determination.
- xiv. **Likelihood of dumping and injury unlikely in post-POI period in light of COVID-19 pandemic.**
  - Post POI analysis is an essential component of likelihood analysis undertaken during sunset review. Authority must consider the likelihood of injury in the future if duty is continued. The period of investigation (POI) in the present review is April 2018 to March 2019. Authority has further considered post-POI period as April 2019 to September 2019 to examine likelihood of recurrence of dumping and injury. However, since the said established post-POI period, lot of developments have taken place in the world market, especially Acetone market, in view of COVID-19 pandemic, which must also be considered while undertaking the likelihood analysis.
  - Since, the end of established post-POI period, entire world, including India, are faced with COVID-19 pandemic. The said pandemic started in December 2019 and cases continues to grow significantly until today.

- Given the large population of India, the demand for hand-sanitizers and disinfectants has increased exponentially and will continue to increase significantly in the future as well. Acetone is a critical raw material for manufacturing Iso-Propyl Alcohol (“IPA”), which are in-turn the key input for disinfectant and hand sanitizers. In fact, during the oral hearing, domestic industry accepted the fact that demand and prices of Acetone have increased during the post POI period during 2020. However, domestic industry also claimed that such increasing trend was a short-term phenomenon.
- The claims of the domestic industry. In this regard are not correct, as explained before, given the nature of COVID-19 pandemic, the demand for hand-sanitizers and disinfectants will continue to grow for a long time and that too consistently as keeping the surroundings as well as hands sanitized regularly is of paramount importance to prevent spread of the virus. Acetone based hand-sanitizers and disinfectants are the most accessible form of sanitizers available for the public at large. The growing demand for Acetone based IPA is corroborated by market reports such as Indian Chemical News, which states as under:

*The COVID-19 pandemic has increased demand for IPA both in India as well as in global market. As per market research, the forecast for global demand of IPA will reach 522,000 TPA during 2020-2024 and half of this growth will come from APAC.*

*As per sources, India’s total demand for IPA is to the tune of 200,000 TPA as there is large IPA demand for sanitizers and this has more than doubled.*

- <sup>1</sup>Even domestic industry constituent – Deepak Phenolics recently started manufacturing acetone-based IPA to cater to the needs to hand-sanitizers<sup>2</sup> and expect the demand of IPA to grow in coming years.
- Given the fact that demand for hand-sanitizers and disinfectants is growing and will continue to grow substantially in future as well, it is natural that demand for Acetone, which is the key raw material is also growing and will continue to grow in future as well. Hence, to even suggest that such increase in demand for hand-sanitizers and in turn demand for Acetone would be short-term has absolutely no merit and must be rejected.
- In addition to increase in demand, there has been a significant increase in prices of Acetone during the post-POI period, especially since the outbreak of COVID-19. As may be observed from table below, prices of Acetone have almost doubled since the POI. Compared to prices prevailing during POI, the world-wide prices indicate the following trend:

YEAR	2018	POI	2019	Apr-20	May-20	Jun-20
				(Last Week)	(Last Week)	(Last Week)
ICIS Price ACETONE bulk	612	533	449	693	958	1,030
Change compared to POI				30%	80%	93%

- Since, the COVID outbreak, Acetone prices have almost doubled during June 2020 compared to POI. The increasing trend is expected to increase even further until the COVID-19 pandemic ends as demand for Acetone based disinfectants would continue to surge. As a result of surge in demand and consequential increase in prices, it is not possible to export Acetone at prices prevailing during POI. The above-mentioned prevailing circumstances clearly indicate that there is no likelihood of recurrence of injury in the future due to imports of Acetone.
- In addition to the fact that demand and prices of Acetone would continue to increase manifold in the future, which reflects that there is no likelihood of dumping in future, it must also be noted that the Indian domestic industry is not self-sufficient to cater to Indian disinfectant/sanitizer demand. Against the domestic demand of 1,99,834 MT during POI, domestic industry had a capacity of only 97,140 MT. Thus, more than half of Indian downstream industries, including disinfectant industries must at all time rely on imported Acetone. Any curb on Acetone imports would be counterproductive to India’s fight against COVID-19 as supply of Acetone and resultant disinfectants would be further reduced.

- Thus, given the growing demand and limited capabilities of domestic producers, coupled with the fact that the prices of Acetone are expected to remain high in future, Respondents submit that there is no likelihood of dumping and injury to domestic industry and continuation of anti-dumping duty would be against the larger Indian public interest. For the said reasons, the existing anti-dumping duty should be terminated.

### **POST DISCLOSURE COMMENTS**

**120. M/s Sumitomo Chemicals Asia Pte Ltd. And M/s Vinmar International Limited,**

**Represented by M/s ELP**

- The examination by Designated Authority in its Disclosure Statement with regard to domestic industry does not provide objective reasons behind its finding that imports were made by the Petitioners for “seed marketing” as it has concluded that over 6% of the total imports during the POI were on account of “seed marketing”, which is larger in volume than imports by some of the subject countries.
- Duty free imports should not be selectively excluded by the Designated Authority when it is convenient to justify the inclusion of the Petitioners as domestic industry and duty free imports should be excluded from the present investigation altogether.
- Alternately, the Petitioners that are found to be importing should be removed from the scope of the domestic industry.
- Petitioners should be directed to correct their claims of excess confidentiality and non-compliance with the confidentiality requirements as specified under Trade Notice no. 10/2018 dated 7 September 2018. In the absence of immediate corrected data being provided to the interested parties, the Hon’ble Designated Authority must observe its obligations under Rule 7 of the AD Rules and reject the data filed by the Petitioners.
- Advance licence imports should not be included as the effect of discontinued or expired duties would only be felt on duty paid imports. Therefore, advance licence imports ought to be excluded altogether from the purview of the present investigation – if duty-free imports are being excluded by the Designated Authority for the domestic industry assessment, then the same standard should be applied impartially and uniformly.
- The existence of a mandatory BIS standard for Acetone is not a bar on the imposition of anti-dumping duty but the BIS Certification requirement and associated costs would result in a substantial decline in imports of the PUC. Accordingly, it would be unfair to exclude the impact of the BIS requirement on the assessment of likelihood. Accordingly, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case duties are allowed to expire.
- With respect to price undercutting, it is relevant to note that economic parameters of the domestic industry like production, capacity utilization, domestic sales, market share in demand, profitability, inventory, employment, waged and productivity have increased during the POI, while undercutting has remained in the same ranges. Therefore, there is an obvious break in the causal link as there is no correlation between alleged price undercutting and economic parameters of the domestic industry.
- The Designated Authority has failed to conduct a comprehensive assessment of the likelihood factors as per the annexure II of AD Rules and precedents. The Designated Authority It appears to have selectively taken into consideration certain factors only ( such as dumping margin in previous investigation, continued imports and export orientation) without providing reasons for the same.
- Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd and Vinmar International Limited were not participants in the original investigations and the Hon’ble Designated Authority cannot rely on dumping margin determined in previous investigations when assessing likelihood of continuation or recurrence of dumping.
- Imports from Saudi Arabia cannot be considered to continue into India at an appreciable volume despite the levy of anti-dumping duties as imports from Petitioners is higher than the total imports made from Saudi Arabia during the POI.
- The Hon’ble Designated Authority appears to have equated all capacities that are not utilized for domestic sales as being “freely disposable”, which is commercially unrealistic and illogical as the producers would most likely have existing markets and commitments in other countries and not all sales for one country are easily transferrable to another market.
- Saudi Arabia being export oriented or having 70 – 80% exports as percentage of its production does not mean that the entire export material from Saudi Arabia is imported or is likely to be imported into India. In fact, India is not at all price-attractive for the exporters as export price of the PUC to third countries is much

higher than that for India. Therefore, other markets are substantially more price attractive than India, whereby even if duties are removed, there is no likelihood of the subject goods being redirected towards India.

- m. An analysis of the likelihood of dumping and injury requires an assessment of whether after the discontinuation of duty there is still a likelihood of dumping or injury that may be faced by the domestic industry. However, in the present case, anti-dumping duties were in place on the subject goods even during the post-POI period and an assessment of the post-POI does not provide a correct analysis of whether the domestic industry is likely to face dumping or injury once the duties are discontinued but, in effect extends the current POI. Therefore, post-POI assessment would be indicative of likelihood only when there are no duties applicable on the subject goods in the post-POI period.
- n. There is no causal link considering the economic parameters of the domestic industry and even during the post-POI period any injury suffered are due to other factors such as Deepak Phenolics being shut down for a period of 14 days.
- o. The COVID-19 pandemic that has emerged after the post- POI period has led to an increase in demand and prices for Acetone due to its usage in the hand-sanitizers. The increased demand is expected to continue in the future as well.
- p. In fact, one of the Petitioners, M/s Deepak Phenolics has recently set up an acetone-based Isopropyl Alcohol (IPA) manufacturing plant, the impact of which the Designated Authority must consider on the demand and supply of the PUC. Accordingly, it is evident that there exists no likelihood of dumping and consequent injury to domestic industry.
- q. Due to the continued increase in demand, the price of PUC has risen significantly in the recent period and the continuation of anti-dumping duty would be against the larger public interest of the country's fight against the COVID-19 pandemic.

#### 121.M/s FCFC, M/s TPCC And M/s LG Chem

##### Represented by WTC

- a. Exports of Acetone from Korea RP have been very low as compared to demand of the India.
- b. There are only two producers of Acetone in Korea RP. In the original anti-dumping total exports from Korea RP were only 4414 MT (4.4% of total demand) and none of the producer/exporter from Korea RP participated in the said investigation.
- c. In the first sunset review investigation, total exports from Korea RP were 8486 MT against (6.06% of total demand). In this sunset review investigation responses of these producers/exporters was rejected due to application of value chain concept.
- d. In both the earlier investigations DGTR worked out dumping/injury margins based on facts available and not the actual data of producers/exporters from Korea RP.
- e. In the present second sunset review investigation, both the producers/exporters from Korea RP have participated and DGTR has worked out negative dumping and injury margin in respect of LG Chem and negative injury margin in respect of the other producer.
- f. India is not a target country for exports and dumping for producers/exporters from Korea RP.
- g. In the post POI data considered by DGTR, it was established that LG Chem has not exported the subject goods to India during post poi period (April 2019 to Sept 2019).
- h. During the POI of the current SSR investigation only a small volume of exports were made by LG Chem, that too only in the first four months of the POI . LG Chem only exported 4 shipments of Acetone to India from April 2019 to June 2020.
- i. Exports of Acetone to India by TPCC had been very low as compared to the demand of the country. During the POI of the sunset review investigation TPCC has exported only \*\*\* MT. No exports to India were made thereafter.
- j. DGTR has worked out negative dumping/injury margin in respect of TPCC and other producer from Taiwan. The above background establishes that India is not a target country for exports by TPCC.
- k. TPCC has submitted that the prices of Acetone sold by TPCC in the current period has increased manifold. The domestic as well as exports sales have reached a record level of US\$ 1000 per/MT. These price levels cannot be termed as dumped and injurious and hence there is no justification for continued imposition of existing duty. In support of the claims



made by TPCC, they have submitted T by T sales data with regard to domestic sales and exports sales for the period Oct 2019 to June 2020.

- l. Exports prices into China PR by various countries as published by ICIS post start of COVID-19 pandemic has increased manifold and reached a peak of US\$ 1046/MT during June 2020.
- m. TPCC and FCFC have provided T by T export price from Taiwan to China can be seen from Export statistics notified by Government of Taiwan.
- n. As per the Disclosure Statement issued by DGTR, the Authority has concluded that in case of FCFC, the goods were exported to India above the non-injurious levels and hence the Injury Margin was determined to be negative.
- o. FCFC has not been regularly exporting the subject goods to India since August, 2018. During the POI of the current SSR investigation only a small volume of exports were made by FCFC. FCFC only exported small quantities of Acetone to India from Oct 2019 to June 2020. FCFC has filed T by T sales data in respect of domestic sales and exports sales for the period Oct 2019 to June 2020 along with sample invoices.
- p. Globally COVID 19 pandemic started from January 2020 and impacted the demand of Acetone as the same is used for manufacturing Isopropyl Alcohol (IPA). The Authority must take the prevailing circumstances into consideration.
- q. IPA is the most commonly used disinfectant in pharmaceutical industries and is also widely used in alcohol wipes, swabs, hand sanitizers, disinfectants and oral mouthwash. COVID-19 pandemic has increased the demand for IPA both in India as well as in global market. As per market research, the forecast for global demand of IPA will reach 5,22,000 TPA during 2020-2024.
- r. Increase in demand and prices of IPA and consequently demand of Acetone has also increased by manifolds. This has resulted in sharp increase in prices of Acetone as compared to any period before, including POI and post-POI (6 months) as considered by the Authority in the current investigation. Indian Chemical News has stated as under:
 

*“We are confident that more and more pharmaceutical products will be made in India, owing to seamless supply of IPA.” The COVID-19 pandemic has increased demand for IPA both in India as well as in global market. As per market research, the forecast for global demand of IPA will reach 522,000 TPA during 2020-2024 and half of this growth will come from APAC.*
- s. As per sources, India's total demand for IPA is to the tune of 200,000 TPA as there is large IPA demand for sanitizers and this has more than doubled.
- t. Demand of Acetone consequent to increase in demand of IPA has increased manifolds and will continue to sustain in future also. Imposition of any anti-dumping duty on Acetone will be counterproductive, as there is already a huge gap existent between demand and supply of Acetone in India. Indian industry only meets 50% of the demand and with further exponential increase in demand due to the outbreak of this pandemic, the gap will further increase.
- u. Exports of to India has almost stopped after commencement of commercial production by Deepak Phenolics.
- v. Major exports of Acetone are being made to China PR and that too at very high prices. There is no possibility of any shift in this behaviour. This trend is likely to continue keeping in view the current pandemic situation around the world.
- w. Immediately after the period of investigation, the prices of Acetone slides downwards globally. This impacted the import prices from all countries.
- x. As per WTO, now onwards the whole world will have to live with COVID-19 and need to take all necessary precautions. Use of sanitizers have become a way of life and hence demand of Acetone will continue to remain at high levels. Demand and prices of Acetone will continue to rise and there is no likelihood of any dumping taking place in future.
- y. The current price levels prevailing in the global market are non-injurious to the domestic industry and there is no likelihood of shifting of exports to India in an event the current anti-dumping duty is withdrawn by the Authority.

- z. The Authority is requested to analyse the books of domestic industry, because at the current prices, the Domestic Industry is making bumper profits and will continue to do so in future also.
- aa. Domestic Industry is unable to meet the demand as is and imposition of anti-dumping duty on ground of likelihood will drive the prices of Acetone off the charts. It is humbly submitted that interests of end-users and the country also need to be taken into thorough consideration as any undue protection to the domestic industry will create a monopolistic market in a situation where the demand of subject goods is only going upwards and so are its prices.
- bb. DGTR should take into consideration the existing situation and likely trends of demand and prices of Acetone while making analysis of likelihood of dumping and injury.
- cc. Impact of COVID-19 pandemic will last for years and it will have major impact on consumption of Acetone resulting from increase of consumption of IPA.
- dd. A short term decline in prices during April 2019 to Sept 2020 shall not be a parameter to judge the likelihood of dumping and injury if existing Anti-dumping Duty is removed.
- ee. During current exceptional circumstances when the whole world is affected by COVID -19, DGTR is requested to examine the likelihood analysis based on the current situation caused due to the pandemic.
- ff. We hope that DGTR will terminate the present investigation and conclude that there is no likelihood of dumping and injury to the domestic industry if the existing Anti-Dumping duty is withdrawn.

#### 122. By Sarvada

**Representing the following:** (1) Kumho P&B Chemicals, (2) Humade Corporation, (3) Unid Global Corporation, (4) Samsung C&T Corporation, (5) IMS Corporation and (6) Canko Marketing Inc.

#### A. Post-POI and likelihood analysis considering the post-COVID-19 situation must be examined.

- a. The demand and prices of Acetone continue to surge post COVID-19 outbreak since Acetone is a key ingredient in manufacturing IPA hand-sanitizers, whose demand has increased exponentially.
- b. When compared to prices of Acetone prevailing during POI, the world-wide prices of Acetone indicate that prices increased by 30%, 80% and 93% during April 2020, May 2020 and June 2020 respectively. The increasing trend is expected to increase even further until the COVID-19 pandemic ends as demand for Acetone based disinfectants would continue to surge. Similarly, KPB's own export prices to India as well as to third-countries during post-POI indicate similar increasing trend compared to the world-wide prices.
- c. Authority has already determined negative injury margin for Respondents during POI. Such being the case, where the prices were significantly higher during post-POI and post-COVID-19 as compared to the POI, the question of likelihood of recurrence of dumping and injury does not arise.

#### B. Negative Injury Margin established for Respondents

- d. Authority has arrived at negative injury margin for the Respondents, which establishes the fact that imports of subject goods produced and exported by Respondents are not injuring the domestic industry in any manner and the domestic industry is well positioned to compete with the imported goods. The sole objective of anti-dumping duty is to curb injurious effects of dumping, which has been achieved in the present case.

#### C. No injury to the domestic industry confirmed by Authority

- e. In the disclosure statement, the Authority has determined the following:
  - i. Increase in domestic industry sales and corresponding decline in imports: Sales of domestic industry increased by 148% between 2017-18 and POI and by 95% between POI and post-POI period. In contrast, during the respective periods, there was a steep decline in imports from subject countries by 14% and 57%. The decline in exports by the Respondents was even steeper by almost 85%, which clearly indicates lack of causal relationship between imports and domestic industry performance.
  - ii. Improvement in production, sales, capacity and utilization of domestic industry: Authority has confirmed that domestic industry has not suffered any injury and its volume parameters has shown significant increase during the POI. Post-POI figures also indicate robust growth, which indicates that domestic industry is not likely to suffer any adverse injury in the future.

- iii. No price suppression or depression: Apart from determining negative injury margin for Respondents, Authority has also determined that during the POI, imports from subject countries are not depressing or suppressing the prices of the domestic industry.
- iv. Significant improvement in DI's market share, profitability, employment, wages and productivity.
- v. Ability to raise capital investment: Authority has clearly stated that domestic industry has not presented any information which suggests that future investment in the sector can be marred by the presence of dumped imports from subject countries. This indicates that the domestic industry is healthy and will be able to perform well in the future as well.

**D. No likelihood or recurrence of dumping and injury in respect of Respondents**

- f. There is no likelihood of recurrence of dumping and injury insofar it relates to Respondents for the following reasons:
  - i. Past dumping margin determinations irrelevant: The market dynamics as existing during the original investigation and first sunset review have significantly changed over the past 12 years. Thus, mere comparison of dumping margins existing in 2008 or 2014 and comparing the same with dumping margins in 2020 will not lead to a proper comparison.
  - ii. In sunset review concerning imports of '4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA)' from the China PR and sunset review concerning imports of "Melamine" from European Union, Iran, Indonesia and Japan, Authority recommended withdrawal of anti-dumping duties, though it determined positive dumping margin. Facts of the present case are similar or even stronger with respect to withdrawal of anti-dumping duty.
  - iii. Significant decline in exports to India by Respondents: There is no appreciable increase in import volumes. Actual exports to India data of the Respondents indicate that exports declined by 31% between 2018 and POI; by 85% between POI and post-POI period and by 90% between 2018 and post-POI period. Such being the case, it is inconceivable to even suggest that imports are continuing at appreciable volumes.
  - iv. No export orientation: Mere export orientation in itself is insufficient to conclude that there exists likelihood of recurrence of dumping and injury. Respondents' as-filed data indicates that Respondents' total export to India out of its total exports as well as in relation to its production was very insignificant as exports to India has almost stopped since POI. This indicates lack of export orientation.
  - v. No trade diversion: Firstly, domestic industry has offered no evidence to suggest that trade diversion is likely. Secondly, negative injury margin has been determined by Authority for the Respondents. Thus, even if anti-dumping duties are discontinued, the 3<sup>rd</sup> country exports would enter Indian market at a non-injurious level. Resultantly, the likelihood of recurrence of injury does not arise.
  - vi. India not a lucrative market for Respondents: India is not a lucrative market for the Respondents since exports to India by Respondents has almost entirely stopped.
  - vii. No freely disposable capacity with Respondents: At the outset, mere existence of capacities in subject countries do not ipso-facto result in increased exports to India. In fact, data submitted by the Respondents indicates that Respondents are already operating above optimal capacity utilization. Thus, the question of unutilized or freely disposable capacity does not arise.
  - viii. No plans for expansion: There are no basis for domestic industry's claim that Respondents have plans for expansion. No concrete evidence has been provided in this regard. The said claim of domestic industry is factually incorrect.
  - ix. Post-POI performance of domestic industry: Analysis of post-POI economic parameters of domestic industry indicates significant & continuous improvement in its performance. The fact that over the past three years, domestic industry has been performing well is a clear indicator of the fact that imports from subject countries are no longer a threat to the domestic industry.
  - x. DA is requested to terminate anti-dumping duty against the Respondents.
  - xi. Determination of injury margin establishes the fact that imports of subject goods produced and exported by Respondents are not injuring the domestic industry in any manner and the domestic industry is well positioned to compete with the imported goods. In fact, domestic industry has been able to sell the like article at a much higher price compared to imported subject goods and make healthy profits at the same time.
  - xii. Respondents pray for immediate termination of the present sunset review investigation.

**123.SUBMISSIONS ON BEHALF OF SABIC AND PETRO RABIGH by LKS****A. Domestic Industry**

- i. It is submitted that SI Group and Deepak Phenolics have imported the subject goods into India in significant quantities. The imports made by the Domestic Industry constitute approximately 15% of the total subject imports, which are being claimed as 'insignificant' by the Domestic Industry. Saudi Arabia's share in imports is lesser than 3%, and should not be considered significant.
- ii. Additionally, HOCL is a sick unit and is under a restructuring process. It cannot be considered a viable domestic producer for the purposes of this investigation.
- iii. It is clear that there exist no viable domestic producers in India to constitute a domestic industry within the meaning of Rule 2(d) of the AD Rules. On such grounds, the current investigation should be terminated.
- iv. If the Authority exercises its discretion to continue the investigation, the imports made by the Domestic Industry must be excluded from the total subject imports for the purposes of analysis in this investigation.

**B. Confidentiality**

- v. No excessive confidentiality has been claimed by the Respondents. The submissions duly comply with the requirements of Trade Notice 10/2018.
- vi. In the "Trade Notice Status- Sunset Review Investigations in the matter of imports of Acetone from Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan" section of the Petition, the Petitioners have considered the Single Producer/Two Producer standard instead of the "More than Two Producers" standard from the Trade Notice.
- vii. In the following standards, the Domestic Industry has failed to provide the required information in the prescribed manner:
  - a. Sales Quantity
  - b. Cost of Sales per Unit- Exports
  - c. PBIT per Unit- Domestic Sales
  - d. Total PBIT- Domestic Sales
  - e. Calculation of NIP

**C. Cumulation of Imports**

- viii. Saudi Arabia accounts for 2.67% of the imports in the POI, 0.71% in 2017-18 and there are no imports from Saudi Arabia in the previous years. Imports from Saudi Arabia are de-minimis and should be assessed separately.

**D. Normal Value, Export Price and Dumping Margin**

- ix. The Petition does not contain any evidentiary data with regard to the adjustments. The Applicants have failed to provide any explanation as to why the charges have been pegged at such a high level. This has unfairly lowered the export price determined.
- x. The valuation of raw material should be done on the basis of the actual data in the exporter's questionnaire response submitted by it to the Authority as done in the original investigation.

**E. Injury**

- xi. Volume of the subject imports has declined substantially in both absolute terms and relative to production and consumption.
- xii. Saudi Arabia's imports are insignificant and have a share of 2.67% in the total imports.
- xiii. Petitioners have increased their installed capacity for production of the subject goods with the installation of a plant by Deepak Phenolics in 2018.
- xiv. The capacity utilization of the domestic industry in the POI is at 89%, which is significantly high and is the highest in the last four years.
- xv. The domestic industry has been able to substantially increase its capacity utilization in the POI vis-à-vis the previous year despite having doubled its capacity in the POI. In case of Deepak Phenolics, the producer has been able to achieve capacity utilization of 100% in Q4 of FY 2018-19.
- xvi. The Petitioners' production of the subject goods has increased from 24,959 MT in 2015-16 to 86,112 MT, i.e. by 245% in the POI.

- xvii. The domestic sales of the Petitioners have increased commensurate to increased production over the period of injury. The Petitioners' domestic sales have also increased threefold in the POI.
- xviii. The Total PBIT increased from a loss of INR 1,565 lakhs in 2015-16 to a profit of INR 1,352 lakhs in the POI.
- xix. The cost of sales as well as the selling price has declined but the decline in selling price is less than the decline in cost of sales, which has resulted in a higher profit margin.
- xx. Despite the increase in capital employed, the domestic industry's return on capital employed has increased in the POI after being negative in the previous year (2017-18)
- xxi. The number of employees has increased from 119 to 352 over the period of injury, commensurate with increased capacity.
- xxii. The massive increase in productivity per day from 71 MT/Day to 246 MT/DAY indicates better efficiencies.

#### F. Likelihood of Injury

- xxiii. Based on the observed pricing trends, it appears that the pricing policy of the subject countries does not affect the pricing policy of the petitioners.
- xxiv. The landed value of all the imports, without the addition of the ADD has been rising consistently.
- xxv. The unutilized capacity in Saudi Arabia is only around 15%, which is 43,500 MT. Respondents do not hold much inventory of the subject goods, but rather sell the same in the domestic market and / or third country export markets.
- xxvi. The Petitioners have not provided any post POI data to indicate the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, even though data of the post POI 6 months could easily have been supplied.
- xxvii. Producers from the subject countries have established third country markets such as in Europe and therefore, there is no evidence to presume that such sales would be redirected to the Indian market or that there will be a surge in exports to India upon revocation of ADD.
- xxviii. The Petitioners have claimed that there is an increase in the capacity of Saudi Kayan by 37% over the injury period. However, this is not true, since there has been no increase in capacity at all.
- xxix. They have claimed that inventories with the company have increased. It must be noted that inventory as percentage of production has decreased, and that is the relevant factor which must be analyzed.
- xxx. The imports from Saudi Arabia have always been meagre. Despite its export orientation claimed by the domestic industry, it barely makes any exports to India. Anti-dumping duty was imposed on Acetone imported from Saudi Arabia in 2015. Saudi Arabia has been exporting only small quantities of Acetone to India for the past decade, irrespective of the duty imposed on them.
- xxxi. With 5 years of duty enforcement, the trade channels have been realigned and there is no reason to presume that the producers and exporters in Saudi Arabia including the Respondents would revise their trade routes to create a sudden surge in exports to India upon revocation of duties.
- xxxii. Easy availability of raw material through backward integration does not imply a rise in imports into India. Considering the argument, the producers in Saudi Arabia have always had backward integration but have never exported in large quantities to India. Their landed price has also always been at the higher end.
- xxxiii. In the injury period, the dumping margin, injury margin, and price undercutting caused by the imports from Saudi Arabia to third countries has been negative
- xxxiv. Estimation of dumping margins, price undercutting and injury margin in third countries is neither a requirement nor a practice for the Authority in the conduct of sunset review investigations.
- xxxv. No investigation has been initiated by China against Saudi Arabia.
- xxxvi. The International Trade Commission of United States has terminated the antidumping duty investigation on acetone from Saudi Arabia due to low imports.

#### G. Causal Link

- xxxvii. As per an Investor Communication dated 24 October 2019, for Quarter 2, 2019-20, Deepak Phenolics stated that any injury caused to the company is due to several other reasons not related to imports from Saudi Arabia:
  - a. Slowing economic growth globally

- b. Subdued activity levels in the automotive and real estate sector
- c. Planned shutdown of the plant for 14 days during the quarter

xxxviii. HOCL is a sick unit and have been facing operational difficulties with its Acetone manufacturing units.

xxxix. Volume of imports from other countries combined is significantly higher than the volume of imports from the subject countries, especially Saudi Arabia.

#### H. Miscellaneous

- xl. The Authority has conducted more than 10 (ten) trade remedy investigations on the subject goods imported from various countries in the past two decades (1999-2019).
- xli. Even though production of Acetone by the domestic industry has increased in the POI vis-à-vis the previous year, it is grossly insufficient to meet the increasing demand.
- xlii. Contradictory to the claim of the domestic industry, there are no other indications of the role of SABIC in the channel of distribution. There is a clear flowchart provided in the Questionnaire Responses, and the same can be verified by the Authority.

#### 124. **Brief of Domestic Industry Comments**

- i. Higher Demand for Acetone than capacities only justify imports, and not dumping.
- ii. Due to inevitable imports, DI has to disregard its cost price and raw material costs and set its selling prices as per the dumped prices offered by foreign exporters.
- iii. CESTAT held in DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority, that demand-supply gap does not warrant exporters dumping goods. If fulfilling the demand is the purpose, then exports can be made at a price equivalent to the normal value.
- iv. The Authority as practice, has never considered demand supply issue relevant in the previous findings when the other factors have established that there is likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. ADD has been recommended at even higher Demand supply gaps.
- v. Any data or information beyond the post POI period cannot be considered. COVID 19 situation is only temporary. Any decision on imposition of ADD cannot be based on a temporary situation.
- vi. The Authority as practice, in previous investigations, including Phenol, has confined the post poi period to be 6 months after the POI. Point 17.30 of the SOP manual also states 6 months subsequent to POI as the post POI period.
- vii. As submitted previously, sanitizers have been removed from the list of essential items by the Government and therefore the acetone-based IPA is no more an essential item.
- viii. Since DI is not suffering injury in the present investigation, the case is required to be decided on the basis of likelihood/threat examination. It is not appropriate to modify the duty in such an event.
- ix. The injury margin is relevant only when the Designated Authority finds that the domestic industry is currently suffering injury. As a practice, the Authority extends the same quantum of duty on grounds of likelihood of recurrence of injury. The same has been re-affirmed by the Gujarat High Court in Nirma Ltd. v. Union of India.
- x. As per Rule 17(2), the question of quantum of injury shall arise only when the Designated Authority finds injury to the domestic industry.
- xi. If the Designated Authority does not find injury to the domestic industry, the Designated Authority is not required to determine injury margin. In fact, when there is no injury, there can be no need for determining injury margin.
- xii. As noted in the Disclosure Statement, there is a likelihood that cessation of duty would lead to dumping and injury to the domestic industry. It can be seen that –Dumping margin is the current investigation as well as the previous investigations were positive and above de minimus levels.
- xiii. Imports from subject countries have continued in substantial volumes despite anti-dumping duty in existence.
- xiv. The responding exporters are highly export oriented, as per the data filed by the responding producers, their exports to India are at dumped prices and at injurious prices during period of investigation or Post period of investigation, further the exports to 3rd countries other than India during Post POI on likely diversion to India would be injurious.

- xv. Additional disclosure of relevant documents is requested to enable DI to come to a meaningful conclusion, non-confidential version of supplementary information, if any, filed by foreign producers, non-confidential version of deficiencies issued to foreign producers, if any, may be provided. Copy of communications sent by the Authority and copy the replies filed by the interested parties, Copy of rejoinder submissions, a non-confidential version of verification report may also be provided.
- xvi. The period for which duty has been in force is no relevant consideration to determine whether further extension is required. Authorities in multiple jurisdictions have extended ADD beyond 20 years.
- xvii. The Domestic Industry has provided post POI data in compliance with the Trade Notice No 1/2013.
- xviii. The initiation notification is as per the established practice of DGTR. The petition contains all the necessary information, a copy of which has been provided to all the known exporters and respective Embassies.
- xix. The opposing interested parties have not established any prejudice caused to them due to lack of alleged information in the notice of initiation, when the notice of initiation is required to be read along with the petition.
- xx. It would be grossly inappropriate to consider turnover of relevant day/week/month/quarter/year to determine their position over the injury period. If the effect of dumped import on the domestic industry is required to be assessed, the effect of other product performance is required to be segregated.
- xxi. As per the past practice of the Authority, including in Acetone and Phenol investigations, even where the Dumping Margin and Injury Margin has found to be negative, the Authority has extended the same duty on the basis of likelihood of recurrence of injury.
- xxii. As per the practice of Authority, the duty should be imposed in terms of USD (\$). Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US\$. The depreciation of INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.

#### **Examination by Authority**

125. The Authority had disclosed dumping margin and injury margin during POI and Post POI in the disclosure statement to all concerned producers/exporters. The comments received from various interested parties in response to the Disclosure have been appropriately examined. As regards imports by domestic industry of the subject goods during POI, the Authority notes the submissions of various interested parties on the imports made by M/s Deepak Phenolics Ltd and M/s SI Group India Pvt. Ltd were 2% of total imports. M/s Deepak Phenolics Ltd. imported the same for seed marketing purpose. The Authority in the foregoing paras quantum of dumping and injury to the domestic industry during POI holds that after assessing the POI analysis does not support continuance of existing ADD but SSR warrants a likelihood analysis of dumping and injury which thereby requires an analysis in post POI period as well. The Authority has undertaken a post POI analysis of likelihood of dumping and injury as done consistently in similar circumstances. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules as follows:

#### **a. Dumping margin determined in previous investigations**

Authority notes that the original investigations into the import of subject goods, and the subsequent reviews brought out the existence of significant dumping as follows:

Nature of Investigation	Dumping Margin ( % )	Subject Country
Original Investigation	32.77%	Korea RP
Sunset Review Investigation	15-25%	
Original Investigation	5-45%	Saudi Arabia and Taiwan

The Authority notes that in POI, dumping margin is above de minimis for 4 cooperative producers/exporters i.e. SABIC, TPCC, FCFC and Kumho. The Authority has examined likelihood of dumping during the post POI period especially for those producers/exporters for whom the dumping is below de minimis in the POI.

#### **b. Continued imports of appreciable quantum in presence of anti-dumping duty**

Imports have though reduced but continue into India at appreciable volume despite the levy of Anti-dumping duties which have been considered for likelihood examination of dumping and also injury as stated in later paras.

**c. Export orientation of subject countries**

The Authority noting the claim made by domestic industry in the foregoing paragraphs on surplus capacity and high export orientation. As per the data filed by the cooperative producers/exporters, the export orientation of producers/exporters in the 3 subject countries is observed as under, which broadly correlated with the claim of the DI.

Country	Exports as percentage of production
South Korea	30-40
Taiwan	40-50
Saudi Arabia	70-80

The Authority notes that some interested parties have stated that merely with a surplus capacity, the subject country may not be targeting India. The Authority holds that if that is the case with the participating producers/exporters the continuance of AD duty may not impact their business model of exporting to countries other than India. However, there could be other producers/exporters who may look at India for exports and hence the continuance of AD duty after the likelihood analysis may be required.

**d. Likelihood analysis on Dumping and Injury**

The Authority notes that in the current SSR, the cooperative producers/exporters from the subject countries account for almost 83% of imports of PUC into India during POI. The cooperative producers/exporters have also provided post POI data as requested. Keeping in view the high degree of participation, the exports of subject goods during post POI from the subject countries to India are quite representative and have been analysed for likelihood of dumping or injury as warranted and considered appropriate.

The Authority has referred the post POI data of 6 months of producers/exporters to evaluate the likelihood of dumping or injury. The methodology of analysis of this data adopted is as under;

- a. Dumping Margin and Injury Margin have been evaluated for exports to India during Post POI after these were found to be negative/deminimis during POI as the case may be.
- b. (i) If there are no exports to India during Post POI or if DM/IM is also deminimis/negative in Post POI for India, dumping margin has been evaluated for exports to 3rd countries other than India and  
(ii) Injury during Post POI has been evaluated considering likely diversion of exports made by cooperative producer/exporter to 3rd countries to India if the Indian market is found to be attractive by the producers/exporters due to likely realisation of higher price.

By applying the aforesaid methodology the following is held;

**Saudi Arabia**

1. M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) - The exports from SABIC continue to be dumped and injurious during POI, as is evidenced from the dumping and injury table in the foregoing paras.
2. M/s Rabigh Refining and Petrochemical Company (Rabigh) - The exports by Rabigh to India during Post POI are noted to be dumped and injurious.
3. The Authority also notes the comments of producers/exporters from Saudi Arabia that their exports have been very insignificant. The Authority holds that the continuance of anti-dumping duty is on the basis of a likelihood analysis on various parameters as stated in this finding. If the cooperative producers/exporters are not inclined to export to India, the continuance of anti-dumping duty would not impact them but for the other non cooperative producers/exporters, there is a need to ensure protection on a likely dumping and consequential injury to the domestic industry.

**Taiwan**

1. M/s Taiwan Prosperity Chemical Corporation (TPCC) – The exports by TPCC during POI are noted to be dumped as depicted in dumping table in foregoing para, The 3<sup>rd</sup> countries exports during post POI on likely diversion to India are noted to be injurious.
2. M/s Formosa Chemicals & Fibre Corporation (FCFC) – While the exports by FCFC to India in POI are noted to be dumped, the likely diversion of FCFC's exports from 3<sup>rd</sup> countries (other than India) to India during Post POI are observed to be injurious.



**South Korea**

1. M/s LG Chem, Ltd (LG) – The exports of LG during POI are noted to be non-dumped and non-injurious. During Post POI, there are no exports to India, however exports to 3<sup>rd</sup> countries other than India are noted to be dumped and their likely diversion to India indicates that they would be injurious.
2. M/s Kumho P&B Chemicals (Kumho) – The exports by M/s Kumho to India are noted to be dumped during POI and the exports to 3<sup>rd</sup> countries other than India during Post POI on likely diversion to India would be injurious.

The Authority holds that there is likelihood of dumping and injury in view of the aforesaid analysis. Authority notes the submission by Kumho regarding error in the confidential calculations which is further re-examined and corrected appropriately.

The treatment accorded to the cooperative producers/exporters for continuance of AD duty is also applicable to the non-cooperative producers/exporters. The Authority recommended continuance of the earlier AD duty as imposed on them as per previous investigation at the later paras of this finding.

**Causal Link**

126. The imports are noted to be undercutting the prices of the Domestic Industry and have a depressing effect. Also, due to the price effects, the petitioners are suffering financial losses.

Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. The other parameters listed under the AD Rules which could contribute to injury to the domestic industry are noted as follows and have been evaluated as demonstrated below;

- a. Third Country: The imports from third country are either attracting anti-dumping duty or under ADD investigation are at higher prices.
  - b. Demand: The demand of the product under consideration has increased since the base year.
  - c. Export Performance – The domestic industry has exported the product under consideration in negligible volumes. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a cause of injury to the domestic industry.
  - d. Technology – The technology as also the production process for producing product under consideration has not undergone any significant development. Possible development in technology is not a cause of injury to the domestic industry.
  - e. Performance of other products of the company – Performance of other products being produced and sold by the Petitioners is not a possible cause of injury to the Domestic Industry. The information relating to the product under consideration which is the relevant information for the present purpose has been considered in all the injury parameters.
  - f. Conditions of competition and Trade Restrictive Practices – There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry
  - g. Changes in the patterns of consumption – There have been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration during POI.
127. The Authority notes that many interested parties have mentioned that the domestic industry's profitability on the basis of current prices has improved which does not warrant continuance of anti-dumping duty. The Authority further notes that various interested parties have also mentioned that prices of Acetone have increased significantly in early 2020 on account of Covid Pandemic as this is an input for making sanitisers, and therefore, continuance of AD duty is not warranted on this product. The Authority notes that prices of acetone ranged between 600\$/MT to 1000\$/MT during first quarter of 2020 and later in May to June 2020 are on an average range of 800 \$/MT. The post POI considered is 1/4/2019 to 30/9/2019 i.e. 6 months as normally considered. However, in few cases which required examination of developments beyond 6 months, Post POI of more than 6 months has also been considered. In the instant case as the circumstances warrant examination of the current facts also keeping in view the continuing pandemic, the Authority has obtained the recent import data also as stated above. The Authority notes that the prices of Acetone are still ranging high and keeping in view the ongoing situation and the views of interested parties on the domestic industry making profits, it is considered appropriate to recommend a price triggering mechanism so that AD duty is invoked only when the price of import is lower than the established trigger price. The Authority further notes that in the instant case it is the likelihood of continuance of dumping and injury which have been established in the foregoing paras. The Authority also notes that in the earlier investigation of the subject countries, the AD duty was referenced as per the injury margin and in the current

scenario an appropriate trigger point needs to be referenced keeping in view the current prices and a price which would not be injurious to the domestic industry for which the NIP has been evaluated during POI. Further, the price which would not be injurious in current time is considered appropriate and realistic to set up a trigger price, since, the composition of the DI has significantly changed in the current SSR as compared to the earlier investigations. The Authority therefore recommends a trigger price as 508 \$/MT (CIF). AD duty would be liable to be paid if the CIF import price of the subject goods from the subject countries is below 508 \$/MT.

128. The Authority notes that in case of imports from South Korea, the present case is second SSR. The Authority notes that investigation includes 2<sup>nd</sup> SSR on imports from South Korea while for Saudi Arabia and Taiwan it is the first SSR. Keeping in view the likelihood of dumping and injury the Authority recommends extension of the existing ADD on imports of subject goods from Saudi Arabia, Taiwan and South Korea as notified vide C.N. No. 05/2015-Customs (ADD) dated 18/2/2015 and C.N No. 13/2015-Customs (ADD) dated 16/4/2015. Subject to above mentioned (para 132) price triggering mechanism.

129. In view of the aforesaid, the Authority recommends imposition of definitive Anti-Dumping Duties on the import of the Subject Goods, originating in or exported from the subject country in Col (7) of the duty table below for a further period of 5 years from the date of Notification to be issued in this regard by the central government substituting existing custom Notification No. 07/2020-Customs (ADD) dated 15/4/2020.

**Duty Table**

S. No	Heading /Sub-heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount*	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2914 11 00	Acetone	Taiwan	Any	Formosa Chemicals and Fibre Corp.	86.10	USD	MT
2	-do-	-do-	Taiwan	Any	Taiwan Prosperity Chemical Corporation	205.05	USD	MT
3	-do-	-do-	Taiwan	Any	Any other than at Sl. No 1 and 2 above	271.37	USD	MT
4	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Taiwan	Any	271.37	USD	MT
5	-do-	-do-	Korea RP	Any	Kumho P&B Chemicals Inc	79.75	USD	MT
6	-do-	-do-	Korea RP	Any	LG Chem, Ltd.	79.75	USD	MT
7	-do-	-do-	Korea RP	Any	Any other than at Sl. No 5 and 6 above	79.75	USD	MT
8	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Korea RP	Any	79.75	USD	MT
9	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any	Saudi Kayan Petrochemical Company	132.98	USD	MT
10	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any	Rabigh Refining and Petrochemical Company	203.85	USD	MT
11	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any	Any other than at Sl. No 9 and 10 above	203.85	USD	MT
12	-do-	-do-	Any country other than country attracting anti-dumping duty	Saudi Arabia	Any	203.85	USD	MT

\* The aforesaid AD duty would be levied only when CIF price of import is below 508 USD/MT.

**Further Procedure**

130. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority